LK ACADEMY
YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

# करेंट अफेयर्स

## सितंबर 2026

### सिविल सेवा परीक्षा हेतु



सितंबर 2026 संस्करण | सिविल सेवा परीक्षा हेतु | ₹120

lkacademy.org | 7285043606

# UPSC CURRENT AFFAIRS — सितंबर 2026

## 1. भारतीय राजव्यवस्था (POLITY & GOVERNANCE)


850-सीट लोकसभा : अधिक सांसद, चर्चा पर प्रभाव (परिसीमन) ..... 1
भारत में क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता; संघवाद के स्तंभ के रूप में क्षेत्रीय दल ..... 2–3
संसद में विधायी चर्चा और संवाद की आवश्यकता (मानसून सत्र) ..... 3–4
विरोध करने का अधिकार (अनु. 19, प्रमुख SC निर्णय) ..... 4–5
न्यायिक पारदर्शिता सूचकांक रिपोर्ट (JALDI) एवं कॉलेजियम प्रणाली ..... 5–7
अधीनस्थ विधान समिति की 257वीं रिपोर्ट (CCI विनियम) ..... 7–8
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 (वंदे मातरम्) ..... 8
डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश ..... 8–9
केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 — 'केरलम्' ..... 9
फास्ट-ट्रैक न्यायालय और शीघ्र न्याय का वादा ..... 63–64
राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026) ..... 65–66
लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 व परीक्षा प्रणाली सुधार ..... 67–69
चुनावी काले धन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश ..... 71


## 2. अर्थव्यवस्था (ECONOMY)


हथकरघा : भारत की विरासत को वैश्विक विकास से जोड़ना ..... 35
MSME का क्लस्टर-आधारित विकास; जलवायु-लचीले MSME क्लस्टर ..... 36–37
भारत के माल निर्यात में वृद्धि का विश्लेषण ..... 37
प्रतिभूति बाज़ार संहिता विधेयक, 2025 (SEBI) ..... 38
विकास के इंजन के रूप में शहर (FICCI–EY रिपोर्ट) ..... 39–40
कोर उद्योग सूचकांक : नई 2022-23 आधार शृंखला ..... 40
मत्स्य पालन सब्सिडी पर WTO समझौता ..... 40–41
निफ्टी 500 अहिंसा सूचकांक ..... 41
निर्यात हेतु इन्वेंट्री-आधारित ई-कॉमर्स में 100% FDI ..... 41
भारत में व्यापार सुगमता (EoDB) — संसदीय समिति रिपोर्ट ..... 41–42
फ्लोटिंग-रेट लोन (RBI निर्देश, 2026) ..... 42
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के दस वर्ष ..... 64–65
खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 ..... 71


## 3. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS)


भारत की विदेश नीति में समुद्र-आधारित दृष्टिकोण (भारतीय नाविकों की सुरक्षा) ..... 55–56
नाटो : रणनीतिक परिवर्तन का नया युग एवं भारत के लिए निहितार्थ ..... 56–57
मक्का समझौता : सऊदी अरब–तुर्की–पाकिस्तान सुरक्षा त्रिकोण ..... 57–58
राष्ट्रपति की मोल्डोवा और उत्तरी मैसेडोनिया यात्रा ..... 58–60
क्वाड द्वारा आसियान की केंद्रीयता का समर्थन (AOIP) ..... 60–61



IAS ACADEMY
YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

अमेरिका–सऊदी अरब नागरिक परमाणु सहयोग समझौता (123 समझौता) ..... 62
बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा गठबंधन (बाब अल-मंडेब, लाल सागर) ..... 62
दक्षिण चीन सागर विवाद (स्कारबोरो शोल) ..... 62

## 4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (ENVIRONMENT & ECOLOGY)

सर्वोच्च न्यायालय और पर्यावरण कानून / न्यायशास्त्र ..... 26–27
वृक्षों के लिए वनों का विनाश (ग्रीन इंडिया मिशन, वृक्षारोपण) ..... 27
ब्रिक्स जलवायु सहयोग : 'पीपल एंड प्लैनेट फर्स्ट' ..... 28
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) ढाँचे में संशोधन ..... 29–31
नो ट्रांज़िशन विदाउट जस्टिस रिपोर्ट (UNEP) ..... 32–33
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI), 2026 ..... 33
ग्लो झील (अरुणाचल प्रदेश) : भारत का 101वाँ रामसर स्थल ..... 33–34
आर्द्रभूमि अभयारण्य के आसपास खनन पर प्रतिबंध (आसन आर्द्रभूमि) ..... 34
थामिरबरानी नदी (मद्रास HC निर्णय) ..... 34

**चर्चित प्रजातियाँ :**

एलोग्राफा (लाइकेन की नई प्रजातियाँ, पश्चिमी घाट) ..... 74
व्हाइट-बेलिड हेरॉन ..... 74–75
पिग्मी हॉग ..... 75
लेपिडोप्टेरा (तितलियों व पतंगों की पहली व्यापक सूची) ..... 75–76
क्लाउडेड लेपर्ड ..... 76
एशियाई जंगली जल भैंस ..... 76
स्लेंडर-बिल्ड वल्चर ..... 77
ब्लैक-नेक्ड क्रेन ..... 77
ब्लैकबक (बन्नी घास मैदान में पुनर्स्थापन) ..... 78

## 5. भूगोल (GEOGRAPHY)

फ्लैश फ्लड (अचानक बाढ़) : कारण, प्रभाव एवं अनुकूलन ..... 31–32

**चर्चित स्थल :**

सिगुर हाथी गलियारा; काला सागर; सेउटा एन्क्लेव; लेक मीड ..... 72
रब-अल-खाली (एम्प्टी क्वार्टर); कुरिल द्वीप समूह; हारा मैंग्रोव्स; बन्नी घास के मैदान ..... 73

## 6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE & TECHNOLOGY)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृषि : आंध्र प्रदेश के लिए अवसर (एग्रीवोल्टिक्स) ..... 10–11
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा; AI-सक्षम साइबर युद्ध हेतु तैयारी ..... 11–12
धोखाधड़ी को रोकना ('स्टॉप द स्कैम') — साइबर अपराध प्रवर्तन ..... 12–13
अगली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के रूप में AI ..... 13–15
मेडिकल टेक्नोलॉजी में AI (स्वास्थ्य में AI हेतु WHO के सिद्धांत) ..... 15–17
बोरोफेन-आधारित हरित स्नेहक ..... 17
ग्लूबॉल और X(2370) कण ..... 17–18
फाल्कन 9 (चंद्रमा पर प्रभाव, स्पेसएक्स) ..... 18–19

LKACADEMY
YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

एवरेस्ट रॉकेट इंजन (LOX-मीथेन) ..... 19
क्यूडेंगा (TAK-003) डेंगू वैक्सीन ..... 20–21
चाँदीपुरा वायरस ..... 21
लेप्टोस्पाइरोसिस ..... 21–22
रेगन एवं प्रोटीन भाषा मॉडल ..... 22
नॉन-मेंडेलियन एपिजेनेटिक वंशागति ..... 22–23
बिटचैट टेकडाउन (I4C, GitHub) ..... 23
व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) संचार ..... 23–24
जिंक-एयर बैटरी के लिए नैनोफ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट ..... 24
एग्री-फोटोवोल्टिक्स ..... 24–25
मॉडिफाइड मिक्स्ड सील सरफेसिंग प्लस (MSS+) सड़क प्रौद्योगिकी ..... 25

## 7. रक्षा एवं सुरक्षा (DEFENCE & SECURITY)

आईएनएस मालवन (ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट) ..... 19–20
कुशा मिसाइल (प्रोजेक्ट कुशा, LR-SAM) ..... 20
अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल ..... 20
ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस (CMF) ..... 78
भारत-अमेरिका विस्फोटक आयुध निपटान (EOD) अभ्यास ..... 78
अभ्यास मैत्री-XV (भारत–थाईलैंड) ..... 78

## 8. सामाजिक मुद्दे (SOCIETY)

यौन कार्य पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विश्लेषण ..... 43–44
लिव-इन पार्टनर्स के लिए सुरक्षा उपाय ..... 44
उपभोक्ता संरक्षण एवं सरोगेट विज्ञापन ..... 45
बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ..... 46–47
युवा वैश्विक रोजगार प्रवृत्ति, 2026 (ILO रिपोर्ट) ..... 47–49
विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति (SOFI), 2026 ..... 49
नूतन सकला — ओडिशा की मानव तस्करी-रोधी नीति ..... 49–50
देखभाल की पुनर्कल्पना : केयरगिवर्स को सशक्त बनाना (नीति आयोग) ..... 50
भारत में साइबर अपराध पर संसदीय समिति की रिपोर्ट ..... 50–51

## 9. इतिहास एवं संस्कृति (HISTORY & CULTURE)

धिमसा नृत्य (गिनीज रिकॉर्ड) ..... 52
नीरागुंडा वीरगल्लू शिलालेख (होयसल) ..... 52–53
वाग्देवी की मूर्ति (भोजशाला, धार) ..... 53
वैश्य टेकरी टीला (उज्जैन, मौर्यकालीन स्तूप) ..... 53–54
वंदे मातरम् (लाल किले पर पहली बार गायन) ..... 54
चर्चित व्यक्तित्व : चंद्रशेखर आजाद; रवीन्द्रनाथ टैगोर ..... 74

LK ACADEMY
YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

## 10. सरकारी योजनाएँ एवं नीतियाँ (GOVERNMENT SCHEMES & POLICY)


सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का आधुनिकीकरण ..... 66–67
समुद्र मंथन : राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना ..... 69
गोबरधन राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना ..... 69–70
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) (संशोधन) विधेयक, 2026 ..... 70
वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड पहल (आयुष) ..... 70–71



LK ACADEMY
YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

# भारतीय राजव्यवस्था



## संपादकीय

### लोकसभा में अधिक सांसद से चर्चा पर प्रभाव

'ऐन 850-सीट लोक सभा मीन्स मोर एमपीज, लेस पार्लियामेंट' (An 850-seat Lok Sabha means more MPs, less Parliament) शीर्षक वाला यह संपादकीय 30 जुलाई 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे अत्यधिक बड़ी लोकसभा विधायी विचार-विमर्श, जाँच और कार्यकारी जवाबदेही को कमजोर कर सकती है।

### लोकसभा के विस्तार के जोखिम

- प्रस्तावित परिसीमन से लोकसभा की सीटें 1972 में तय की गई 543 सीटों से बढ़कर 824-850 हो सकती हैं, लेकिन संख्यात्मक प्रतिनिधित्व से संघीय तनाव और संस्थागत कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है।
- एक सीमा से अधिक होने पर बड़ी विधायिकाएँ अव्यावहारिक हो जाती हैं; अमेरिका में आबादी 120 मिलियन से बढ़कर 335 मिलियन से ज़्यादा होने के बावजूद 1929 से हाउस की सीटें 435 पर ही सीमित हैं।

### विचार-विमर्श पर प्रभाव

- प्रश्नकाल या बहस के लिए सीमित समय होने के कारण 850 सदस्यों में से केवल 15-20 सदस्य ही भाग ले सकते हैं, जिससे पीछे की बेंचों पर बैठे सदस्यों और छोटी पार्टियों की आवाज दब जाती है।
- अधिकांश सांसद बिना प्रश्न पूछे, निजी सदस्यों के विधेयक पेश किए बिना या सार्थक बहसों में भाग लिए बिना पाँच साल का कार्यकाल पूरा कर सकते हैं और पार्टी के आदेशों द्वारा शासित मूक प्रतिनिधि बनकर रह जाते हैं।
- संसद की बैठकों में गिरावट, विधेयकों का ध्वनि मत से शीघ्र पारित होना, समितियों द्वारा कमजोर जाँच-पड़ताल और विपक्ष की उपेक्षा पहले से ही संसद को कमजोर कर रही है; सांसदों की संख्या में वृद्धि से यह संस्थागत गिरावट और भी अधिक हो जाएगी।
- अत्यधिक बड़ा सदन व्यक्तिगत कानून निर्माताओं की भूमिका को कमजोर करेगा और कार्यपालिका के प्रभुत्व को मजबूत करेगा, जो वास्तविक बातचीत में असमर्थ दिखावटी विधायिकाओं जैसा होगा; इसके बजाय संसाधनों का उपयोग बेहतर कार्यालयों, कर्मचारियों और समिति प्रणालियों के माध्यम से सांसदों की मदद करने के लिए किया जाना चाहिए।

### संस्थागत विकल्प

- सांसद राष्ट्रीय कानून निर्माता होते हैं जो कानून बनाने, विदेश नीति, व्यापक आर्थिक शासन और केंद्र सरकार की जवाबदेही के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि स्थानीय शिकायतें विधायकों और 73वें और 74वें संशोधन के तहत बनाई गई संस्थाओं से संबंधित होती हैं।
- जनसंख्या वृद्धि की समस्या का समाधान राज्य विधानसभाओं का विस्तार करके और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाकर किया जाना चाहिए, साथ ही राष्ट्रीय शासन व प्रभावी विधायी जाँच पर केंद्रित एक सुगठित लोकसभा को बनाए रखना चाहिए।

## संपादकीय के अतिरिक्त

### *परिसीमन के लिए संवैधानिक रोडमैप*

- **संवैधानिक आधार :** 84वें संशोधन ने 2026 के बाद पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने तक अंतरराज्यीय सीट आवंटन को रोक दिया।
- **ऐतिहासिक उदाहरण :** 87वें संशोधन ने राज्यवार लोकसभा सीटों में बदलाव किए बिना 2001 की जनगणना का उपयोग करके 2008 में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने में सक्षम किया।
- **जनसांख्यिकीय भिन्नता :** NFHS-5 ने केवल पाँच राज्यों में प्रतिस्थापन से ऊपर प्रजनन दर पाई, जो कम प्रजनन दर वाले राज्यों की जनसंख्या-आधारित सीट आवंटन पर चिंताओं को स्पष्ट करती है।
- **विधायी समीक्षा :** 16 अप्रैल को प्रस्तुत किए गए परिसीमन विधेयक, 2026 के लिए संसदीय जाँच और राज्यों के साथ संरचित परामर्श की आवश्यकता है।
- **समावेशी प्रतिनिधित्व :** 2022 के जम्मू एवं कश्मीर परिसीमन ने 90 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौ सीटें आरक्षित कीं।
- **महिलाओं के लिए आरक्षण :** 106वें संशोधन में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को संशोधन के बाद प्रकाशित जनगणना के आँकड़ों के परिसीमन से जोड़ा गया है।
- **सार्वजनिक परामर्श :** असम के 2023 के परिसीमन में मसौदा प्रकाशन और सार्वजनिक सुनवाई का उपयोग किया गया, जो पारदर्शी आपत्तियों व क्षेत्रीय भागीदारी के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करता है।

YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

## भारत में क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता

'क्या भारत में क्षेत्रीय दल अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं?' (Are regional parties losing relevance in India?) शीर्षक वाला यह संपादकीय 12 अगस्त 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सरकारों की कम संख्या, चुनावी असफलताओं और संगठनात्मक तनाव के बावजूद क्षेत्रीय दलों को पर्याप्त चुनावी समर्थन प्राप्त है।

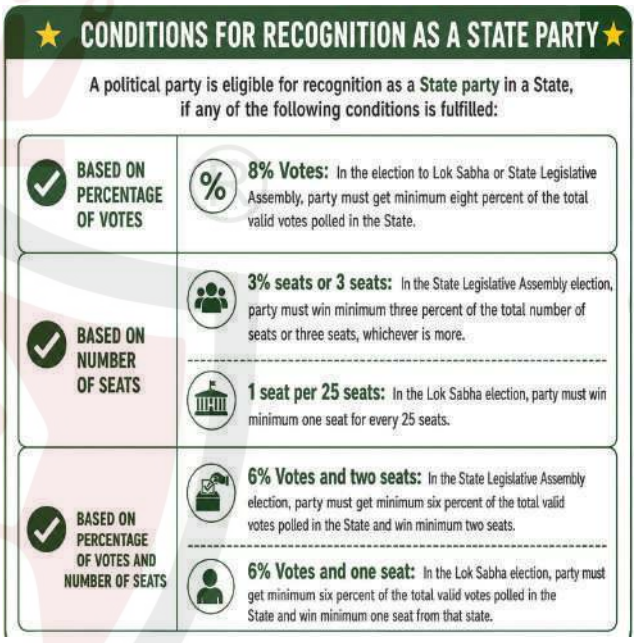
### चुनावी असफलताएँ और संगठनात्मक तनाव

- तृणमूल कांग्रेस की 2026 में पश्चिम बंगाल में हुई हार और बड़े पैमाने पर दलबदल ने क्षेत्रीय पार्टियों की प्रासंगिकता पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं।
- टीएमसी, आप एवं एनसीपी (शरद पवार) को प्रभावित करने वाले दलबदल से पार्टी की संगठनात्मक कमजोरियाँ उजागर होती हैं, न कि स्पष्ट तौर पर मतदाताओं के समर्थन में कमी आती है।
- विधानसभा चुनावों में मतदाता क्षेत्रीय पार्टियों को लोकसभा चुनावों की तुलना में अधिक मजबूती से पसंद करते हैं जो राज्य स्तर पर उनकी स्थायी पहचान को दर्शाती है।




### राजनीतिक शक्ति के वितरण में परिवर्तन

- भाजपा स्वतंत्र रूप से 11 राज्यों में सरकार चला रही है, कांग्रेस तीन राज्यों में और क्षेत्रीय दल चार राज्यों में, जो लगभग 25 वर्षों में इनकी सबसे कम संख्या है।
- क्षेत्रीय दलों ने 2015–2020 के दौरान नौ राज्यों में स्वतंत्र रूप से शासन किया, जो निरंतर चुनावी समर्थन के बीच सरकारी नियंत्रण में गिरावट का संकेत देती है।
- भाजपा समर्थित चार गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है, जबकि भाजपा क्षेत्रीय सहयोगियों वाली छह अन्य सरकारों का नेतृत्व कर रही है।
- झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर और तमिलनाडु में कांग्रेस एक कनिष्ठ गठबंधन सहयोगी बनी हुई है जो वहाँ राष्ट्रीय पार्टी के घटते प्रभुत्व को दर्शाती है।
- भारत की फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली जीत और हार दोनों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती है; इसलिए क्षेत्रीय सरकारों की कम संख्या वोट-शेयर में गिरावट का प्रमाण नहीं हैं।




### वोट-शेयर के साक्ष्य और निरंतर प्रासंगिकता

- राष्ट्रीय दलों का संयुक्त लोकसभा वोट शेयर 2009–2024 के दौरान मोटे तौर पर स्थिर रहा, जो 60.04% और 68.15% के बीच रहा।
- सीटों और सत्ताधारी गठबंधनों में बड़े बदलावों के बावजूद 2009 में उनकी हिस्सेदारी 63.59% थी और 2024 में 62.72% थी।
- क्षेत्रीय पार्टियों ने लगातार लगभग एक-तिहाई वोट प्राप्त किए जिसमें 2009 में 31.22%, 2014 में 35.85%, 2019 में 28.1% और 2024 में 33.53% है।
- क्षेत्रीय दलों ने 2024 में लोकसभा की 190 सीटें जीतीं, जो 2019 में मिली 142 सीटों से उनकी चुनावी क्षमता में निरंतर वृद्धि दर्शाती हैं।
- वर्ष 2024 में राज्यवार पर्याप्त भिन्नता के बावजूद सिक्किम, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में उनके वोट शेयर विशेष रूप से मजबूत बने रहे।
- तमिलनाडु का उदाहरण दिखाता है कि एक क्षेत्रीय पार्टी की हार दूसरी क्षेत्रीय पार्टी को लाभ पहुँचा सकती है जो क्षेत्रीय राजनीति में गिरावट के बजाय अंतर-क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा का संकेत है।

### संपादकीय से परे

#### *संघवाद के स्तंभ के रूप में क्षेत्रीय दल*

- **क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व :** तमिल भाषाई लामबंदी के माध्यम से डीएमके के उदय ने तमिलनाडु की द्वि-भाषा नीति को संरक्षित करने और हिंदी-केंद्रित समरूपता के कथित अनुमान का विरोध करने में मदद की है।
- **संघीय सौदेबाजी :** 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद टीडीपी के गठबंधन के प्रभाव ने अमरावती के विकास और पोलावरम परियोजना के पूरा होने के लिए केंद्र सरकार के समर्थन में योगदान दिया।
- **गठबंधन का संयम :** क्षेत्रीय दलों ने 1996-98 के दौरान संयुक्त मोर्चा सरकारों और बाद में यूपीए एवं एनडीए गठबंधन सरकारों को आकार दिया है जिससे विभिन्न राज्य हितधारकों के बीच बातचीत करना अनिवार्य हो गया।
- **नीतिगत नवाचार :** AIADMK के नेतृत्व में तमिलनाडु का 1982 का पौष्टिक भोजन कार्यक्रम, 1995 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्कूल भोजन कार्यक्रम का पूर्ववर्ती था।
- **संवैधानिक एकीकरण :** 1986 के मिजो समझौते से मिजो नेशनल फ्रंट ने लोकतांत्रिक राजनीति में प्रवेश किया, जिसके बाद मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला और एमएनएफ की निर्वाचित सरकार बनी।
- **प्रतिस्पर्धी संघवाद :** बीजेडी की सरकारों के तहत विकसित ओडिशा के चक्रवात आश्रय स्थल, निकासी योजना और आपदा-प्रतिक्रिया संस्थान व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त शासन पद्धतियाँ बन गए।
- **राजकोषीय संघवाद :** क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व वाली सरकारें जीएसटी परिषद के माध्यम से कराधान को प्रभावित करती हैं, जहाँ राज्यों के पास सामूहिक रूप से भारित मतदान शक्ति का दो-तिहाई हिस्सा होता है।

## संसद में विधायी चर्चा और संवाद की आवश्यकता

14 अगस्त, 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित संपादकीय 'मानसून सत्र निष्फल रहा, संसद विफल रही' (Monsoon Session was arid, Parliament fell short) में छात्रों की शिकायतों पर विचार-विमर्श करने और शिक्षा एवं रोजगार संबंधी गहन चिंताओं का सार्थक समाधान करने में संसद की विफलता को उजागर किया गया है।

### विधायी और विचार-विमर्श संबंधी विफलता

- मानसून सत्र देशव्यापी छात्र विरोध प्रदर्शनों, एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे और संसद की ओर मार्च कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद आयोजित हुआ।
- पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, लोकसभा ने 11 विधेयक पारित किए, लेकिन नौ विधेयकों में संबंधित मंत्री के अलावा किसी भी सांसद ने भाग नहीं लिया।
- केवल सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 पर ही विस्तृत बहस हुई, जो लगभग 11 घंटे तक चली और इसमें 48 सांसदों ने भाग लिया।
- यद्यपि यह विधेयक परीक्षा अनियमितताओं के विरुद्ध, 2024 के कानून को मजबूत करता है किंतु यह छात्रों के भविष्य की संभावनाओं को आकार देने वाली संरचनात्मक समस्याओं का अपर्याप्त रूप से समाधान करता है।
- छात्रों की गहरी चिंताओं की उपेक्षा करके संसद ने सड़क व संसद के बीच बढ़ती खाई को पाटने का अवसर गँवा दिया, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर हो गई।

### राजनीतिक जिम्मेदारी और अनसुलझे मुद्दे

- व्यवधान के लिए दोनों पक्ष समान रूप से जिम्मेदार हैं, लेकिन संसदीय कामकाज और विधायी बहस सुनिश्चित करने की अधिक जिम्मेदारी सरकार की है।
- गणितीय बहुमत (संख्या बल) को ध्वनि मतों के माध्यम से विचार-विमर्श का स्थान नहीं लेना चाहिए। साथ ही, सदन के प्रभावी प्रबंधन के लिए राजनीतिक सामंजस्य एवं रचनात्मक जुड़ाव आवश्यक है।
- प्रधानमंत्री व गृह मंत्री अनुपस्थित रहे, अमित शाह का चर्चा का प्रस्ताव देर से आया और विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर तख्तियाँ लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
- पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के लिए जवाबदेही, अयोध्या मंदिर के दान की कथित चोरी और दीर्घकालिक शिक्षा व रोजगार संकट सहित कई अनसुलझे मुद्दे अभी भी बने हुए हैं।
- संसद का लोकतांत्रिक वादा केवल प्रतिनिधित्व या परिसीमन संख्याओं पर ही आधारित नहीं है, बल्कि प्रतिनिधियों के जिम्मेदार, उत्तरदायी एवं सुनने के इच्छुक बने रहने पर भी आधारित है।

### संपादकीय के अतिरिक्त

#### *संसदीय विचार-विमर्श में सुधार*

- **सार्वजनिक परामर्श :** पूर्व-विधायी परामर्श नीति, 2014 में मसौदा विधेयकों को उनके औचित्य, वित्तीय निहितार्थों एवं अपेक्षित प्रभाव के साथ 30 दिनों के लिए प्रकाशित करने का प्रावधान है।
- **समिति की जाँच :** 2023 में पेश किए गए तीनों आपराधिक कानून विधेयकों को अधिनियमित होने से पहले स्थायी समिति की जाँच, हितधारकों के साथ परामर्श और रिपोर्ट 246, 247 व 248 से गुजरना पड़ा।

- **आम सहमति बनाना :** 2020 में पारित तीन कृषि कानूनों को नवंबर 2021 में निरस्त कर दिया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि स्थायी हितधारक स्वीकृति के अभाव में किए गए बड़े सुधारों की राजनीतिक कीमत क्या होती है।
- **बहस के सुरक्षा उपाय :** कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला 2021 का विधेयक लोकसभा में बिना किसी चर्चा के और राज्यसभा में केवल एक संक्षिप्त हस्तक्षेप के बाद पारित हो गया, जिससे विधायी जाँच कमजोर हो गई।
- **विपक्ष का स्थान :** ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स प्रति सत्र 20 विपक्षी दिवस आरक्षित रखता है जो गैर-सरकारी प्राथमिकताओं पर सुनिश्चित बहस के लिए एक तुलनात्मक मॉडल प्रदान करता है।
- **विधायी स्वतंत्रता :** विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में सरकार की स्थिरता को खतरे में डालने वाले मतदानों तक ही पार्टी व्हिप को सीमित करने की सिफारिश की गई, जिससे विधायकों को सामान्य विधेयकों पर अधिक स्वतंत्रता मिल सके।
- **व्यवधान के लिए जवाबदेही :** वर्ष 2023 के शीतकालीन सत्र के दौरान 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और उसके बाद प्रमुख आपराधिक कानून पारित किए गए, जो जाँच को बाधित किए बिना आनुपातिक अनुशासन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

## मुख्य परीक्षा

## विरोध करने का अधिकार

### संदर्भ

नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हालिया पुलिस कार्रवाई ने विरोध करने के अधिकार (राइट टू प्रोटेस्ट) और बीएनएसएस की धारा 163 के उपयोग पर बहस को फिर से छेड़ दिया है।

### भारत में विरोध करने के अधिकार के बारे में

- यह एक संवैधानिक अधिकार है जो नागरिकों को उचित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए शांतिपूर्वक असहमति व्यक्त करने, एकत्रित होने एवं जवाबदेही की मांग करने की अनुमति देता है।
- संविधान में विरोध करने के अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। ये अधिकार सार्वजनिक चर्चा, सरकारी जवाबदेही एवं लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।
  - **अनुच्छेद 19(1)(a):** यह वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
  - **अनुच्छेद 19(1)(b):** शांतिपूर्ण एवं निरायुध एकत्रित होने (सभा) या सम्मेलन करने का अधिकार देता है।
  - **अनुच्छेद 19(1)(c):** संघ या यूनियन बनाने के अधिकार की रक्षा करता है।
  - **अनुच्छेद 21:** यह जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा एवं शिकायतों की अभिव्यक्ति की रक्षा करता है।

### विरोध करने के अधिकार का महत्त्व

- **लोकतांत्रिक भागीदारी :** अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति एवं सभा को सक्षम बनाते हैं जिसका उदाहरण 2011 के भ्रष्टाचार रोधी आंदोलन द्वारा दिया गया है जिसमें एक प्रभावी लोकपाल की मांग की गई है।
- **सरकारी जवाबदेही :** लगातार जन आंदोलन नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसा कि कृषि कानून निरसन अधिनियम, 2021 से पहले एक वर्ष तक चले किसानों के विरोध प्रदर्शनों से पता चलता है।
- **अधिकारों की सुरक्षा :** विरोध प्रदर्शन हाशिए पर पड़े समुदायों को गरिमा एवं समानता का दावा करने में सक्षम बनाता है, जैसा कि 1927 के महाड सत्याग्रह ने जाति-आधारित सार्वजनिक जल तक पहुँच से वंचित किए जाने को चुनौती दी थी।
- **सामाजिक परिवर्तन :** सामूहिक कार्रवाई हानिकारक प्रथाओं को चुनौती देती है और सार्वजनिक नीति को नया आकार देती है, जैसे कि चिपको आंदोलन ने वन संरक्षण एवं सामुदायिक भागीदारी को मजबूत किया।
- **लोकतांत्रिक सुरक्षा वाल्व :** शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन संवैधानिक रूप से शिकायतों को व्यक्त करने का माध्यम बनता है और अलगाव को कम करता है; रामलीला मैदान निर्णय (2012) ने उचित प्रतिबंधों के अधीन शांतिपूर्ण सभा की पुष्टि की।
- **जन-जागरण :** विरोध प्रदर्शन उपेक्षित मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे कि 2012 के निर्भया विरोध प्रदर्शनों ने जस्टिस वर्मा समिति को प्रेरित किया और 2013 में आपराधिक कानून सुधारों में योगदान दिया।

### विरोध करने के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले

- **हिमत लाल के. शाह बनाम पुलिस आयुक्त (1973):** राज्य सड़कों पर सार्वजनिक सभाओं को विनियमित कर सकता है किंतु वह पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकता है या शांतिपूर्ण सभाओं पर मनमाने ढंग से अपना अधिकार नहीं जता सकता है।
- **रामलीला मैदान हादसा (2012):** नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का मौलिक अधिकार प्राप्त है; प्रतिबंध वैध और उचित होने चाहिए, जबकि पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
- **मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018):** जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध अस्वीकार्य था; अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन के अधिकारों और निवासियों के शांतिपूर्ण जीवन के बीच संतुलन बनाना होगा।
- **अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020):** शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन संवैधानिक रूप से संरक्षित है किंतु सार्वजनिक सड़कों

और स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है, खासकर जब आवश्यक आवागमन बाधित हो रहा हो।

- **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020):** धारा 144 वैध शिकायतों या लोकतांत्रिक अधिकारों को दबा नहीं सकती है और प्रतिबंधों के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा होना चाहिए तथा वे आनुपातिक होने चाहिए और न्यायिक समीक्षा की अनुमति देनी चाहिए।

## विरोध करने के अधिकार का प्रयोग करने में आने वाली समस्याएँ

- **संवैधानिक सीमाएँ :** विरोध करने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है; अनुच्छेद 19(2) भाषण पर निर्दिष्ट प्रतिबंधों की अनुमति देता है, जबकि अनुच्छेद 19(3) संप्रभुता, अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए सभाओं पर उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है।
- **निवारक आदेश का दुरुपयोग :** बीएनएसएस की धारा 163 के तहत बार-बार या व्यापक रूप से जारी किए गए आदेश, जो कि तत्काल खतरों के लिए होते हैं, असाधारण प्रतिबंधों को सामान्य बना सकते हैं और वैध असहमति को दबा सकते हैं।
- **अनुमति संबंधी बाधाएँ :** अनिर्देशित इनकार या पूर्ण प्रतिबंध से 'सभा' का अधिकार समाप्त हो सकता है; हिमत लाल (1973) ने मनमानी विवेकाधिकार को अस्वीकार कर दिया, जबकि MKSS (2018) ने पूर्ण निषेध का विरोध किया।
- **पुलिस की ज्यादतियाँ :** असंगत लाठीचार्ज, आंसू गैस या जबरन तितर-बितर करना अनुच्छेद 19 एवं 21 का उल्लंघन हो सकता है, जैसा कि रामलीला मैदान घटना (2012) से प्रदर्शित होता है।
- **असहमति को अपराधीकरण करना :** सीएए विरोधी प्रदर्शनों के बाद दर्ज की गई एफआईआर ने शांतिपूर्ण भागीदारी और साबित हो सकने वाली हिंसा, गैरकानूनी सभा या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- **डिजिटल प्रतिबंध :** इंटरनेट बंद होने से लामबंदी, संचार और रिपोर्टिंग में बाधा उत्पन्न होती है; अनुराधा भसीन (2020) ने इस प्रकार के प्रतिबंधों को अस्थायी, आवश्यक एवं आनुपातिक होने की आवश्यकता बताई।
- **सार्वजनिक व्यवधान :** अनिश्चितकालीन सड़क अवरोध यात्रियों के अधिकारों को प्रतिबंधित करते हैं; अमित साहनी (2020) ने कहा कि प्रदर्शनों को सार्वजनिक मार्गों पर लगातार कब्जा किए बिना निर्दिष्ट स्थानों का उपयोग करना चाहिए।

## शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक असहमति की रक्षा करना

- **अधिकार-आधारित विनियमन :** अधिकारियों को शांतिपूर्ण सभाओं को सुगम बनाना चाहिए और कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय अपनाने चाहिए, जो MKSS (2018) को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसने व्यापक प्रतिबंध के बजाय विनियमन एवं सुरक्षा उपायों का समर्थन किया।
- **आपातकालीन नियंत्रण :** धारा 163 के तहत बीएनएसएस के आदेशों में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए, उनकी आवधिक समीक्षा होनी चाहिए और वैधानिक समय सीमा का पालन करना चाहिए; बार-बार जारी किए जाने वाले आदेश लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने वाले नहीं होने चाहिए।
- **समान परिचालन मानक :** देशव्यापी मानक संचालन प्रक्रियाओं में अनुमति की समयसीमा, बल के प्रयोग का क्रमबद्ध तरीका, पूर्व चेतावनी, सुरक्षित निकासी मार्ग, चिकित्सा सहायता एवं वीडियो प्रलेखन स्थापित किए जाने चाहिए।
- **पुलिस की जवाबदेही :** प्रकाश सिंह (2006) में दिए गए निर्देशानुसार, राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों को विरोध प्रदर्शनों के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग और दुर्व्यवहार की स्वतंत्र रूप से जाँच करनी चाहिए।
- **संस्थागत संवाद :** आयोजकों, पुलिस, निवासियों एवं प्रशासकों के बीच स्थायी संपर्क तंत्र मार्गों, अवधि, भीड़ के आकार और सार्वजनिक असुविधा को लेकर विवादों को हल कर सकता है।
- **विरोध प्रदर्शन का ढाँचा :** जंतर-मंतर की तर्ज पर बने सुलभ एवं दिखाई देने वाले स्थलों पर पानी, स्वच्छता, चिकित्सा सहायता, परिवहन की सुविधा और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होनी चाहिए।

# न्यायिक पारदर्शिता सूचकांक रिपोर्ट

## संदर्भ

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की जस्टिस एक्सेस एंड लोअरिंग डिलेज इन इंडिया (JALDI) पहल ने अपनी तरह का पहला न्यायिक पारदर्शिता सूचकांक जारी किया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और 25 उच्च न्यायालयों का आकलन किया गया है।

## मुख्य निष्कर्ष

- **कॉलेजियम के निर्णय :** सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावों में योग्यता एवं ईमानदारी जैसे सामान्य कारकों का हवाला दिया जाता है; पिछले पाँच स्थानांतरण प्रस्तावों में कोई कारण नहीं बताया गया।
- **आरटीआई अनुपालन :** पंद्रह उच्च न्यायालय धारा 8 के अलावा अतिरिक्त छूटों का प्रावधान करते हैं और प्रायः इसके लिए अस्पष्ट, व्यापक या विरोधाभासी भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
- **वित्तीय पारदर्शिता :** आठ उच्च न्यायालय बजट प्रकाशित नहीं करते हैं जबकि कोई भी लेखापरीक्षण रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करते हैं।

- **न्यायिक प्रक्रियाएँ :** तेरह उच्च न्यायालयों ने लाइव-स्ट्रीमिंग नियमों को अपनाया किंतु केवल छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना व गुवाहाटी ने ही 75% से अधिक कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया। कोई भी न्यायालय न्यायाधीशों के चयन के मानदंड या स्पष्ट रूप से न्यायाधीशों के अलग होने और अनुशासन संबंधी नीतियों को प्रकाशित नहीं करता है।
- **संपत्ति संबंधी खुलासे :** 2025 के प्रस्ताव के बाद सर्वोच्च न्यायालय के लगभग 90% न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया; उच्च न्यायालयों में खुलासा अलग-अलग था, जिनमें केरल में 90%, दिल्ली में 13.6% और मद्रास में 11% शामिल हैं।
- **संस्थागत शक्ति :** उन्नीस उच्च न्यायालय न्यायिक संख्या की अद्यतन जानकारी प्रकाशित करते हैं लेकिन केवल पाँच ही कर्मचारियों की संख्या प्रकाशित करते हैं। इलाहाबाद, कलकत्ता, मणिपुर, पटना और त्रिपुरा दोनों ही जानकारी प्रकाशित करते हैं।
- **पंजीकरण और नियुक्तियाँ :** सभी उच्च न्यायालय रजिस्ट्री अधिकारियों की सूची प्रकाशित करते हैं, 23 संपर्क विवरण प्रदान करते हैं और 20 उनकी भूमिकाएँ निर्दिष्ट करते हैं। चौबीस जिला न्यायाधीशों की संक्षिप्त सूची प्रकाशित करते हैं किंतु केवल 14 ही अंक सार्वजनिक करते हैं।
- **स्थानांतरण :** सभी 25 उच्च न्यायालय स्थानांतरण आदेश प्रकाशित करते हैं, 18 न्यायालय कारण बताते हैं और 14 न्यायालयों की औपचारिक नीतियाँ हैं। सर्वोच्च न्यायालय संकल्प प्रकाशित करता है लेकिन उसकी कोई स्थानांतरण नीति नहीं है।
- **आचार संहिता :** कोई भी उच्च न्यायालय न्यायिक आचार संहिता प्रकाशित नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन प्रकाशित करता है किंतु उसमें शिकायत और दंड प्रक्रियाएं मौजूद नहीं हैं।
- **अनुशासनात्मक विवरण :** केवल जम्मू एवं कश्मीर और त्रिपुरा ही जिला न्यायाधीशों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी प्रकाशित करते हैं।
- **रैंकिंग :** हिमाचल प्रदेश संस्थागत शासन में अग्रणी रहा और त्रिपुरा ने कार्मिक पारदर्शिता में; मेघालय एवं बॉम्बे बजट व सार्वजनिक पहुँच के मामले में पिछड़ गए। सर्वोच्च न्यायालय ने शासन में तो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन प्रक्रिया एवं कार्मिक पारदर्शिता में उसका प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा।

## न्यायिक पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

- **अस्पष्ट अस्वीकरण प्रक्रिया :** कोई भी उच्च न्यायालय स्वयं को न्यायाधीश के पद से हटाने के मानदंड प्रकाशित नहीं करता; केवल दिल्ली उच्च न्यायालय ही स्वयं को न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया का संकेत देता है।

### कॉलेजियम प्रणाली के बारे में

- **अर्थ :** कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों की सिफारिश करता है; औपचारिक नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। इसका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।
- **सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम :** सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए, इसमें मुख्य न्यायाधीश और चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं; उच्च न्यायालय की सिफारिशों की जाँच मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं।
- **उच्च न्यायालय कॉलेजियम :** नियुक्ति के प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके बाद कार्यकारी सुझावों और सर्वोच्च न्यायालय स्तर की जाँच से गुजरते हैं।
- **संवैधानिक प्रावधान :** अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों को, अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय की नियुक्तियों को, अनुच्छेद 224 अतिरिक्त न्यायाधीशों को और अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादलों को नियंत्रित करता है।
- **न्यायिक विकास :** फर्स्ट जजेस केस (1981) ने कार्यपालिका की प्रधानता का समर्थन किया, सेकेंड जजेस केस (1993) ने न्यायिक प्रधानता स्थापित की और थर्ड जजेस केस (1998) ने कॉलेजियम का विस्तार व स्पष्टीकरण किया।
- **नियुक्ति प्रक्रिया :** सरकार पुनर्विचार के लिए सिफारिश वापस भेज सकती है किंतु अगर सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम इसे दोहराता है तो उसे प्रस्ताव स्वीकार करना होगा।
- **NJAC का निर्णय :** 99वें संवैधानिक संशोधन एवं एनजेएसी अधिनियम, 2014 का उद्देश्य कॉलेजियम को प्रतिस्थापित करना था किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के कारण 2015 में 4:1 के बहुमत से इन्हें अमान्य घोषित कर दिया।

- **लाइव-स्ट्रीमिंग में अंतर :** स्वप्निल त्रिपाठी वाद में आए फैसले के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी वेबसाइट पर लाइव-स्ट्रीमिंग के औपचारिक नियम प्रकाशित नहीं किए हैं।
- **बजट संबंधी अपारदर्शिता :** आठ उच्च न्यायालय बजट का कोई विवरण जारी नहीं करते हैं, जबकि 15 न्यायालय चालू या पिछले वर्षों के व्यय आँकड़े उपलब्ध नहीं कराते हैं।
- **अपूर्ण संपत्ति प्रकटीकरण :** कोई भी उच्च न्यायालय अपने सभी न्यायाधीशों की संपत्ति संबंधी घोषणाएँ प्रकाशित नहीं करता है; केवल सात न्यायालय ही न्यायाधीशों द्वारा किए गए खुलासों की रिपोर्ट करते हैं।

- **अस्पष्ट नियुक्तियाँ :** न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश करने या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले के लिए सीमित कारण बताते हैं।
- **अपारदर्शी केस आवंटन :** कोई भी अदालत न्यायाधीशों की पीठ गठित करने या मामलों को सौंपने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रकाशित नहीं करती है, जिससे प्रशासनिक विवेकाधिकार के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

### पारदर्शी न्यायपालिका के लिए रोडमैप

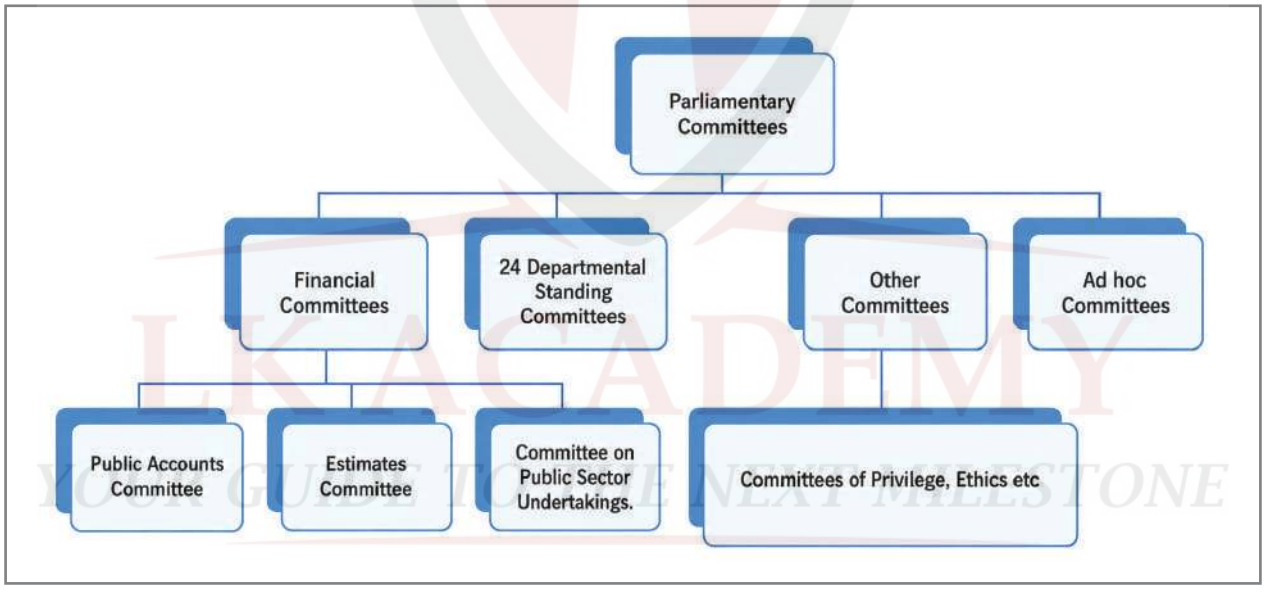
- **कॉलेजियम में पारदर्शिता :** नियुक्तियों व तबादलों के लिए उम्मीदवार-विशिष्ट कारणों को रिकॉर्ड करना, 2017 के पारदर्शिता प्रस्ताव को निरंतर लागू करना और वैध गोपनीयता की रक्षा करते हुए मापन योग्य चयन मानदंड प्रकाशित करना।
- **रोस्टर में पारदर्शिता :** न्यायाधीशों की नियुक्ति, मामलों के वर्गीकरण और आवंटन के लिए स्थिर नीतियाँ प्रकाशित करना और स्थापित रोस्टर मानदंडों से महत्त्वपूर्ण विचलन के कारणों को भी दर्ज करना।
- **तर्कसंगत तबादले :** मनमानी या दंडात्मक कार्रवाई की धारणाओं को कम करने के लिए आवश्यक गोपनीयता के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालयों में तबादलों के लिए संस्थागत रूप से सार्थक कारण प्रदान करना।
- **आरटीआई अनुपालन :** केवल वैधानिक छूटों को ही लागू करना; सुभाष चंद्र अग्रवाल वाद के फैसले (2019) ने पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में पुष्टि की।
- **खुली न्याय व्यवस्था :** स्वप्निल त्रिपाठी वाद (2018) के तहत लाइव स्ट्रीमिंग का विस्तार करना, समय पर कारण सूचियाँ एवं प्रतिलेख प्रकाशित करना और गोपनीयता या सुरक्षा के लिए बहिष्कृत कार्यवाही का स्पष्ट रूप से पहचान करना।
- **नैतिक जवाबदेही :** विश्वसनीय शिकायत तंत्र स्थापित करना, न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन को लागू करना और न्यायाधीशों की संपत्तियों के आवधिक सार्वजनिक प्रकटीकरण को संस्थागत रूप देना।
- **प्रशासनिक आधुनिकीकरण :** रिक्तियों, कर्मचारियों की संख्या, भर्ती संबंधी आँकड़े, बजट एवं लेखापरीक्षाओं को नियमित रूप से प्रकाशित करना; न्यायिक एआई नीति अपनाना और अनुसंधान के लिए गुमनाम केस डेटा जारी करना।

## प्रारंभिक परीक्षा

## अधीनस्थ विधान समिति की 257वीं रिपोर्ट

### संदर्भ

राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समिति ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा 2024 में बनाए गए विनियमों की जाँच की।




### अधीनस्थ विधान समिति के बारे में

- यह एक संसदीय स्थायी समिति है जिसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग 15 सदस्यीय समितियाँ हैं।
  - इस समिति में किसी मंत्री को मनोनीत नहीं किया जाता है।
- यह इस बात की जाँच करता है कि नियम, विनियम, उपनियम और अन्य वैधानिक उपकरण बनाने की शक्तियाँ संविधान या संसद द्वारा प्रदत्त अधिकार के दायरे में प्रयोग की जाती हैं या नहीं।

### मुख्य अवलोकन और सिफारिशें

| क्षेत्र | समिति की टिप्पणी | सिफारिश |
|---|---|---|
| **नियामक समीक्षा** | प्रतिस्पर्धा कानून को उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का जवाब देना होगा। | समय-समय पर सीसीआई के नियमों की समीक्षा करना व वैश्विक प्रथाओं के साथ उनकी तुलना करना। |
| **MSME संरक्षण** | बड़ी कंपनियाँ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों व स्टार्टअप्स के खिलाफ बाजार शक्ति का दुरुपयोग कर सकती हैं। | प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रवर्तन को मजबूत करना व लक्षित प्रतिस्पर्धा की वकालत करना। |
| **बार-बार अपराध** | कंपनियाँ जुर्माने को केवल व्यवसाय करने की लागत के रूप में मान सकती हैं। | मौद्रिक दंड दिशा-निर्देशों के तहत बार-बार उल्लंघन को गंभीर कारक के रूप में माना जाना चाहिए। |
| **पारदर्शिता** | कई बार अपील के दौरान सीसीआई द्वारा लगाए गए दंडों पर रोक लगा दी जाती है या उन्हें रद्द कर दिया जाता है। | दंड की गणना के लिए विस्तृत गणितीय विवरण प्रदान करना और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया को मजबूत करना। |
| **नियामक समन्वय** | आधुनिक प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दे प्राय: कई क्षेत्रीय नियामकों के साथ परस्पर संबंधित होते हैं। | सूचना साझाकरण व नीति समन्वय के लिए समझौता ज्ञापनों सहित औपचारिक तंत्र स्थापित करना। |

### भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- यह प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं को समाप्त करता है, उपभोक्ता हितों की रक्षा करता है और निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
- यह प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों, प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग और विलय एवं अधिग्रहण सहित संयोजनों को विनियमित करता है।

## राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026

### संदर्भ

संसद ने वंदे मातरम के गायन के दौरान बाधा डालने या व्यवधान उत्पन्न करने पर दंड का प्रावधान करते हुए इसे कानूनी संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया है।

### विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- यह विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करता है ताकि वंदे मातरम को इसके दायरे में शामिल किया जा सके।
  - यह जान-बूझकर इसके गायन को रोकने या इसके गायन में संलग्न किसी समूह को बाधित करने पर दंडनीय है।
  - इस अपराध के लिए तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  - बार-बार अपराध करने वालों को कम से कम एक साल की कैद की सजा का सामना करना पड़ता है।
- यह विधेयक 24 जनवरी, 1950 को हुई संविधान सभा की कार्यवाही को याद दिलाता है, जब डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को जन गण मन के समान दर्जा प्रदान किया था।
  - यह स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रगान की ऐतिहासिक भूमिका को मान्यता देता है।
  - यह राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण के अभाव से उत्पन्न कानूनी अंतर को पाटता है।

### राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971

- धारा 2 भारत के राष्ट्रीय ध्वज या संविधान को जलाने, विकृत करने, अपवित्र करने या किसी भी प्रकार से अपमानित करने पर रोक लगाता है।
  - इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
  - राष्ट्रीय ध्वज में संवैधानिक संशोधन या परिवर्तन कराने के उद्देश्य से की गई वैध आलोचना अपराध नहीं है।
- धारा 3 जान-बूझकर राष्ट्रगान गाने से रोकने या राष्ट्रगान गाते समय किसी सभा में अशांति फैलाने पर रोक लगाता है।
  - इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
- 2003 के संशोधन के माध्यम से शामिल की गई धारा 3A में धारा 2 या 3 के तहत दूसरी बार तथा उसके बाद दोषी ठहराए जाने पर कम से कम एक साल की सजा का प्रावधान है।

## डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

### संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारों, वित्तीय नियामकों, दूरसंचार अधिकारियों एवं जाँच एजेंसियों को डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के खिलाफ कार्रवाई में समन्वय स्थापित करने और पीड़ितों की धनराशि की वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

### सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्देश

- भारतीय रिजर्व बैंक को चार सप्ताह के भीतर उन खातों पर अस्थायी डेबिट रोक लगाने के लिए एक मानक प्रक्रिया (SOP) अपनानी होगी जो अवैध लेनदेन और साइबर-आधारित धोखाधड़ी से जुड़े हैं।
  - अंतिम मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) को आई4सी और सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

- आरबीआई को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में विलंबित लेनदेन से बचाव और ग्राहक संरक्षण उपायों को भी लागू करना चाहिए।

❖ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गृह मंत्रालय की मानक परिचालन नीति (SOP) के तहत शिकायत निवारण और धन वापसी मॉड्यूल को कार्यान्वित करना होगा।
- उच्च न्यायालयों को खातों को फ्रीज करने से संबंधित मामलों से निपटने वाले न्यायालयों और न्यायनिर्णय अधिकारियों को शिकायत निवारण तंत्र के बारे में सूचित करना होगा।
- वसूली गई धनराशि को अदालतों, उपभोक्ता मंचों, आरबीआई लोकपाल और प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से शीघ्रता से वितरित किया जाना चाहिए।

❖ शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार सप्ताह के भीतर राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने और ई-जीरो एफआईआर तंत्र को अपनाने की आवश्यकता है।
- ई-जीरो एफआईआर 19 राज्यों में कार्यरत थी, जबकि केवल 14 राज्यों ने समन्वय केंद्रों को अधिसूचित किया था।

❖ अंतर-विभागीय समिति को तकनीकी सुरक्षा उपायों, साझा दायित्व, पीड़ित मुआवजे और धोखाधड़ी वाले ऑडियो व वीडियो कॉल के लिए संभावित समय-आधारित किल स्विच की जाँच करनी चाहिए।

❖ सीबीआई को अपनी 10 करोड़ रुपये की जाँच सीमा को कम करने और एक ही संगठित नेटवर्क द्वारा किए गए धोखाधड़ी के मामलों को एक साथ समूहित करने पर विचार करना चाहिए।

## डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में

❖ डिजिटल अरेस्ट एक साइबर घोटाला है जिसमें धोखेबाज पुलिस, अदालतों या जाँच एजेंसियों का रूप धारण करके पीड़ितों को डराकर उनसे पैसे हस्तांतरित करवा लेते हैं।
- पीड़ितों को झूठे आपराधिक मामलों से जोड़ा जाता है और उन्हें गिरफ्तारी, खाते फ्रीज करने या लंबे समय तक पूछताछ की धमकी दी जाती है।
- धोखाधड़ी करने वाले लोग विश्वसनीय दिखने के लिए फर्जी नंबर, वीडियो कॉल, जाली वारंट एवं नकली आधिकारिक दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं।
- पीड़ितों पर काल्पनिक जुर्माना या सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करने का दबाव डाला जाता है, हालाँकि डिजिटल गिरफ्तारी को कोई कानूनी मान्यता नहीं है।

# केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026

## संदर्भ

संसद ने उस विधेयक को पारित कर दिया है जिससे केरल का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम् करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जो मलयालम में राज्य के नाम को दर्शाता है।

## विधेयक के प्रमुख प्रावधान

❖ इस विधेयक के तहत राज्य का संवैधानिक नाम केरल से बदलकर केरलम् कर दिया गया है जो एक निर्धारित तिथि से प्रभावी होगा।
- यह केरल विधानसभा द्वारा 24 जून, 2024 को सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बाद हुआ है।
- यह नाम केरल की मलयालम भाषाई पहचान और ऐक्य केरल आंदोलन की विरासत को दर्शाता है।

❖ यह संविधान के अनुच्छेद 31A और 290A तथा पहली व चौथी अनुसूची में केरल के संदर्भों को प्रतिस्थापित करता है।
- केरल से संबंधित मौजूदा कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी, जिसमें राज्य के नाम के स्थान पर 'केरलम्' शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
- सरकारें मौजूदा कानूनों में उनके मूल स्वरूप को बदले बिना एक वर्ष के भीतर संशोधन कर सकती हैं।

❖ यह परिवर्तन राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी होगा।

## राज्य का नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया

❖ अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने या किसी मौजूदा राज्य के क्षेत्रफल, सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार देता है।
- इस प्रकार का विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति को इसे संबंधित राज्य विधानमंडल को निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजना होगा।
- राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं।

❖ अनुच्छेद 4 के माध्यम से अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानूनों से पहली एवं चौथी अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है और उनसे जुड़े प्रावधान भी शामिल किए जा सकते हैं।
- ऐसे कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है।
- इसलिए यह विधेयक संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।

❖ इससे पहले राज्यों के नाम बदलने में 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड और 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा करना शामिल है।

## केरल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

❖ अशोक के प्रमुख शिलालेख II में केरलपुत्रों का उल्लेख है जिनका संबंध आमतौर पर प्राचीन चेरा क्षेत्र से है।

❖ भाषाविज्ञानी हरमन गुंडर्ट ने 'केरलम्' को 'चेराम' या 'चेरालम' से जोड़ा है, हालाँकि नाम की सटीक व्युत्पत्ति अभी भी बहस का विषय है।

❖ ऐक्य केरल आंदोलन ने 1920 के दशक के दौरान गति पकड़ी और एक एकीकृत मलयालम भाषी राज्य की मांग की।

❖ भाषाई पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर, 1956 को आधुनिक केरल का गठन हुआ।
- इस दिन को केरल पिरवी के रूप में मनाया जाता है।
- संविधान में अंग्रेजीकृत नाम 'केरल' का प्रयोग किया गया, जबकि मलयालम में 'केरलम्' नाम जारी रहा।

❑❑❑

# विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

## संपादकीय

### कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृषि : आंध्र प्रदेश के लिए एक अवसर

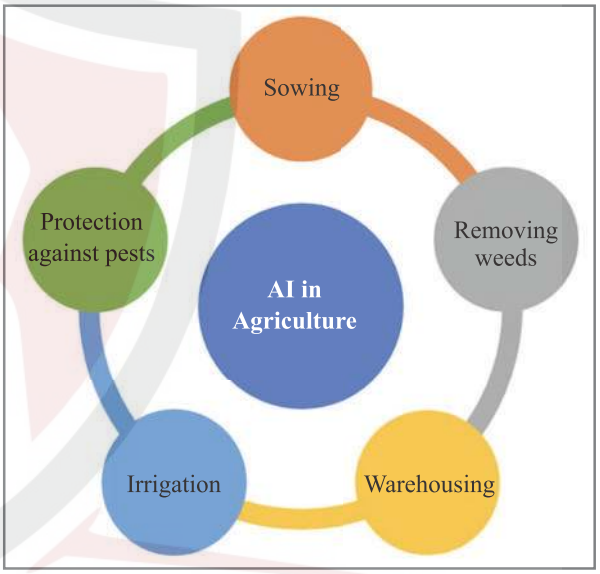
'एआई और कृषि के बीच एक नया कॉम्पैक्ट : आंध्र प्रदेश के लिए एक अवसर' (A new compact between AI & agriculture: An Andhra Pradesh opportunity) शीर्षक वाला यह संपादकीय 3 अगस्त, 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार एग्रीवोल्टिक्स एआई डेटा केंद्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और किसानों को स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना का सह-मालिक बना सकता है।

### ऊर्जा संबंधी चुनौती और एग्रीवोल्टिक्स अवसर

- गूगल का प्रस्तावित 15 अरब डॉलर का एक गीगावाट क्षमता वाला विशाखापत्तनम एआई डेटा सेंटर, जिसके 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है, को प्रतिदिन 24 गीगावाट बिजली की आवश्यकता होगी।
- मौजूदा बिजली का प्रयोग करने से कृषि एवं उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँच सकता है जबकि अतिरिक्त तापीय ऊर्जा उत्पादन से पर्यावरणीय लागत बढ़ेगी।
- आंध्र प्रदेश का डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस हाइपरस्केल ऑपरेटरों को अपनी बिजली की खरीद और प्रबंधन करने की अनुमति देता है जिससे कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा समाधान संभव हो पाते हैं।
- एग्रीवोल्टिक्स एक ही भूमि पर खेती और ऊँचे सौर पैनलों को जोड़ता है जिससे किसानों को आय में विविधता लाने के साथ-साथ खाद्य एवं बिजली का उत्पादन करने की सुविधा मिलती है।
- किसानों को भूमि का स्वामित्व बरकरार रखना चाहिए और सामुदायिक आधारित विशेष प्रयोजन वाहनों में इक्विटी रखनी चाहिए, जिससे वे गूगल को बिजली प्रदान करने वाले सौर उद्यम के सह-मालिक बन सकें।

### वित्तपोषण और परिचालन मॉडल

- दुग्ध सहकारी समितियों की तर्ज पर बनाई गई सौर सहकारी समितियाँ किसानों को एकजुट कर सकती हैं जबकि 10-12 फीट ऊँचे पैनल लगाने से उनके नीचे खेती करना संभव हो सकेगा।
- गूगल कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करा सकता है, जिसे संशोधित पीएम-कुसुम सब्सिडी और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट से प्राप्त क्रेडिट गारंटी द्वारा पूरक बनाया जा सकता है।
- डीडीएल ढाँचे के तहत गूगल एक दीर्घकालिक ऑफटेकर के रूप में ओपन-एक्सेस और बैंकिंग व्यवस्था का उपयोग कर सकता है जिससे किसान उपयोगिताओं को एक क्रेडिट योग्य ग्राहक मिल जाएगा।
- ICRIER के पायलट प्रोजेक्ट से पता चलता है कि सौर ऊर्जा तीसरी फसल बन सकती है, जिससे कृषि आय आठ से दस गुना बढ़ सकती है। साथ ही, सिंचाई, छाया वाली फसलों, प्रसंस्करण व बिजली की बिक्री को भी समर्थन मिल सकता है।




### व्यापक लाभ और विस्तार

- प्रस्तावित 5,000 एक-मेगावाट कृषि-फोटोवोल्टिक प्रणालियाँ, जिनकी लागत लगभग 4 करोड़ रुपये प्रति प्रणाली है, अनुमानित 20,000 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से 5 गीगावाट क्षमता का सृजन करेंगी।
- मिश्रित वित्तपोषण और गारंटीकृत बिजली खरीद से सरकारी बजट पर न्यूनतम दबाव के साथ धन जुटाया जा सकता है।
- किसानों को फसल, बिजली से होने वाली आय और लाभांश प्राप्त होता है; गूगल को प्रतिस्पर्धी स्वच्छ ऊर्जा और सामाजिक स्वीकृति मिलती है, जबकि राज्य भूमि और बिजली को लेकर होने वाले संघर्ष से बच जाता है।
- भूमि अधिग्रहण के विपरीत, जिसमें किसानों को एकमुश्त किराया प्रदान किया जाता है, सह-स्वामित्व मॉडल भूमि को एक संपत्ति

IKAGURU
YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

के रूप में बरकरार रखता है और डेटा सेंटर को एक भरोसेमंद ग्राहक बनाता है।

### संपादकीय के अतिरिक्त

### एग्रीवोल्टिक्स प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़े जोखिम

- **फसल की उपयुक्तता :** ICAR-IARI का 100 kWp का पायलट प्रोजेक्ट फसल संयोजनों का परीक्षण कर रहा है क्योंकि शेडिंग एवं उत्पादकता के प्रभाव कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होते हैं।
- **उपज सुरक्षा उपाय :** जापान में सौर ऊर्जा साझाकरण परियोजनाओं के लिए संदर्भ फसल उपज का 80% हिस्सा बरकरार रखना अनिवार्य है जबकि जर्मनी 66% के मानक का उपयोग करता है।
- **पूंजीगत बोझ :** उच्च स्तरीय बागवानी प्रणालियाँ प्राय: अंतरस्थानिक डिजाइनों की तुलना में अधिक महँगी होती हैं जिससे सब्सिडी व रियायती वित्तपोषण पर निर्भरता बढ़ जाती है।
- **समावेशी स्वामित्व :** पीएम-कुसुम किसानों, सहकारी समितियों, पंचायतों, परिवारिक संगठनों और जल-उपयोगकर्ता संघों की भागीदारी की अनुमति देता है जिससे बड़े भूस्वामियों के बीच केंद्रीकरण सीमित होता है।
- **परिचालन संबंधी जटिलता :** पैनल पर गंदगी, जंग लगना, कीटनाशकों के संपर्क में आना और मशीनरी को नुकसान जैसी समस्याओं के लिए विशेष रखरखाव एवं संगत कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है।
- **राजस्व सुरक्षा :** पीएम-कुसुम भुगतान और बिजली की खपत से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए 25 वर्ष के बिजली खरीद समझौतों, अनिवार्य डिस्कॉम खरीद और एस्क्रो व्यवस्था का उपयोग करता है।
- **एंड-ऑफ-लाइफ दायित्व :** ओडिशा में पीएम-कुसुम परियोजनाओं के लिए पीपीए की समाप्ति के बाद ई-कचरा नियमों का पालन करना अनिवार्य है जो उचित निपटान एवं भूमि पुनर्स्थापन में सहायक होगा।

## कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा

'एआई एवं साइबर, आज के सुरक्षा खतरों का दोहरा चक्र' (AI and cyber, the double helix of today's security threats) शीर्षक वाला यह संपादकीय 4 अगस्त, 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर खतरों का अभिसरण किस प्रकार युद्ध को बदल रहा है, शक्ति का पुनर्वितरण कर रहा है और वैश्विक सुरक्षा उपायों को पछाड़ रहा है।

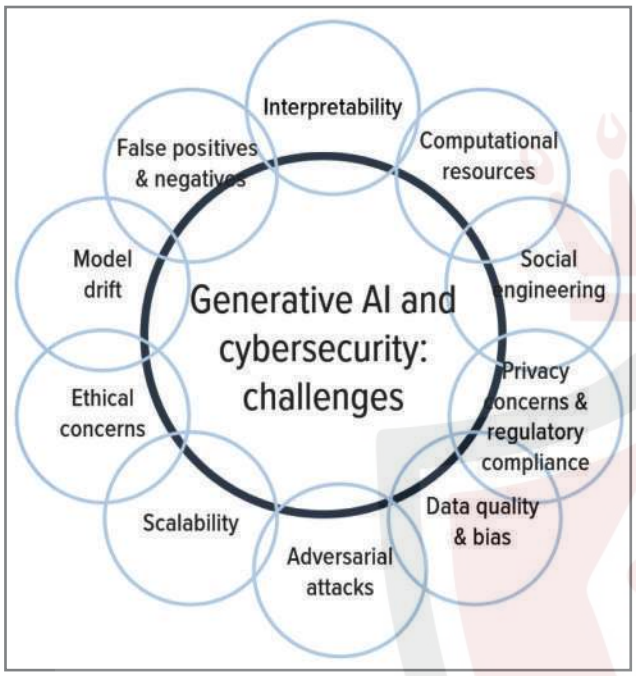
### सुरक्षा खतरों का अभिसरण

- डिजिटल अंतर्संबंध में हो रही वृद्धि एआई एवं साइबर जोखिमों को परस्पर मजबूत बनाती है जिससे वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के हर स्तर पर खतरा पैदा होता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित मैलवेयर पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल ढल सकते हैं, पारंपरिक एंटीवायरस प्रणालियों से बच सकते हैं और साइबर हमलों का पता लगाना और उन्हें कम करना कठिन कर सकते हैं।
- दुर्भावनापूर्ण ऑटोनॉमस एजेंट जीरो ट्रस्ट प्रोटोकॉल को कमजोर कर सकते हैं और आंतरिक खतरों को बढ़ा सकते हैं जिससे मौजूदा सुरक्षा वास्तुकला में कमजोरियाँ उजागर हो सकती हैं।
- यूक्रेन युद्ध से पता चलता है कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ किस प्रकार असममित लाभ पैदा करती हैं जो पारंपरिक सैन्य गणनाओं को बाधित करने में सक्षम हैं।
- सरकारें नवाचार, नीतिगत सामंजस्य और रणनीतिक यथार्थवाद को एक साथ ला रही हैं किंतु उनकी साइबर तैयारियाँ परिष्कृत डिजिटल विरोधियों से पीछे चल रही हैं।

### एजेंटिक एआई और बदलती सत्ता संरचनाएँ

- व्यवसाय पर्याप्त प्रशिक्षण या मानव-इंटरफेस अनुकूलन के बिना तेजी से लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अपना रहे हैं जिससे एजेंटिक एआई का कार्यान्वयन तेजी से जटिल होता जा रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार, एंथ्रोपिक के मिथॉस ने प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टमों में जीरो-डे कमजोरियों का पता लगाया है, जिससे पुराने सिस्टमों की सीमाएँ उजागर हुई हैं।
- रूस-यूक्रेन एवं अमेरिका-इजराइल-ईरान संघर्षों में एआई-सक्षम प्रणालियों ने मिसाइल प्रक्षेप पथों को ट्रैक किया है और इमेज, टेक्स्ट, रेडियो व विद्युत चुम्बकीय संकेतों से खुफिया जानकारी निकाली है।
- गोलकीपर और व्हिपलैश जैसे स्वायत्त गोला-बारूद स्वतंत्र रूप से लक्ष्यों की पहचान कर उन पर हमला कर सकते हैं, जिससे मानवीय नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं।
- विश्व आर्थिक मंच ने चेतावनी दी है कि एआई साइबर सुरक्षा को मजबूत कर सकता है किंतु साथ ही साथ परिष्कृत स्वचालित हमलों को सक्षम कर सकता है जो जीरो ट्रस्ट सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं।
- उन्नत स्वायत्त एजेंट विद्रोही समूहों को ऐसी क्षमताएँ प्रदान कर सकते हैं जो पहले केवल राज्यों तक ही सीमित थीं, जिससे सैन्य एवं आर्थिक शक्ति एआई नेताओं की ओर पुनर्वितरित हो सकती हैं।

❖ मानवजनित, पलान्टिर और तुलनीय पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से उन्नत प्रौद्योगिकी को नियंत्रित कर रहे हैं जबकि एआई के संकेंद्रण और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियम अभी भी अविकसित हैं।




## शासन, विश्वसनीयता एवं भू-राजनीतिक जोखिम

❖ जैसे-जैसे एजेंटिक ऑटोनॉमस ऑपरेशंस अधिक सक्षम, स्वायत्त और वर्तमान शासन ढाँचे के माध्यम से नियंत्रित करना अधिक कठिन होते जा रहे हैं, मौजूदा साइबर नियमों के पुनर्लेखन की आवश्यकता हो सकती है।

❖ कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न मतिभ्रम, व्यक्तिपरक निर्णय और अंतर्निहित एल्गोरिथम पूर्वाग्रह विकृत निर्णय उत्पन्न कर सकते हैं और एल्गोरिथम संबंधी कट्टरता को बढ़ावा दे सकते हैं।

❖ अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोप कि चीन के मूनशॉट ने एंथ्रोपिक के फेबल मॉडल की नकल की है, जिसे चीन ने खारिज कर दिया है, अत्याधुनिक एआई क्षमताओं को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाते हैं।

❖ यदि उन्नत मॉडल कमजोरियों को खोजने और उनका फायदा उठाने में अधिकांश मनुष्यों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो खतरे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे तक फैल सकते हैं।

❖ रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अविश्वसनीय या राष्ट्रीय स्तर पर पक्षपातपूर्ण चेतावनी उत्पन्न कर सकती है; इसलिए मानवीय निगरानी बनाए रखना और चेतावनियों को सटीक स्थितिगत समझ से जोड़ना आवश्यक है।

### संपादकीय के अतिरिक्त

### *कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस साइबर युद्ध के लिए भारत की तैयारी*

◆ **बढ़ते खतरे का भार :** CERT-In ने 2025 में 29.44 लाख से अधिक साइबर घटनाओं को संभाला और 1,530 अलर्ट जारी किए, जो भारत की साइबर-सुरक्षा प्रणाली के सामने मौजूद चुनौतियों के पैमाने को दर्शाता है।

◆ **संस्थागत आधार :** रक्षा एआई परिषद और रक्षा एआई परियोजना एजेंसी का गठन सैन्य एआई को अपनाने में तेजी लाने के लिए किया गया था किंतु इसके लिए तीनों सेनाओं एवं नागरिकों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता है।

◆ **स्वदेशी क्षमता:** ₹10,371.92 करोड़ के इंडियाएआई मिशन ने 38,000 से अधिक जीपीयू को शामिल किया है जो घरेलू मॉडल और सुरक्षित रक्षा-स्तरीय कंप्यूटिंग के लिए एक आधार प्रदान करता है।

◆ **वास्तविक अभ्यास :** भारत एनसीएक्स 2025 ने स्वायत्त मैलवेयर, डीपफेक हेरफेर और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे पर हमलों का अनुकरण किया, जिससे एआई-सक्षम साइबर संकटों के लिए परिचालन तत्परता में सुधार हुआ।

◆ **मॉडल आश्वासन :** इंडियाएआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट और 13 रिस्पॉन्सिबल एआई परियोजनाएँ पूर्वाग्रह, गोपनीयता, व्याख्यात्मकता एवं जोखिम मूल्यांकन को कवर करती हैं जो सैन्य एआई परीक्षण को सूचित कर सकती हैं।

◆ **विशेषज्ञ कार्यबल :** CSPAI कार्यक्रम साइबर सुरक्षा पेशेवरों को एआई सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए प्रशिक्षित करता है, जो रक्षा और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में इसी तरह की क्षमता निर्माण के लिए एक मॉडल प्रदान करता है।

◆ **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग :** 2026 ऑस्ट्रेलिया-भारत साझेदारी में साइबर अपराध, दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधि, सुरक्षा मानदंड और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा शामिल हैं जो सीमा पार खतरों के खिलाफ सामूहिक लचीलेपन का समर्थन करते हैं।

## धोखाधड़ी को रोकना

'स्टॉप दि स्कैम' (Stop the scam) शीर्षक वाला यह संपादकीय 7 अगस्त, 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसमें डिजिटल अरेस्ट घोटालों से निपटने में भारत की प्रगति, प्रवर्तन संबंधी कमियों और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

## शिकायतों में कमी और संस्थागत प्रतिक्रिया

❖ साइबर अपराध की शिकायतें 2024 में 1,23,672 से घटकर 2025 में 58,249 और 2026 की पहली छमाही में 16,377 रह गई, जो उत्साहजनक प्रगति दर्शाती है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई को संदिग्ध अवैध खातों पर अस्थायी डेबिट रोक लगाने के लिए मानक प्रक्रियाएँ तैयार करने का निर्देश दिया है।
- राज्यों को साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने और त्वरित पंजीकरण एवं जाँच के लिए ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIRs) लागू करने की आवश्यकता है।
- एक अंतरविभागीय समिति पीड़ित के लिए मुआवजे की जाँच करेगी, जबकि बैंकों, दूरसंचार ऑपरेटरों और पुलिस की सलाह से वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी में कमी आई है।
- युवाओं और पेशेवरों के लिए जारी की गई सलाह अपर्याप्त बनी हुई हैं, जबकि जाँच के बावजूद कम दोषसिद्धि दर धीमी एवं अप्रभावी कानून प्रवर्तन व्यवस्था को उजागर करती है।

## विकसित होती पद्धतियाँ और वित्तीय पुनर्प्राप्ति

- धोखाधड़ी करने वाले लोग सिम बॉक्स का इस्तेमाल करके भारतीय नंबर शो करते हैं, तेजी से पैसे ट्रांसफर करने के लिए अंतरराज्यीय खातों का उपयोग करते हैं और वीडियो कॉल के दौरान डीपफेक का इस्तेमाल करते हैं।
- न्यायालय ने वित्तीय मुआवजे को प्राथमिकता दी है जो 36,290 मामलों में ₹18.05 करोड़ की राशि के साथ पूरा किया गया। साथ ही, खाता-फ्रीज मामलों के तेजी से निपटान को भी प्राथमिकता दी है।
- MuleHunter.AI, जिसे 20 से अधिक बैंकों में तैनात किया गया है, विदेशी अपराधियों के अज्ञात या दोषी न ठहराए जाने की स्थिति में भी वित्तीय नुकसान को सीमित करने में मदद करता है।

## सीमा-पारीय धोखाधड़ी नेटवर्क

- दुर्लभ दोषसिद्धि म्यांमार, गोल्डन ट्रायंगल और कंबोडिया में फैले विदेशी घोटाले के अड्डों से संचालित होने वाले व्यवसायों को दर्शाती है जिन्हें प्रायः आधिकारिक संरक्षण के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती थी।
- म्यांमार की छापेमारी काफी हद तक अप्रभावी रही क्योंकि धोखाधड़ी के केंद्र संघर्ष क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए, जिससे वे घरेलू जाँचकर्ताओं से आगे निकल गए।
- चीन द्वारा 2023 में की गई कार्रवाई के बाद नेटवर्क ने अन्य देशों को निशाना बनाया और भारतीयों को जबरदस्ती एवं यातना के तहत डिजिटल अपराध करने के लिए तस्करी की।
- भारत को म्यांमार और कंबोडिया में धोखाधड़ी नेटवर्क को खत्म करने के लिए मजबूर करने हेतु चीन, अमेरिका एवं आसियान के साथ राजनयिक दबाव का समन्वय करना चाहिए।

### संपादकीय के अतिरिक्त

#### *साइबर अपराध प्रवर्तन में नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा*

- **आनुपातिक फ्रीजिंग :** डॉ. सजीर बनाम आरबीआई (2024) वाद में केरल उच्च न्यायालय ने खाते पर प्रतिबंध को पूरी शेष राशि की बजाय विवादित राशि तक सीमित कर दिया।
- **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय :** शबीर बनाम फेडरल बैंक (2026) वाद में न्यायालय ने पुलिस को एक महीने के भीतर विवादित राशि निर्दिष्ट करने या रोक हटाने का निर्देश दिया।
- **निर्दोष खाता संरक्षण :** अबू बकर सिद्दीक (2026) वाद में न्यायालय ने तीन पुलिस अनुरोधों के माध्यम से ग्रहणाधिकार के तहत रखे गए ₹28,000 से अधिक के खाता संचालन की अनुमति दी।
- **निजता संरक्षण :** पुट्टास्वामी वाद निर्णय (2017) में वित्तीय व दूरसंचार डेटा साझाकरण सहित राज्य के हस्तक्षेप में वैधता, आवश्यकता एवं आनुपातिकता की मांग की गई है।
- **एल्गोरिथम आधारित जवाबदेही :** दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया RBIH का MuleHunter.AI, पैटर्न-आधारित संदेह के माध्यम से ग्राहकों को स्वचालित रूप से दंडित करने के बजाय मानवीय सत्यापन का समर्थन करेगा।
- **समयबद्ध निवारण :** I4C के जनवरी 2026 के मानक परिचालन (SOP) में साइबर अपराध से संबंधित फ्रीज, ग्रहणाधिकार (Lien) या भुगतान रोक (पेमेंट होल्ड) से प्रभावित खाताधारकों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है।
- **न्यायिक पर्यवेक्षण :** केरल उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विवादित धनराशि को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा जाता है जिसमें पीड़ित को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति और खाताधारकों के संपत्ति अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है।

## मुख्य परीक्षा

# अगली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में एआई

## संदर्भ

सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ भारत के अगले डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के रूप में एआई का प्रस्ताव करते हैं जिसमें आधार, यूपीआई एवं डीईपीए (DEPA) से प्रेरित निम्न लागत वाले अनुमान एवं ओपन-सोर्स मॉडल का उपयोग किया जाता है।

## भारत के अगले डीपीआई के रूप में एआई को कमोडिटी बनाने के बारे में

- **मूल विचार :** एआई को कमोडिटी बनाने का अर्थ कंप्यूटिंग क्षमता, एआई मॉडल और अनुमान को किफायती, सुलभ एवं

EK ACADEMY YOUR GUIDE TO THE NEXT MISSION

अंतरसंचालनीय बनाने से है, जैसे कि सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढाँचा, न कि कोई महँगी मालिकाना सेवा।

- **डीपीआई मॉडल :** यह सरकारों, शोधकर्ताओं, स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई के लिए उपलब्ध साझा कंप्यूटिंग संसाधनों, खुले मॉडलों, विश्वसनीय डेटासेट एवं मानक इंटरफेस के माध्यम से आधार, यूपीआई व डीईपीए पर आधारित होगा।
- **उद्देश्य :** एआई तक पहुँच की लागत कम करने से स्थानीय भाषा की शिक्षा, कृषि परामर्श, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा और नागरिक सेवाओं जैसे अनुप्रयोगों को समर्थन मिल सकता है जबकि विदेशी एआई प्लेटफार्मों पर निर्भरता कम हो सकती है।

## भारत के अगले डीपीआई के रूप में एआई के पक्ष में तर्क

- **इंडिया स्टैक का स्वाभाविक विस्तार :** आधार डिजिटल पहचान को सक्षम बनाता है, यूपीआई अंतरसंचालनीय वास्तविक समय भुगतान प्रदान करता है और डीईपीए सहमति-आधारित डेटा साझाकरण का समर्थन करता है; साझा एआई क्षमताएँ अगली सक्षम परत बन सकती हैं।
- **प्रवेश बाधाओं को कम करना :** ₹10,371.92 करोड़ के इंडियाएआई मिशन ने रियायती दरों पर 38,000 से अधिक जीपीयू उपलब्ध कराए हैं जिससे स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, एमएसएमई और सार्वजनिक संस्थानों के लिए कंप्यूटिंग लागत कम हो गई है।
- **एआई तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण :** किफायती अनुमान ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, कृषि संबंधी सलाह और व्यक्तिगत शिक्षा में सहायता कर सकता है, जबकि BHASHINI बहुभाषी डिजिटल सेवाओं के लिए साझा AI उपकरणों की क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- **घरेलू मूल्य को बरकरार रखना :** भारत तकनीकी प्रतिभा और डेटा-प्रोसेसिंग क्षमताओं में पर्याप्त योगदान देता है, लेकिन विदेशी कंपनियाँ अग्रणी मॉडलों और एपीआई पर हावी हैं; स्वदेशी मॉडल भारत के भीतर अधिक बौद्धिक व आर्थिक मूल्य बनाए रख सकते हैं।
- **एप्लिकेशन डेवलपर्स को सशक्त बनाना :** साझा कंप्यूटिंग क्षमता, डेटासेट और मूलभूत मॉडल भारतीय डेवलपर्स को महँगे अंतर्निहित एआई बुनियादी ढाँचे में बार-बार निवेश करने के बजाय क्षेत्र-विशिष्ट अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देंगे।
- **तकनीकी संप्रभुता को सुदृढ़ करना :** विदेशी स्वामित्व वाली एपीआई पर निर्भरता भारतीय उपयोगकर्ताओं को बाहरी मूल्य निर्धारण, पहुँच और डेटा-गवर्नेंस निर्णयों के प्रति संवेदनशील बनाती है; एआईकोश व स्वदेशी फाउंडेशन-मॉडल कार्यक्रम इस संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं।

## भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र में चुनौतियाँ

- **आयातित एआई हार्डवेयर पर निर्भरता :** भारत में अभी तक अत्याधुनिक एआई एक्सेलेरेटरों का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता है; यहाँ तक कि इंडियाएआई का साझा-कंप्यूट नेटवर्क भी काफी हद तक आयातित जीपीयू और संबंधित घटकों पर निर्भर करता है।
- **अपर्याप्त ऊर्जा नियोजन :** एआई डेटा केंद्रों को बड़ी, निरंतर एवं भौगोलिक रूप से केंद्रित बिजली और शीतलन क्षमता की आवश्यकता होती है जिसके लिए विशेष ग्रिड योजना, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण व कुशल जल प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
- **विदेशी मॉडल का केंद्रीकरण :** जीपीटी, जेमिनी एवं क्लाउड सहित कई प्रमुख मॉडल व एपीआई विदेशी कंपनियों द्वारा नियंत्रित हैं जिससे भारतीय उपयोगकर्ता बाहरी मूल्य निर्धारण, पहुँच और शासन संबंधी निर्णयों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।




- **प्रतिनिधि डेटासेट की कमी :** कई भारतीय भाषाओं, बोलियों एवं सांस्कृतिक संदर्भों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की कमी बनी हुई है, हालाँकि BHASHINI, प्रोजेक्ट वाणी और AIKosh इन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।
- **महँगी मालिकाना API :** डॉलर में निर्धारित, प्रति टोकन शुल्क भारतीय स्टार्टअप्स के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग को महँगा बना सकते हैं, जबकि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और एकतरफा मूल्य निर्धारण परिवर्तन अतिरिक्त अनिश्चितता पैदा करते हैं।

### भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे के निर्माण खंड

- **भारत एआई मिशन :** वर्ष 2024 में ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत यह परियोजना साझा कंप्यूटिंग, स्वदेशी मॉडल, एआईकोश डेटासेट, अनुप्रयोगों, कौशल, स्टार्टअप और जिम्मेदार एआई का समर्थन करती है।
- **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम :** वर्ष 2015 में शुरू की गई इस परियोजना ने डिजिटल कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं का विस्तार किया है जिससे जनसंख्या-स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढाँचे के लिए संस्थागत आधार तैयार हुआ।
- **आधार-सक्षम डीबीटी :** आधार प्रमाणीकरण और सत्यापित बैंक खाते प्रत्यक्ष कल्याणकारी हस्तांतरण को सुगम बनाते हैं। साथ ही, सरकारों को डुप्लिकेट या अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने और गबन को कम करने में मदद करते हैं।
- **एकीकृत भुगतान इंटरफेस :** यूपीआई अंतरसंचालनीय त्वरित बैंक भुगतान सुविधा प्रदान करता है और जुलाई 2026 में इसने लगभग 23.66 बिलियन लेनदेन संसाधित किए, जिनकी कीमत ₹29.88 लाख करोड़ थी।
- **डिजीलॉकर :** यह सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म नागरिकों को सरकार और अधिकृत संस्थानों द्वारा जारी किए गए प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुँचने, उन्हें संग्रहीत करने, साझा करने और सत्यापित करने में सक्षम बनाता है।
- **डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क :** ONDC विभिन्न अनुप्रयोगों में खरीदारों, विक्रेताओं एवं लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं को जोड़ने के लिए ओपन प्रोटोकॉल का उपयोग करता है जिससे क्लोज्ड ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर निर्भरता कम हो जाती है।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन :** आभा (ABHA) नंबरों, पेशेवर रजिस्ट्रियों और सहमति-आधारित स्वास्थ्य अभिलेखों के माध्यम से ABDM एक अंतरसंचालनीय राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास करता है।

## भारत की एआई टोकन अर्थव्यवस्था के लिए रोडमैप

- **पावर प्लानिंग में कंप्यूट को एकीकृत करना :** राष्ट्रीय विद्युत योजना में एआई डेटा-सेंटर की मांग को शामिल करना; IEA का अनुमान है कि 2025 और 2030 के बीच वैश्विक डेटा-सेंटर बिजली की खपत लगभग दोगुनी हो जाएगी।
- **किफायती सार्वजनिक कंप्यूटिंग का विस्तार करना :** इंडियाएआई कंप्यूट पोर्टल पर आधारित यह सुविधा, योग्य उपयोगकर्ताओं को लगभग ₹65 प्रति घंटे की रियायती दरों पर 38,000 से अधिक जीपीयू तक पहुँच प्रदान करती है।
- **ओपन-वेट मॉडल को बढ़ावा देना :** भारतजेन और एआईकोश जैसी पहलों के बाद सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित एआई मॉडल को गोपनीयता और सुरक्षा उपायों के अधीन, रियूजेबल वेट्स व दस्तावेजीकरण जारी करने की आवश्यकता होगी।
- **एक एकीकृत इंटेलिजेंस इंटरफेस का निर्माण करना :** यूपीआई या एपीआई सेतु के समान एक इंटरऑपरेबल गेटवे बनाना, जो अनुप्रयोगों को सामान्य मानकों के माध्यम से कई सार्वजनिक एवं निजी एआई मॉडल तक पहुँचने में सक्षम बनाए।
- **फ्रीमियम टोकन आवंटन शुरू करना :** पारदर्शी पात्रता मानदंड, उपयोग सीमा और आवधिक ऑडिट का उपयोग करते हुए सत्यापित स्टार्टअप, छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को सीमित मासिक अनुमान क्रेडिट प्रदान करना।
- **भारतीय भाषाओं में नवाचार का समर्थन करना :** BHASHINI, प्रोजेक्ट वाणी और AIKosh का उपयोग करने वाले अनुप्रयोगों के लिए टोकन क्रेडिट आरक्षित करना, विशेष रूप से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा एवं नागरिक सेवा वितरण के क्षेत्र में।
- **वित्त क्षेत्र में एआई कौशल विकास :** आवश्यक कल्याणकारी सब्सिडी को कमजोर किए बिना इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स के माध्यम से सांकेतिक पहुँच के लिए मौजूदा नवाचार, शिक्षा एवं औद्योगिक कौशल विकास बजट का एक हिस्सा आवंटित करना।

## मेडिकल टेक्नोलॉजी में एआई

### संदर्भ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 'मेडिकल टेक्नोलॉजी में एआई : कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में क्रांति' (AI in MedTech: Revolutionizing Healthcare Through Artificial Intelligence) नामक ज्ञान पत्र जारी किया है जिसमें भारत की नैदानिक विविधता और विनिर्माण क्षमता के माध्यम से जिम्मेदार एआई-सक्षम मेडटेक का नेतृत्व करने की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है।

### चिकित्सा प्रौद्योगिकी में एआई की बढ़ती भूमिका

- **मुख्यधारा में नैदानिक स्वीकृति :** एआई नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रक्रियाओं में प्रवेश कर रहा है, एएमए (AMA) सर्वेक्षणों के अनुसार चिकित्सकों द्वारा इसका उपयोग 2023 में 38% से बढ़कर 2026 में 81% हो गया है।
- **चिकित्सा उपकरणों का विस्तार :** जनवरी 2025 तक अमेरिकी एफडीए ने 1,000 से अधिक एआई-सक्षम चिकित्सा उपकरणों को अधिकृत कर दिया, विशेष रूप से रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में।
- **बाजार में तीव्र वृद्धि :** एक उद्योग अनुमान के अनुसार, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा-एआई बाजार 2024 में 26.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 187.7 बिलियन डॉलर हो जाएगा।

### चिकित्सा प्रौद्योगिकी में एआई के अनुप्रयोग

- **निदान एवं मेडिकल इमेजिंग :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तपेदिक, कैंसर, स्ट्रोक, हृदय संबंधी असामान्यताओं और मधुमेह संबंधी

रेटिनोपैथी का पता लगाने में मदद करने के लिए एक्स-रे, सीटी स्कैन, MRIs और रेटिना की छवियों का विश्लेषण करती है।

- **दुर्लभ रोगों का पता लगाना :** फेस2जीन जैसे उपकरण चेहरे की विशेषताओं का विश्लेषण करके संभावित आनुवंशिक सिंड्रोम की पहचान करते हैं जो आनुवंशिक परीक्षण और विशेषज्ञ निदान का समर्थन करते हैं किंतु उनका विकल्प नहीं हैं।
- **पूर्वानुमान आधारित स्वास्थ्य सेवा :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सा इतिहास, महत्त्वपूर्ण संकेतों और प्रयोगशाला परिणामों को मिलाकर सेप्सिस, पुनर्भर्ती और नैदानिक स्थिति में गिरावट जैसे जोखिमों का अनुमान लगाती है।
- **व्यक्तिगत चिकित्सा :** मशीन लर्निंग, उपयुक्त उपचारों व खुराकों के चयन में सहायता के लिए जीनोमिक डेटा, बायोमार्कर, ट्यूमर प्रोफाइल और उपचार प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करती है।
- **नैदानिक निर्णय सहायता :** एआई, दवाइयों की परस्पर क्रियाओं को चिह्नित करने, आगे के परीक्षणों की सिफारिश करने और निदान या रेफरल संबंधी निर्णयों में सहायता करने के लिए नैदानिक नियमों को रोगी डेटा के साथ जोड़ता है।
- **दवा की खोज :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैविक लक्ष्यों और आशाजनक यौगिकों की पहचान करती है जबकि अल्फाफोल्ड के 200 मिलियन से अधिक अनुमानित प्रोटीन संरचनाओं का डेटाबेस जैव चिकित्सा अनुसंधान में सहायता करता है।
- **दस्तावेजीकरण व प्रशासन :** एनएलपी (NLP) नैदानिक नोट्स से जानकारी निकालता है जबकि एआई उपकरण कोडिंग, सारांश, शेड्यूलिंग, दावों के प्रसंस्करण और नैदानिक दस्तावेजीकरण में सहायता करते हैं।




## चिकित्सा प्रौद्योगिकी में एआई की चुनौतियाँ

- **नैदानिक विश्वसनीयता :** रोगी आबादी, रोग के पैटर्न, उपकरण या कार्यप्रवाह में बदलाव के साथ प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है; इसलिए एफडीए साइट-विशिष्ट सत्यापन एवं निरंतर पोस्ट-मार्केट निगरानी पर जोर देता है।
- **प्रशिक्षण डेटा में पूर्वाग्रह :** कुछ आयु वर्ग, लिंग, जातीयता, त्वचा के रंग या स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स के निम्न प्रतिनिधित्व से सटीकता में कमी आ सकती है और असमान नैदानिक परिणाम उत्पन्न हो सकता है।
- **गोपनीयता और डेटा प्रबंधन :** चिकित्सा रिकॉर्ड, जीनोमिक जानकारी और नैदानिक छवियों के लिए सूचित सहमति, उद्देश्य सीमा, एन्क्रिप्शन, पहुँच नियंत्रण एवं अनधिकृत पुनः उपयोग से सुरक्षा आवश्यक है।
- **स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एकीकरण :** असंगत डेटा प्रारूप और पुरानी ईएचआर (EHR) प्रणालियाँ कार्यप्रवाह को बाधित कर सकती हैं; एचएल7 एफएचआईआर (HL7 FHIR) जैसे मानक अंतरसंचालनीय स्वास्थ्य सूचना विनिमय का समर्थन करते हैं।
- **रोगी एवं चिकित्सक का विश्वास :** अस्पष्ट रूप से समझाई गई सिफारिशें अस्वीकृति या अत्यधिक निर्भरता का कारण बन सकती हैं, जिसके लिए इच्छित उपयोग, प्रदर्शन सीमाओं और सार्थक मानवीय पर्यवेक्षण का खुलासा करना आवश्यक है।
- **दायित्व और जवाबदेही:** जब एआई की सिफारिश या सॉफ्टवेयर अपडेट से मरीज को नुकसान पहुँचता है, तो डेवलपर्स, निर्माताओं, अस्पतालों व चिकित्सकों के बीच जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं हो सकती है।
- **नियामक एवं अपनाने संबंधी बाधाएँ :** नैदानिक साक्ष्य, साइबर सुरक्षा, अनुमोदन, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और वित्तीय व्यवहार्यता आवश्यक बनी हुई हैं; यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम चिकित्सा उद्देश्यों के लिए एआई प्रणालियों को उच्च जोखिम वाली मानता है।

## भारतीय परिप्रेक्ष्य में आगे की राह

- **एआई का उपयोग चुनिंदा रूप से करना :** स्थानीय स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं के अनुसार निदान में देरी को कम करने, नैदानिक निर्णयों में सुधार करने या पहुँच को व्यापक बनाने वाले आवेदनों को प्राथमिकता देना।
- **परस्परसंचालनीय प्रणालियाँ बनाना :** सुरक्षित स्वास्थ्य सूचना आदान-प्रदान के लिए FHIR मानकों का उपयोग करते हुए मान्य AI उपकरणों को EHRs एवं ABDM प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करना।
- **समावेशी अनुकूलन सुनिश्चित करना :** वंचित एवं बहुभाषी समुदायों का समर्थन करने के लिए एआई टूल को ई-संजीवनी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और भाषिनी से जोड़ना।

### स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के लिए WHO के छह मूल सिद्धांत

- **मानव स्वायत्तता की रक्षा करना :** स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और चिकित्सा संबंधी निर्णयों पर मनुष्यों का नियंत्रण बना रहना चाहिए, साथ ही निजता, गोपनीयता और सूचित सहमति पूरी तरह से सुरक्षित रहनी चाहिए।
- **स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुरक्षा, सटीकता और प्रभावशीलता के मानकों को पूरा करना होगा, जो गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरंतर सुधार तंत्र द्वारा समर्थित हों।
- **पारदर्शिता एवं स्पष्टता सुनिश्चित करना :** किसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली के डिजाइन और तैनाती के बारे में जानकारी उपयोग से पहले उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे सूचित परामर्श व सार्वजनिक बहस संभव हो सके।
- **जिम्मेदारी एवं जवाबदेही को बढ़ावा देना :** एआई का उपयोग प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा उचित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जिसमें समीक्षा, जिम्मेदारी एवं निवारण के लिए स्पष्ट तंत्र मौजूद हों।
- **समावेशिता और समानता सुनिश्चित करना :** एआई को आयु, लिंग, आय, नस्ल, जातीयता, विकलांगता या अन्य संरक्षित विशेषताओं की परवाह किए बिना समान पहुँच को बढ़ावा देना चाहिए।
- **उत्तरदायी और टिकाऊ बने रहना :** एआई सिस्टम के लिए निरंतर वास्तविक दुनिया का मूल्यांकन, पर्यावरण पर कम प्रभाव और तकनीकी बदलाव के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त तैयारी आवश्यक है।

### *स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के लिए ICMR की चार प्राथमिकताएँ*

- **गुणवत्तापूर्ण डेटा संकलित करना :** प्रतिनिधि एआई विकास, सत्यापन और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करने के लिए अनुसंधान संस्थानों में विश्वसनीय स्वास्थ्य डेटासेट को मानकीकृत और संयोजित करना।
- **निजी क्षेत्र में साझेदारियाँ विकसित करना :** अस्पतालों, मेडटेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ सहयोग करके उचित जनहित सुरक्षा उपायों के तहत अनुसंधान को स्केलेबल एआई टूल्स में परिवर्तित करना।
- **वास्तविक दुनिया के साक्ष्य उत्पन्न करना :** व्यापक तैनाती से पहले विभिन्न आबादी, बीमारियों और स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में एआई प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए ICMR के संस्थानों के नेटवर्क का उपयोग करना।
- **अंत:विषयक कार्यबल विकसित करना :** डेटा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं बायोमेडिकल शोधकर्ताओं के साथ-साथ डॉक्टरों, नर्सों व सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों को भी एआई प्रशिक्षण में एकीकृत करना।

## प्रारंभिक परीक्षा

### सामान्य विज्ञान

## बोरोफेन-आधारित हरित स्नेहक

### संदर्भ

गुवाहाटी स्थित IASST के शोधकर्ताओं ने अरंडी के तेल आधारित स्नेहक में उच्च-प्रदर्शन योजक के रूप में बोरोफेन के पहले उपयोग का प्रदर्शन किया है।

### बोरोफेन के बारे में

- बोरोफेन एक द्वि-आयामी नैनोमैटेरियल है जो पूरी तरह से बोरॉन परमाणुओं से बना होता है।
- इसमें उच्च यांत्रिक शक्ति, विद्युत चालकता और रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता होती है।
- इसके संभावित अनुप्रयोगों में बैटरी, सुपरकैपेसिटर, ईंधन सेल और उन्नत स्नेहन प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

### शोध के मुख्य निष्कर्ष

- अरंडी का तेल नवीकरणीय और जैवअपघटनीय होता है किंतु इसके स्नेहन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त योजक पदार्थों की आवश्यकता होती है।
  - घर्षण एवं टूट-फूट को कम करने से औद्योगिक ऊर्जा हानि को कम किया जा सकता है और उपकरणों की समय से पहले विफलता को रोका जा सकता है।
- वजन के हिसाब से केवल 0.1% बोरोफेन मिलाने से अरंडी के तेल का औसत घर्षण गुणांक लगभग 42% तक कम हो गया।
  - शुद्ध अरंडी के तेल की तुलना में घर्षण गुणांक 0.059 से घटकर 0.034 हो गया।
- बोरोफेन बिना रासायनिक संशोधन की आवश्यकता के अरंडी के तेल में समान रूप से फैल गया।
  - संचालन के दौरान इसने लौह ऑक्साइड, कार्बनयुक्त अवशेषों एवं बोरॉन-आधारित यौगिकों से युक्त एक सुरक्षात्मक ट्राइबोफिल्म का निर्माण किया।
  - इस फिल्म ने अपरूपण तनाव को कम किया, भार वहन क्षमता में सुधार किया और सतह के घिसाव को न्यूनतम किया।

## ग्लूबॉल और X(2370)

### संदर्भ

BESIII कोलैबोरेशन ने इस बात के पुख्ता सबूत पेश किए हैं कि X(2370) में एक प्रमुख ग्लूबॉल घटक मौजूद है जो इसे लंबे समय से प्रत्याशित कण (Long-predicted Particle) के लिए एक अग्रणी उम्मीदवार बनाता है।

### प्रबल बल और ग्लूऑन के बारे में

- प्रबल बल चार मूलभूत बलों में से एक है और इसका वर्णन क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स (QCD) द्वारा किया जाता है।
  - यह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं अन्य हैड्रॉन के अंदर क्वार्कों को एक साथ बाँधता है।
  - इसकी अवशिष्ट अंत:क्रिया परमाणु नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाँधने में भी मदद करती है।
- प्रबल बल ग्लूऑन नामक कणों द्वारा मध्यस्थ होता है।
  - फोटॉनों के विपरीत, ग्लूऑन रंगीन आवेश वहन करते हैं और इसलिए एक-दूसरे के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं।
  - यह स्व-अंत:क्रिया ग्लूऑन को वैलेंस क्वार्क के बिना मिश्रित कण बनाने की अनुमति देती है।

### ग्लूबॉल के बारे में

- ग्लूबॉल अल्पकालिक, रंगहीन मिश्रित कण होते हैं जो मुख्य रूप से बँधे हुए ग्लूऑन से बने होते हैं।
  - ये पारंपरिक मेसॉन से भिन्न होते हैं जिनमें मुख्य रूप से क्वार्क-एंटीक्वार्क युग्म होता है।
- ग्लूबॉल की पहचान करना मुश्किल होता है क्योंकि ये तेजी से हल्के कणों में विघटित हो जाते हैं।
  - ये समान क्वांटम गुणों वाले सामान्य हैड्रॉन के साथ भी मिल सकते हैं, जिससे उनकी ग्लूओनिक पहचान अस्पष्ट हो जाती है।

### X(2370) से साक्ष्य

- X(2370) कण को पहली बार 2011 में विकिरणशील J/ψ मेसोन क्षय में BESIII द्वारा देखा गया था।
  - इस प्रकार के क्षय से ग्लूऑन से भरपूर वातावरण प्राप्त होता है जो ग्लूबॉल की खोज के लिए उपयुक्त होता है।
- बाद के विश्लेषण से इसके स्पिन-पैरिटी क्वांटम संख्या $0^{-+}$ निर्धारित हुई, जो एक स्यूडोस्केलर ग्लूबॉल के अनुरूप है।
  - इसका लगभग 2.37 GeV का द्रव्यमान भी लैटिस-क्यूसीडी भविष्यवाणियों के अनुरूप है।
- लगभग 10 बिलियन J/ψ घटनाओं के विश्लेषण में (K^*(892)\ bar K) में अवरोधक क्षय पाया गया, जो दर्शाता है कि X(2370) एक फ्लेवर-सिंग्लेट अवस्था है।
  - इसका द्रव्यमान, क्वांटम संख्या, उत्पादन दर और क्षय पैटर्न सामूहिक रूप से वैकल्पिक स्पष्टीकरणों की तुलना में एक प्रमुख ग्लूबॉल घटक का समर्थन करते हैं।

## अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

## फाल्कन 9

### संदर्भ

स्पेसएक्स फाल्कन 9 का एक परित्यक्त ऊपरी चरण 5 अगस्त, 2026 को चंद्रमा से टकरा गया, जिससे एक नया क्रेटर बन गया और चंद्र का पदार्थ बाहर निकल आया।

### लूनर इम्पैक्ट के बारे में

- 15 जनवरी, 2025 को फायरफ्लाई एयरोस्पेस के 'ब्लू घोस्ट 1' और आईस्पेस (ispace) के 'रेजिलिएंस' लूनर लैंडर्स को लेकर ऊपरी स्टेज को लॉन्च किया गया।
  - लैंडर्स को तैनात करने के बाद यह लगभग 19 महीनों तक एक अनियंत्रित उच्च-पृथ्वी कक्षा में बना रहा।
  - सौर गतिविधि और गुरुत्वाकर्षण बलों ने धीरे-धीरे इसे चंद्रमा की ओर मोड़ दिया।
- यह यंत्र लगभग 5,400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आइंस्टीन क्रेटर के पास टकराया।
  - इससे लगभग 18 मीटर चौड़ा और 3 मीटर से कम गहरा एक गड्ढा बन गया।
  - इस टक्कर के कारण चंद्रमा की धूल एवं चट्टानें बाहर निकलीं, जिससे चमकीले और गहरे रंग के विपरीत पैटर्न बने।
- दक्षिण कोरिया के डानूरी ऑर्बिटर ने सबसे पहले इस स्थल की तस्वीर ली, जिसके बाद नासा के लूनर रिकॉनसेंस ऑर्बिटर ने भी तस्वीरें लीं।
  - LRO ने 11 से 12 अगस्त, 2026 के बीच विस्तृत तस्वीरें लीं।
- कृत्रिम प्रभाव से वैज्ञानिकों को चंद्र क्रेटर निर्माण, उपसतह सामग्री और अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने की तकनीकों का अध्ययन करने में मदद मिल सकती है।

### स्पेसएक्स के बारे में

- स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन को सामान्यतया स्पेसएक्स के नाम से जानते हैं। यह एक अमेरिकी निजी एयरोस्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना एलॉन मस्क ने 2002 में की थी।
- यह प्रक्षेपण लागत को कम करने और अंतरिक्ष तक पहुँच का विस्तार करने के लिए प्रक्षेपण यान, अंतरिक्ष यान और उपग्रह प्रणालियों का विकास करता है।
- इसके प्रमुख सिस्टमों में फाल्कन 9, फाल्कन हेवी, स्टारशिप, ड्रैगन एवं स्टारलिंक उपग्रह समूह शामिल हैं।

### फाल्कन 9 के बारे में

- फाल्कन 9 एक आंशिक रूप से पुन: प्रयोज्य, द्वि-चरणीय कक्षीय रॉकेट है, जिसे स्पेसएक्स द्वारा विकसित किया गया है और इसे पहली बार 2010 में लॉन्च किया गया था।
  - इसके पहले चरण में नौ मर्लिन इंजन लगे हैं और इसे पुन: उपयोग के लिए लैंड किया जा सकता है।
  - इसका एक्स्पेंडेबल ऊपरी चरण पेलोड को उनके इच्छित प्रक्षेप पथ में स्थापित करने के लिए मर्लिन वैक्यूम इंजन का उपयोग करता है।

- यह उपग्रहों, ड्रैगन अंतरिक्ष यानों और अन्य पेलोड को निम्न-पृथ्वी कक्षा, भू-स्थिर स्थानांतरण कक्षा और अंतरग्रहीय प्रक्षेप पथों में प्रक्षेपित करता है।
- इसके प्रथम चरण के बूस्टर का पुन: उपयोग करने से प्रक्षेपण लागत कम हो गई है और अंतरिक्ष अभियानों की उच्च आवृत्ति संभव हो पाई है।

## एवरेस्ट रॉकेट इंजन

### संदर्भ

बेंगलुरु स्थित एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित 800 kN फुल-फ्लो स्टेजेड कंबशन LOX-मीथेन इंजन 'एवरेस्ट' (EVEREST) का अनावरण किया।



### एवरेस्ट के बारे में

- एवरेस्ट एक 80 टन श्रेणी का तरल रॉकेट इंजन है जिसे पुन: प्रयोज्य मध्यम-लिफ्ट प्रक्षेपण यानों के लिए डिजाइन किया गया है।
  - यह 800 kN का वैक्यूम थ्रस्ट उत्पन्न करता है, लगभग 340 सेकंड का विशिष्ट आवेग प्रदान करता है और 50%-110% थ्रॉटलिंग का समर्थन करता है।
  - व्यापक थ्रॉटलिंग से आरोहण (Ascent), अवरोहण (Desecnt) और पुन: प्रयोज्य वाहन की रिकवरी के दौरान सटीक थ्रस्ट नियंत्रण संभव हो पाता है।
- यह इंजन ऑक्सीकारक के रूप में तरल ऑक्सीजन और ईंधन के रूप में तरल मीथेन का उपयोग करता है जिन्हें सामूहिक रूप से मेथालॉक्स कहा जाता है।
  - मीथेन केरोसिन की तुलना में अधिक स्वच्छ रूप से जलती है और कम कालिख पैदा करती है, जिससे निरीक्षण व मरम्मत की आवश्यकताएँ कम हो जाती हैं।
  - कोर इंजन के पुर्जे उन्नत मेटल 3डी प्रिंटिंग का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं।

### फुल-फ्लो स्टेज्ड दहन (FFSC) प्रौद्योगिकी के बारे में

- FFSC इंजन में ईंधन एवं ऑक्सीडाइजर का पूरा प्रवाह दहन से पहले अलग-अलग प्री-बर्नर एवं टर्बोपंप से होकर गुजरता है।
  - ईंधन से भरपूर और ऑक्सीकारक से भरपूर गैसें अपने-अपने टर्बोपंपों को चलाती हैं।
  - इसके बाद दोनों गैस स्ट्रीम्स मुख्य दहन कक्ष में प्रवेश करती हैं जिससे प्रणोदक का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित होता है।
- यह प्रणाली उच्च चैम्बर दबाव, अधिक दक्षता एवं टरबाइन घटकों पर कम ऊष्मीय तनाव का समर्थन करती है।
  - इसकी दक्षता और स्वच्छ मेथालॉक्स दहन इसे बार-बार उड़ान चक्रों के लिए उपयुक्त बनाता है।

### पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण प्रणाली के बारे में

- एस्ट्रोबेस, एवरेस्ट इंजन द्वारा संचालित द्वि-चरणीय पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान विकसित कर रहा है।
  - इसके पहले चरण के लिए 'रिटर्न-टू-लॉन्च-साइट रिकवरी' का उपयोग करने की योजना है।
  - कंपनी के मौजूदा वाहन आर्किटेक्चर में 200 किलोमीटर की निम्न-पृथ्वी कक्षा में 8 टन भार ले जाने की क्षमता बताई गई है।

## रक्षा प्रौद्योगिकी

## आईएनएस मालवन

### संदर्भ

भारतीय नौसेना ने 22 जुलाई, 2026 को कारवार में माहे श्रेणी की दूसरी एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट 'आईएनएस मालवन' को शामिल किया।

### आईएनएस मालवन के बारे में

- आईएनएस मालवन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि द्वारा निर्मित किए जा रहे माहे-श्रेणी के आठ पोत में से दूसरा है।
  - यह भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले 16 एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी (ASW-SWCs) में से छठा है।
  - इस पोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है।
- इसका नाम महाराष्ट्र के तटीय शहर मालवन के नाम पर रखा गया है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत से जुड़ा हुआ है।
  - यह 2003 में सेवामुक्त किए गए भारतीय नौसेना के एक पुराने तटीय माइनस्वीपर की विरासत को आगे बढ़ाता है।
  - इसके प्रतीक चिह्न में बाघ नख अंकित है जबकि इसका आदर्श वाक्य 'साइलेंट क्लाव्स' है।
- यह पोत उथले तटीय जल में पानी के नीचे के खतरों का पता लगा सकता है, उनका पीछा कर सकता है और उनसे निपट सकता है।

### माहे श्रेणी के बारे में

- माहे श्रेणी के पोत तटीय जलक्षेत्र में पनडुब्बी रोधी और निगरानी अभियानों के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हैं।
  - ये भारतीय नौसेना के अभय श्रेणी के एंटी-वेस्ट कॉर्वेट्स की जगह लेंगे।
  - इनमें जलमग्न निगरानी के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सोनार यंत्र लगे हुए हैं।
- प्रत्येक पोत लगभग 78 मीटर लंबा है और इसका वजन लगभग 896 टन है।
  - यह अधिकतम 25 समुद्री मील की गति प्राप्त कर सकता है और इसकी सहनशक्ति लगभग 1,800 समुद्री मील है।
  - इस श्रेणी के विमान डीजल इंजन-वाटरजेट प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करते हैं।

## कुशा मिसाइल

### संदर्भ

डीआरडीओ (DRDO) ने 23 जुलाई, 2026 को ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कुशा लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LR-SAM) का पहला उड़ान परीक्षण किया।

### प्रोजेक्ट कुशा के बारे में

- प्रोजेक्ट कुशा एक स्वदेशी, लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जिसे डीआरडीओ भारतीय उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर विकसित कर रहा है।
- यह एक पूरी तरह से स्वचालित एवं स्केलेबल सिस्टम है जिसे विभिन्न दूरी व ऊँचाइयों पर हवाई खतरों का पता लगाने, निगरानी करने और उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसकी हथियार प्रणाली में इंटरसेप्टर मिसाइलें, लंबी दूरी के रडार, कमान एवं नियंत्रण केंद्र व स्वचालित युद्ध-प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं।
- यह लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों, मानवरहित हवाई वाहनों और बड़े निगरानी या सहायक विमानों का मुकाबला कर सकता है।
- इसके कथित डिजाइन में AESA रडार, सटीक खोजकर्ता, हिट-टू-किल क्षमता और प्रॉक्सिमिटी-फ्यूज इंटरसेप्शन शामिल हैं।
- इसकी तुलना प्रायः रूस के S-400 से की जाती है किंतु इसका उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के रूप में काम करने के बजाय भारत की मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों का पूरक बनना है।
- इस प्रणाली को एक लेयर्ड एंगेजमेंट एनवेलप (स्तरित संलयन आवरण) बनाने के लिए तीन इंटरसेप्टर के साथ योजनाबद्ध किया गया है :
  - M1 की अनुमानित रेंज 150 किमी. तक है।
  - M2 की अनुमानित रेंज 250 किमी. तक है।
  - M3 की अनुमानित रेंज लगभग 350 किमी. तक है।
- मिसाइल ने उच्च गति एवं उच्च ऊँचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक अवरुद्ध कर दिया।

## अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल

### संदर्भ

भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया और इसके सभी परिचालन एवं तकनीकी मापदंडों को सत्यापित किया।

### अग्नि-4 के बारे में

- अग्नि-4 भारत की अग्नि शृंखला की स्वदेशी रूप से विकसित, परमाणु-सक्षम, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
- डीआरडीओ द्वारा विकसित यह लगभग 20 मीटर लंबी है और इसकी मारक क्षमता लगभग 4,000 किलोमीटर है।
- यह लगभग 1,000 किलोग्राम का भार ले जा सकता है और द्वि-चरणीय ठोस-प्रणोदक प्रणाली का उपयोग करता है।
- इसका रोड-मोबाइल लॉन्चर तैनाती में लचीलापन व उत्तरजीविता बढ़ाता है।
- उन्नत विमानन प्रणाली, ऑनबोर्ड कंप्यूटर और जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली सटीकता एवं उड़ान में स्थिरता प्रदान करते हैं।
- इसमें रिंग लेजर जाइरो-आधारित नेविगेशन सिस्टम और एक मिश्रित रॉकेट मोटर शामिल है।
- यह परीक्षण सामरिक बल कमान द्वारा किया गया, जो भारत के सामरिक परमाणु बलों का प्रबंधन करती है।
- इस सफल प्रक्षेपण ने परिचालन विश्वसनीयता की पुष्टि की और भारत की विश्वसनीय रणनीतिक-प्रतिरोध क्षमता को मजबूत किया।

# स्वास्थ्य एवं रोग

## क्यूडेंगा

### संदर्भ

भारत ने दो दशकों में दर्ज किए गए डेंगू के मामलों में ग्यारह गुना वृद्धि के बीच अपने पहले डेंगू के टीके को मंजूरी दी।

### क्यूडेंगा के बारे में

- क्यूडेंगा (TAK-003) जापानी दवा कंपनी ताकेडा द्वारा विकसित एक टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन है।
- इसका निर्माण जर्मनी की ताकेडा GmbH द्वारा किया जाता है और इसे ताकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा आयात किया जाता है।
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इसकी गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के बाद विपणन प्राधिकरण प्रदान किया।

- यह मंजूरी औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 के तहत प्रदान की गई थी।
- यह एक पुनर्योजी, जीवित-क्षीणित एवं चतुर्संयोजक टीका है जो DENV-1, DENV-2, DENV-3 और DENV-4 को कवर करता है।
- 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति इसे ले सकते हैं, चाहे उन्हें पहले डेंगू का संक्रमण हुआ हो या नहीं।
- कुछ पहले के टीकों के विपरीत इसके लिए टीकाकरण से पहले रक्त परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है जिससे इसका प्रदान करना सरल हो जाता है।
- क्यूडेंगा को विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्री-क्वालिफिकेशन प्राप्त है, 40 से अधिक देशों में इसे मंजूरी मिल चुकी है और इसकी 32 मिलियन से अधिक खुराकें वितरित की जा चुकी हैं।

### डेंगू के बारे में

- डेंगू मच्छरों से फैलने वाला एक वायरल रोग है जो फ्लेवीवायरस जीनस के चार सीरोटाइप के कारण होता है।
- यह मुख्य रूप से संक्रमित मादा एडीज एजिप्टी मच्छरों द्वारा फैलता है।
- यही मच्छर चिकनगुनिया, पीत ज्वर व जीका वायरस के प्रसार का भी कारण है।
- इसके लक्षणों में तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द, आँखों के पीछे दर्द और मांसपेशियों एवं जोड़ों में तीव्र दर्द शामिल हैं।
- विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 39 करोड़ संक्रमण के मामले होते हैं जिनमें लगभग 9.6 करोड़ लक्षण युक्त मामले शामिल हैं।

## चाँदीपुरा वायरस

### संदर्भ

रिपोर्टिंग के समय गुजरात एवं राजस्थान में चाँदीपुरा वायरस (CHPV) से नौ मौतों की पुष्टि हुई थी, जिनमें राजस्थान की दो लड़कियाँ भी शामिल थीं।

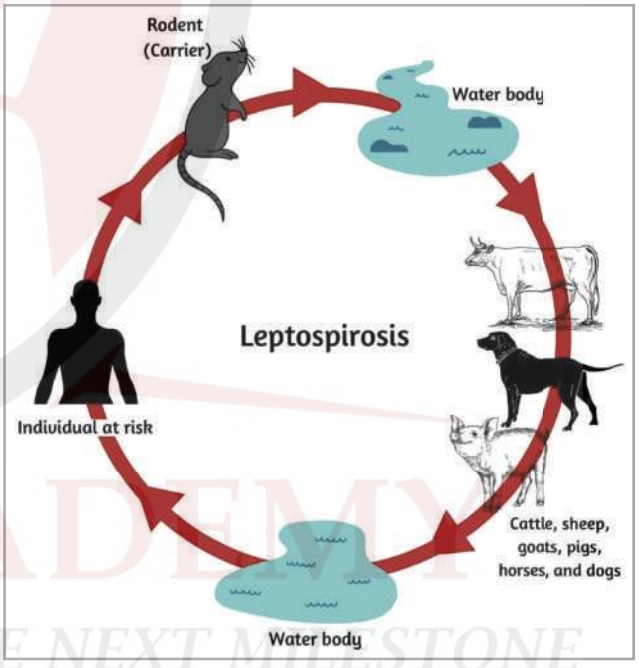
### चाँदीपुरा वायरस के बारे में

- CHPV एक वेक्टर-जनित वायरस है जो रैबडोविरिडे कुल से संबंधित है जिसमें रेबीज पैदा करने वाला लिसावायरस (Lyssavirus) भी शामिल है।
- इसके कारण एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES) होता है जिसमें मस्तिष्क के ऊतकों में तेजी से और संभावित रूप से घातक सूजन हो जाती है।
- इस वायरस को सबसे पहले 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गाँव में आइसोलेट किया गया था।
- वर्ष 2003-04 के दौरान आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में बड़े पैमाने पर प्रकोप का प्रसार हुआ, जिनमें मृत्यु दर काफी अधिक दर्ज की गई।
- CHPV मुख्य रूप से पश्चिमी, मध्य एवं दक्षिणी भारत में, विशेष रूप से ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में पाया जाता है।
- CHPV मुख्य रूप से संक्रमित फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाई, विशेष रूप से फ्लेबोटोमस पापाटासी द्वारा फैलता है।
  - मच्छर एवं टिक्स भी वायरस का संचरण कर सकते हैं जबकि मानव-से-मानव संचरण की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।
- यह बीमारी मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करती है और मानसून के मौसम में इसके मामले चरम पर होते हैं।
- अस्पताल में भर्ती होने के 24-48 घंटों के भीतर मृत्यु हो सकती है, इसलिए शीघ्र चिकित्सा हस्तक्षेप अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- CHPV के खिलाफ फिलहाल कोई भी स्वीकृत एंटीवायरल दवा या निवारक टीका उपलब्ध नहीं है।

## लेप्टोस्पाइरोसिस

### संदर्भ

केरल में 1989 से रिपोर्ट की जा रही लेप्टोस्पाइरोसिस एक स्थानिक बीमारी बन गई है और राज्य में संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु दर में सबसे अधिक इसी बीमारी का रिकॉर्ड है।




### लेप्टोस्पाइरोसिस के बारे में

- लेप्टोस्पाइरोसिस एक जीवाणुजनित रोग है जो मनुष्यों एवं जानवरों दोनों को प्रभावित करता है।
- यह लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया के कारण होता है जो दूषित पानी, मृदा एवं कीचड़ में पनपते हैं।
- यह बीमारी उच्च आर्द्रता व भारी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य है।

YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

- बाढ़ से पशुओं के मूत्र से दूषित पानी के मानव बस्तियों में फैलने के कारण संक्रमण बढ़ जाता है।
- संक्रमित पशु के मूत्र से दूषित पानी, मिट्टी या भोजन के संपर्क में आने से संक्रमण होता है।
- संक्रमित जानवर के मूत्र या शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से भी यह रोग फैल सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका संक्रमण दुर्लभ है।
- आउटडोर कार्यों में संलग्न कर्मचारी, पशुओं की देखभाल करने वाले, बागवानी एवं बाढ़ के पानी या दूषित ताजे पानी में प्रवेश करने वाले लोगों को अधिक खतरा होता है।
- अनुपचारित संक्रमण से गुर्दे की क्षति, मेनिन्जाइटिस, लीवर फेलियर, श्वसन संकट एवं मृत्यु हो सकती है।
- मामूली संक्रमणों का उपचार डॉक्सीसाइक्लिन या पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है।

## जैव-प्रौद्योगिकी

### रेगन एवं प्रोटीन भाषा मॉडल

#### संदर्भ

ड्यूक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने रेगन (Raygun) नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकसित की है जो प्रोटीन को छोटा करने, बड़ा करने एवं व्यापक रूप से पुनर्रचना करने में सक्षम है। यह अध्ययन नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ।

#### प्रोटीन भाषा मॉडल के बारे में

- प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल (pLM) प्रोटीन की संरचना और कार्य को समझने के लिए अमीनो-एसिड अनुक्रमों का अध्ययन करता है।
- यह अमीनो एसिड को शब्दों के रूप में और संपूर्ण प्रोटीन अनुक्रम को एक वाक्य के रूप में मानता है।
- लाखों अनुक्रमों का विश्लेषण करके pLM प्रोटीन को नियंत्रित करने वाले अंतर्निहित जैविक व्याकरण को सीखते हैं।
- ये लुप्त अमीनो एसिड की भविष्यवाणी करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भाषा मॉडल किसी लुप्त या आगामी शब्द की भविष्यवाणी करते हैं।
- सीखे गए पैटर्न प्रोटीन अनुक्रमों को उनकी त्रि-आयामी संरचनाओं और जैविक कार्यों से जोड़ते हैं।
- ये पैटर्न स्थापित जैविक नियमों को स्पष्ट रूप से सिखाए बिना ही स्वतः ही खोजे जाते हैं।

#### रेगन के बारे में

- रेगन, पीएलएम पर आधारित होकर छोटे, लंबे या व्यापक रूप से संशोधित प्रोटीन बनाता है।
- यह महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विशेषताओं को संरक्षित रखते हुए मौजूदा प्रोटीनों को नया रूप देता है।
- रेगन प्रोटीन को 10-25% तक और कभी-कभी 50% से भी अधिक तक सिकोड़ सकता है।
- यह प्रणाली जैविक अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी और लक्षित दवाओं के लिए अनुकूलित प्रोटीन का समर्थन कर सकती है।

#### प्रोटीन भाषा मॉडल के अनुप्रयोग

- pLM प्रोटीन की संरचना, स्थिरता, बंधन क्षमता और कोशिकीय कार्यों की भविष्यवाणी करते हैं जिससे उत्परिवर्तन की व्याख्या करने में मदद मिलती है।
- ये चिकित्सीय प्रोटीन विकसित करने के अलावा प्लास्टिक के अपघटन और जैव ईंधन उत्पादन के लिए एंजाइम डिजाइन करते हैं।
- चिकित्सा के क्षेत्र में ये दवाओं की खोज को गति देते हैं और यह समझाते हैं कि आनुवंशिक भिन्नताएँ प्रोटीन के कार्यों को किस प्रकार बदलती हैं।
- जैव प्रौद्योगिकी में ये बेहतर एंजाइम, टिकाऊ सामग्री, नैदानिक उपकरण एवं औद्योगिक विनिर्माण में सहयोग करते हैं।

### नॉन-मेंडेलियन एपिजेनेटिक वंशागति

#### संदर्भ

नेचर जेनेटिक्स में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि कुछ डीएनए मेथाइलेशन पैटर्न अंतर्निहित डीएनए अनुक्रम को बदले बिना चूहों की पीढ़ियों में स्थानांतरित हो सकते हैं।

#### मुख्य निष्कर्ष

- शोधकर्ताओं ने लगभग 7,600 जीनोमिक क्षेत्रों का अध्ययन किया और पाया कि उनमें से लगभग 93% मेंडेलियन वंशानुक्रम का पालन करते हैं।
- लगभग 7%, जो कम से कम 522 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने गैर-मेंडेलियन एपिजेनेटिक वंशानुक्रम दिखाया।
- परिणाम बताते हैं कि वंशानुगत जैविक जानकारी डीएनए अनुक्रम से आगे भी विस्तारित हो सकती है।
- शोधकर्ताओं ने 305 लिंग-विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की, ये सभी यकृत ऊतक में पाए गए और लगभग सभी महिलाओं में अधिक मिथाइलेटेड थे।
- पूर्व में अज्ञात कम से कम पाँच जीनों ने जनक-उत्पत्ति-विशिष्ट जीनोमिक इमप्रिंटिंग प्रदर्शित की।
- कैपन11 जीन में प्राकृतिक अंतरपीढ़ीगत पैरामुटेशन की पुष्टि की गई, जो वृषण अर्धसूत्री विभाजन और प्रजनन क्षमता से संबंधित है।
- पैरामुटेशन के दो अतिरिक्त संभावित मामलों में इंट्रासिस्टर्नल A कण (IAPs) शामिल थे, जो अंतर्जात रेट्रोवायरल तत्त्व हैं।
- IAPs सामान्य जनन-कोशिका विसंक्रमण का प्रतिरोध कर सकते हैं जिससे एपिजेनेटिक चिह्न पीढ़ियों तक बने रह सकते हैं।

### एपिजेनेटिक्स और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में

- एपिजेनेटिक्स जीन अभिव्यक्ति में होने वाले वंशानुगत परिवर्तनों का अध्ययन करता है जो डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन के बिना होते हैं।
- एपीजीनोम कोशिकीय सॉफ्टवेयर की तरह कार्य करता है जो यह निर्धारित करता है कि कौन से जीन सक्रिय होंगे या निष्क्रिय होंगे।
- आनुवंशिक भिन्नताएँ आनुवंशिक रूप से समान यकृत, मस्तिष्क और मांसपेशी कोशिकाओं को अलग-अलग कार्य करने में सक्षम बनाती हैं।
- आहार, तनाव, बढ़ती उम्र, व्यायाम एवं विषाक्त पदार्थ एपिजेनेटिक मार्करों को संशोधित कर सकते हैं और जैविक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।
- डीएनए मेथाइलेशन साइटोसिन बेस में मिथाइल समूह जोड़ता है जिससे प्रायः प्रमोटरों के पास जीन प्रतिलेखन कम हो जाता है।
- हिस्टोन संशोधन डीएनए की पैकिंग को नियंत्रित करना; कसकर पैक किया गया क्रोमेटिन जीन को निष्क्रिय कर देता है, जबकि ढीला क्रोमेटिन प्रतिलेखन को सक्षम बनाता है।
- हिस्टोन मॉडिफिकेशन DNA की पैकिंग को कंट्रोल करते हैं; टाइट पैक क्रोमैटिन जीन्स को साइलेंस (निष्क्रिय) कर देता है, जबकि लूज क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन को संभव बनाता है।
- नॉन-कोडिंग, आरएनए कोडिंग आरएनए के साथ परस्पर क्रिया करके और प्रोटीन उत्पादन को रोककर जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करता है।

## सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

### बिटचैट टेकडाउन

#### संदर्भ

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने जनव्यवस्था और निगरानी संबंधी चिंताओं के मद्देनज़र GitHub को BitChat रिपॉजिटरी हटाने का निर्देश दिया।

#### BitChat और GitHub के बारे में

- जैक डोर्सी द्वारा विकसित बिटचैट, इंटरनेट, सर्वर, सिम कार्ड या फोन नंबर के बिना ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग का उपयोग करता है।
- प्रत्येक डिवाइस क्लाइंट एवं सर्वर दोनों के रूप में कार्य करता है और पीयर-टू-पीयर कनेक्शन के माध्यम से संदेशों को रिले करता है।
- यह इंटरनेट बंद होने, आपदाओं एवं कम कनेक्टिविटी की स्थितियों के दौरान संचार में सहायता करता है।
- GitHub कोड रिपॉजिटरी, वर्जन कंट्रोल और सहयोगी सॉफ्टवेयर-विकास उपकरण प्रदान करता है।
- ओपन-सोर्स रिपॉजिटरी को हटाने से इंस्टॉल किए गए एप्लिकेशन निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं या बाद में कोड के पुनर्वितरण को रोका नहीं जा सकता है।

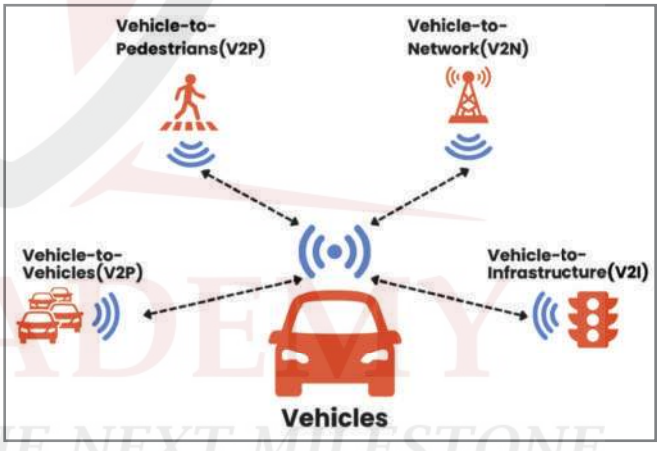
#### कानूनी और संवैधानिक मुद्दे

- आई4सी ने आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) और आईटी नियम, 2021 के नियम 3(1)(d) का हवाला दिया।
- सरकार का तर्क है कि बिटचैट कानूनी रूप से डेटा को इंटरसेप्ट करने और उपयोगकर्ताओं की पहचान करने में बाधा डालता है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था को संभावित खतरा हो सकता है।
- आलोचकों का कहना है कि धारा 79 मध्यस्थों के लिए सुरक्षित आश्रय से संबंधित है जबकि अवरोधन प्रायः धारा 69A के तहत होता है।
- श्रेया सिंघल वाद में मध्यस्थों द्वारा डेटा हटाने के लिए अदालत के आदेश या वैध सरकारी निर्देश की आवश्यकता होती है।
- अनुराधा भसीन वाद का हवाला देते हुए इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने मांग की कि प्रतिबंध आवश्यकता, आनुपातिकता एवं सीमित अवधि के अनुरूप हों।

### व्हीकल-टू-व्हीकल संचार

#### संदर्भ

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) संचार कार्यान्वयन का प्रस्ताव रखा।




#### व्हीकल-टू-व्हीकल प्रौद्योगिकी के बारे में

- व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) तकनीक वायरलेस तरीके से आसपास के वाहनों की गति, स्थिति, दिशा, त्वरण एवं ब्रेकिंग डाटा संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान करती है।
- परंपरागत सेंसरों के विपरीत यह अंधे जंक्शनों, मोड़ों और बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के आसपास दृष्टि रेखा से परे खतरों की पहचान करता है।

KACADEMY YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

- फैक्ट्री में लगे ऑन-बोर्ड यूनिट टावरों या क्लाउड सर्वरों के बिना सेलुलर व्हीकल-टू-एवरीथिंग तकनीक के माध्यम से सीधे संचार करते हैं।
- यह लाइसेंस-मुक्त 5.875-5.925 GHz बैंड का उपयोग करता है जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अनुप्रयोगों के लिए आवंटित है।

### प्रस्तावित कार्यान्वयन

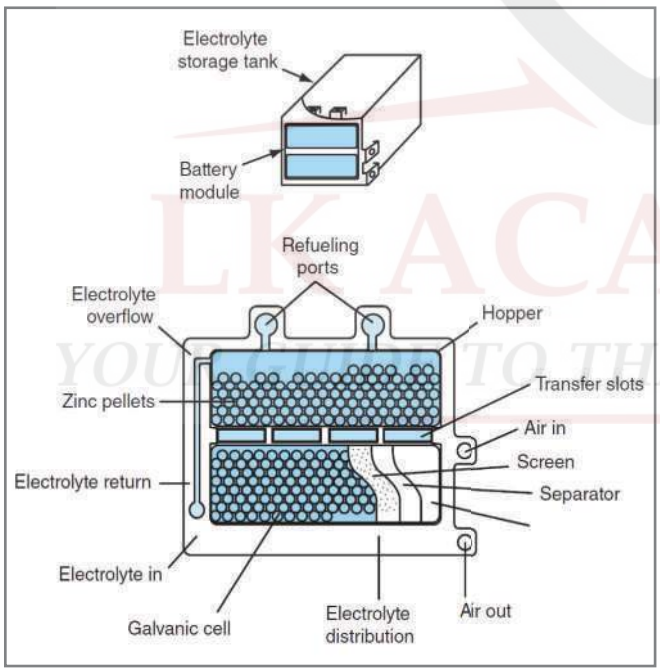
- AIS-230 में तकनीकी, स्थिति निर्धारण, विद्युत चुम्बकीय अनुकूलता, प्रदर्शन और साइबर सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है।
- 1 अक्टूबर, 2027 से L, M एवं N वाहनों में स्वेच्छा से लगाए गए वी2वी सिस्टम को AIS-230 का पालन करना होगा।
- 1 अक्टूबर, 2028 से नव निर्मित L, M एवं N वाहनों के लिए AIS-230-अनुरूप प्रणाली अनिवार्य हो जाएगी।
- V2V, ऑनबोर्ड सेंसर की दृश्य सीमा से परे प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करके उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणालियों का पूरक है।

## उभरती प्रौद्योगिकियाँ

## जिंक-एयर बैटरी के लिए नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट

### संदर्भ

SASTRA डीम्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिचार्जेबल जिंक-एयर बैटरी की दक्षता एवं सुरक्षा में सुधार करने वाला एक नैनोफ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया है।




### संबंधित बिंदु

- यह इलेक्ट्रोलाइट एक पारंपरिक जलीय इलेक्ट्रोलाइट के भीतर सस्ते सिलिका एवं जिंक-ऑक्साइड नैनोकणों को फैलाता है।
- यह जिंक के क्षरण और हाइड्रोजन उत्सर्जन को रोकता है, साथ ही वायु कैथोड पर ऑक्सीजन प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाता है।
- तीन महीने से अधिक समय से स्थिर यह पेटेंट तकनीक ग्रिड स्टोरेज एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सपोर्ट करती है।
- जिंक-एयर बैटरियाँ उच्च सैद्धांतिक ऊर्जा घनत्व, निम्न लागत एवं सुरक्षित जल-आधारित रसायन विज्ञान प्रदान करती हैं।

### जिंक-एयर एवं जिंक-आयन बैटरियों के बारे में

- जिंक-आयन बैटरी के विपरीत जिंक-एयर बैटरी में जिंक एनोड व वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है।
- जिंक-आयन बैटरी एक धात्विक-जिंक एनोड एवं मैंगनीज/वैनेडियम-ऑक्साइड कैथोड के बीच जिंक आयनों ($Zn^{2+}$) का स्थानांतरण करती हैं।
- डिस्चार्ज के दौरान जस्ता ऑक्सीकृत होकर कैथोड में प्रवेश करता है; चार्जिंग इस गति को उलट देती है।
- जिंक-आयन बैटरियाँ कम लागत, बेहतर सुरक्षा, पर्यावरणीय लाभ और लंबी चक्र अवधि प्रदान करती हैं।

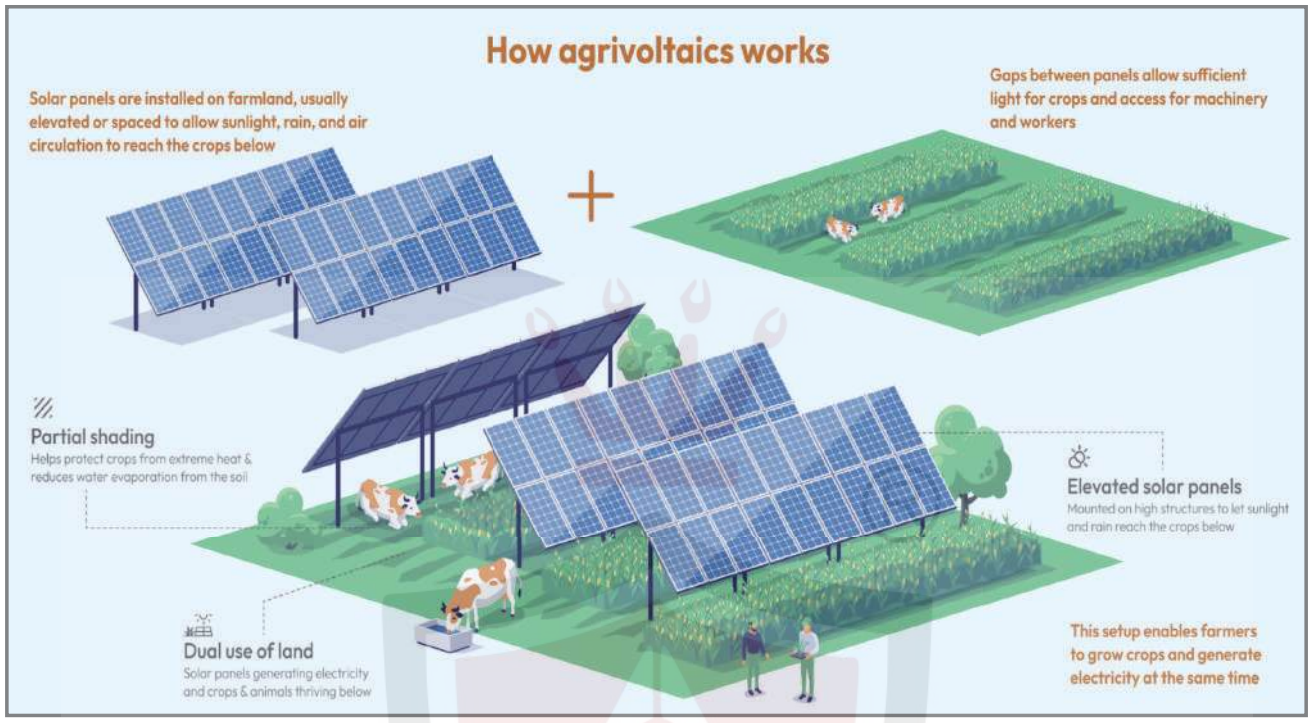
## एग्री-फोटोवोल्टिक्स

### संदर्भ

एग्री-वोल्टिक्स तकनीक सौर ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को कृषि भूमि एवं खाद्य सुरक्षा की जरूरतों के साथ सामंजस्य बिठाने में मदद करती है।

### एग्री-फोटोवोल्टिक्स के बारे में

- कृषि-फोटोवोल्टिक्स (AgriPV) एक ही भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन और फसल की खेती को जोड़ता है।
- पैनलों को फसलों से ऊपर लगाया जाता है, पंक्तियों के बीच में दूरी रखी जाती है, लंबवत रूप से स्थापित किया जाता है या ग्रीनहाउस में एकीकृत किया जाता है।
- पैनल की छाया से गर्मी का तनाव और पानी की हानि कम होती है जबकि पौधों द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन पैनलों को ठंडा करता है और उनकी कार्यक्षमता में सुधार करता है।
- फसलों का चयन क्षेत्र विशेष पर निर्भर करता है: हल्दी एवं तुलसी छाया सहन कर सकती हैं, जबकि अनाज के लिए अधिक दूरी पर पौधों के बीच रोपण की आवश्यकता होती है।




## लाभ एवं व्यावसायिक मॉडल

- किसान बिजली की बचत, अतिरिक्त बिजली की बिक्री और निरंतर कृषि उत्पादन के माध्यम से आय अर्जित करते हैं।
- वाष्पोत्सर्जन में कमी से जल उपयोग दक्षता में सुधार होता है, विशेष रूप से शुष्क राजस्थान व गुजरात में।
- ये पैनल फसलों को लू, भारी बारिश एवं ओलावृष्टि से बचाते हैं। साथ ही, कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण को बिजली प्रदान करते हैं।
- परियोजनाएँ किसान-स्वामित्व वाली, सहकारी या किसान उत्पादक संगठन-आधारित, पट्टे पर या राजस्व-साझाकरण वाली हो सकती हैं।

# विविध

## मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग प्लस टेक्नोलॉजी

### संदर्भ

CSIR-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने राजस्थान सरकार को अपनी स्वदेशी एमएसएस+ (MSS+) सड़क प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया।

### प्रमुख विशेषताएँ

- मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग प्लस (MSS+) टिकाऊ, लागत प्रभावी सड़क निर्माण एवं निवारक रखरखाव में सहायक है।
- इसका लाइव प्रदर्शन 7 अगस्त, 2026 को जयपुर शहर की एक सड़क पर आयोजित किया गया था।
- एमएसएस+ स्मार्ट मिक्स प्रो भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित मोबाइल संयंत्र है, जिसे इस तकनीक के लिए डिजाइन किया गया है।
- स्वचालित अनुपात निर्धारण एवं मिश्रण से गुणवत्ता में निरंतरता, कार्य में तेजी और मैन्युअल हस्तक्षेप में कमी सुनिश्चित होती है।
- MSS+ उत्सर्जन, ऊर्जा उपयोग, सामग्री की बर्बादी और रखरखाव लागत को कम करते हुए सड़क की अवधि को बढ़ाता है।
- उत्तर प्रदेश में 100 किलोमीटर सड़कों पर पहले से ही इसका उपयोग किया जा रहा है और अब राजस्थान के लिए इस पर विचार किया जा रहा है।

LK ACADEMY
YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

# पर्यावरण/पारिस्थितिकी/ भूगोल/जलवायु परिवर्तन



## संपादकीय

### सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण कानून को बढ़ावा और उसके दूरगामी प्रभाव

'सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण कानून को पोषित किया है। क्या आज इसके फैसले दूरगामी लगते हैं?' (SC has nurtured environmental law. Do its decisions look distant today?) शीर्षक वाला यह संपादकीय 14 अगस्त, 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था, जो पर्यावरण न्यायशास्त्र में सर्वोच्च न्यायालय की मूलभूत भूमिका और विकास परियोजनाओं की निरंतर न्यायिक जाँच की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

#### संवैधानिक आधार

- प्रारंभ में भारत में कोई सटीक पर्यावरण नीति नहीं थी किंतु स्टॉकहोम सम्मेलन ने देश के उभरते पर्यावरण दर्शन को आकार दिया।
- 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद 48A को शामिल किया गया, जो राज्य को पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है और अनुच्छेद 51A(g) को भी शामिल किया गया, जो नागरिकों पर एक संबंधित मौलिक कर्तव्य लागू करता है।

#### पर्यावरण न्यायशास्त्र का विकास

- भोपाल गैस त्रासदी ने न्यायिक हस्तक्षेप को गति दी, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने नुकसान पहुँचाने वाले स्वाभाविक रूप से खतरनाक उद्यमों के लिए पूर्ण दायित्व का सिद्धांत विकसित किया।
- प्रदूषण फैलाने वाले से भुगतान लेने का सिद्धांत, जिसे 1992 के रियो शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश किया गया था, भारत में पहली बार इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो-लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में लागू किया गया था।
- वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच वाद में न्यायालय ने यह माना कि एहतियाती सिद्धांत के लिए पर्यावरणीय क्षरण का उसके स्रोत पर ही पूर्वानुमान लगाना और उसे रोकना आवश्यक है।
- इसी फैसले में एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषण फैलाने वाले से भुगतान लेने के सिद्धांत को सतत विकास एवं प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के आवश्यक तत्त्वों के रूप में मान्यता दी गई।
- वनशक्ति समीक्षा निर्णय में मौद्रिक क्षतिपूर्ति के ऊपर एहतियात को प्राथमिकता दी गई क्योंकि पारिस्थितिक क्षति को रोकना बाद में प्रदूषण फैलाने वाले से भुगतान करवाने की नीति लागू करने से बेहतर है।
- एमसी मेहता बनाम कमल नाथ वाद में न्यायालय ने सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत को विकसित किया, प्रदूषण फैलाने वाले पर भुगतान का दायित्व थोपा और अंतर-पीढ़ीगत समानता की पुष्टि की।
- इन निर्णयों ने सर्वोच्च न्यायालय को सतत विकास का समर्थन करने वाले सिद्धांतों के माध्यम से भारत के पर्यावरण संबंधी न्यायशास्त्र को पोषित करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में स्थापित किया।

#### समकालीन न्यायिक असंगति

- न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने टिप्पणी की कि न्यायालय प्रायः गैर सरकारी संगठनों द्वारा पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का समर्थन करता है किंतु जब याचिकाएँ अवसंरचना परियोजनाओं पर सवाल उठाती हैं तो वह अधिक न्यायिक अनिच्छा प्रदर्शित करता है।
- असंगत निर्णय न्यायालय के अपने पर्यावरणीय सिद्धांतों के विपरीत हैं और मौजूदा पारिस्थितिकी खतरों को बढ़ा सकते हैं तथा कानूनी निश्चितता को कमजोर कर सकते हैं।
- पर्यावरण एवं विकास स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं; वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच वाद ने तीन दशक पहले सतत विकास के माध्यम से इनके सामंजस्य को मान्यता दी थी।
- अदालतों को हर पर्यावरणीय चुनौती को अनुचित माने बिना वास्तव में तुच्छ याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए क्योंकि न्यायिक पहुँच को बंद करने से प्रतिबद्ध पर्यावरणविदों के पास कोई प्रभावी उपाय नहीं बचता है।
- न्यायिक जाँच इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि परियोजनाएँ पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन करती हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी विकास गतिविधियाँ, चाहे उनका स्तर कुछ भी हो, कानूनी सुरक्षा उपायों को पूरा करती हैं।

#### संपादकीय के अतिरिक्त

*न्यायालय-नेतृत्व आधारित पर्यावरण शासन व्यवस्था की सीमाएँ*

- **विधायी जनादेश :** पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और CAQM अधिनियम, 2021 से पता चलता है कि निर्वाचित संस्थाओं को लागू करने योग्य मानक और विशेष नियामक निकाय बनाने होंगे।
- **न्यायिक निर्भरता :** एमसी मेहता दिल्ली प्रदूषण मामले को 2026 में बंद किए जाने से पहले चार दशकों तक निरंतर निगरानी की आवश्यकता पड़ी, जो न्यायिक निर्देशों पर प्रशासनिक निर्भरता को दर्शाता है।

- **विशेषीकृत न्यायनिर्णय :** सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम बनाम अंकिता सिन्हा (2021) मामले में एनजीटी की स्वप्रेरित शक्तियों की पुष्टि करते हुए विशेषीकृत पर्यावरण प्रवर्तन को मजबूत किया।
- **वैज्ञानिक मूल्यांकन :** चार धाम परियोजना से जुड़े मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित उच्चाधिकार समिति ने हिमालयी घाटियों में सड़क निर्माण के संचयी और स्वतंत्र प्रभावों की जाँच की।
- **सामुदायिक भागीदारी :** नियामगिरि वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आदिवासी सांस्कृतिक और वन-अधिकार दावों को ग्राम सभाओं के पास भेज दिया, जिसमें परामर्श किए गए सभी 12 गाँवों ने बॉक्साइट खनन को अस्वीकार कर दिया।
- **नियामक प्रवर्तन :** सीपीसीबी ने 2018 में 351 प्रदूषित नदी क्षेत्रों की पहचान की, जो यह दर्शाता है कि अदालतों द्वारा पर्यावरणीय सिद्धांतों को घोषित किए जाने के बाद निरंतर निगरानी और राज्य-स्तरीय प्रवर्तन क्यों अपरिहार्य हैं।
- **निवारक समन्वय :** जनवरी 2026 में जब दिल्ली का AQI 354 था, लेकिन इसके गंभीर होने का पूर्वानुमान था, तब CAQM ने GRAP के तीसरे चरण को लागू किया, जो पूर्वानुमान-आधारित प्रशासनिक कार्रवाई को दर्शाता है।

## वृक्षों के लिए वनों का विनाश

'लूजिंग फॉरेस्ट फॉर ट्रीज' (Losing forest for trees) शीर्षक वाला यह संपादकीय 18 अगस्त, 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत के वृक्षारोपण-केंद्रित दृष्टिकोण ने पारिस्थितिकी रूप से कार्यात्मक वनों को बहाल किए बिना वृक्षों की संख्या में वृद्धि की है।

### ग्रीन इंडिया मिशन के कार्यान्वयन में विफलता

- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के एक प्रदर्शन ऑडिट में पाया गया कि लगभग एक दशक तक संचालन के बावजूद ग्रीन इंडिया मिशन ने बहुत कम उपलब्धियाँ हासिल कीं।
- 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सुधार के अपने लक्ष्य के मुकाबले जीआईएम (GIM) ने केवल 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ही कवर किया है जबकि वन विस्तार मुश्किल से 4% तक ही पहुँचा है।
- वनरोपण एवं भूमि पुनर्स्थापन के लिए कैम्पा (CAMPA) एवं मनरेगा (MGNREGA) निधियों के साथ प्रस्तावित समन्वय काफी हद तक साकार नहीं हो सका।
- NAPCC के एक स्तंभ के रूप में जीआईएम (GIM) का उद्देश्य भारत की पेरिस प्रतिबद्धता का समर्थन करते हुए जैव विविधता, जल सुरक्षा, कार्बन पृथक्करण एवं पर्यावासों को बहाल करना था।

### वृक्षारोपण की संख्या बनाम वन पुनर्स्थापन

- वर्ष 2024 में शुरू की गई 'एक पेड़ माँ के नाम' परियोजना में 140 करोड़ पौधे लगाए जाने की रिपोर्ट है किंतु वृक्षारोपण की कुल संख्या वन की गुणवत्ता को नहीं दर्शाती है।
- भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 में 1,445 वर्ग किमी. अतिरिक्त हरित आवरण दर्ज किया गया किंतु इसमें से केवल 156 वर्ग किमी. ही वास्तविक वन था।
- शेष 1,289 वर्ग किमी. क्षेत्र में जंगलों के बाहर वृक्षों का आवरण था, जबकि दर्ज किए गए जंगलों के भीतर सघन आवरण झाड़ियों वाले भूभाग में परिवर्तित होते रहे।
- अरावली पर्वतमाला में नए वृक्षारोपण से खनन, अतिक्रमण एवं आक्रामक विलायती कीकर की समस्या को व्युत्क्रम नहीं किया जा सका है या एक जटिल देशी पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्निर्माण नहीं किया जा सका है।
- पारिस्थितिकी बहाली के लिए जैव विविधता, आवासों व प्राकृतिक प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होती है जबकि वृक्षारोपण अभियान मुख्य रूप से मापन योग्य हेक्टेयर व पौधों की संख्या उत्पन्न करते हैं।
- सीएजी (CAG) ढाँचा व्यय एवं कार्यान्वयन संबंधी कमियों को माप सकता है किंतु यह किसी जीवित वन के पारिस्थितिकी मूल्य का पूरी तरह से आकलन नहीं कर सकता है।

### संपादकीय के अतिरिक्त

#### *समुदाय के नेतृत्व में पारिस्थितिकी बहाली*

- **वैधानिक प्राधिकरण :** वन अधिकार अधिनियम की धारा 5 ग्राम सभाओं को मान्यता प्राप्त सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण एवं प्रबंधन करने का अधिकार देती है।
- **स्थानीय जानकारी :** महाराष्ट्र में विकसित सामुदायिक वन योजनाओं में स्थानीय वनस्पति, संसाधन उपयोग एवं स्थानीय पारिस्थितिकी स्थितियों की ग्राम-स्तरीय समझ को पुनर्स्थापन निर्णयों में शामिल किया गया है।
- **आजीविका प्रोत्साहन :** महाराष्ट्र में लघु वन उत्पादों के पारगमन परमिट जारी करने के लिए ग्राम सभाओं के अधिकार को बहाल करने से सामुदायिक अधिकारों और महिलाओं के आजीविका के अवसरों को मजबूती मिली।
- **महिलाओं की भागीदारी :** ओडिशा के तटीय महिला समूहों ने मैंग्रोव बहाली को जलवायु-लचीली आजीविका के साथ जोड़ा है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण को घरेलू आर्थिक सुरक्षा से जोड़ा जा सके।
- **संस्थागत आधार :** उत्तराखंड की वन पंचायतें एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ यह दर्शाती हैं कि सामुदायिक नेतृत्व औपचारिक वन विभाग प्रशासन का पूरक हो सकता है।
- **स्केलेबल मॉडल :** महाराष्ट्र ने कोंकण और विदर्भ क्षेत्रों के सात जिलों के 100 अन्य गाँवों में एक सफल सामुदायिक वन-संसाधन प्रबंधन मॉडल का विस्तार किया।
- **पारिस्थितिकी जवाबदेही :** आधारभूत मापदंडों, उत्तरजीविता निगरानी और प्रलेखन का उपयोग करने वाली सामुदायिक वन योजनाएँ केवल वृक्षारोपण की संख्या की तुलना में पुनर्जनन व पर्यावास पुनर्प्राप्ति का अधिक सार्थक आकलन कर सकती हैं।

## ब्रिक्स समूह में लोगों एवं ग्रह को प्राथमिकता

'ब्रिक्स एक ऐसे भविष्य के लिए काम कर रहा है जो लोगों एवं ग्रह को प्राथमिकता देता है' (BRICS is working for a future that puts people and planet first) शीर्षक वाला यह संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस में 20 अगस्त, 2026 को प्रकाशित हुआ। इसमें जन-केंद्रित, समावेशी एवं कार्यान्वयन-उन्मुख पर्यावरणीय शासन के लिए भारत के नेतृत्व वाले ब्रिक्स सहयोग पर प्रकाश डाला गया है।

### ब्रिक्स का पर्यावरणीय दृष्टिकोण

- 18 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में भारत की अध्यक्षता में सामूहिक पर्यावरण कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया।
- ब्रिक्स वैश्विक आबादी के 49.5%, जीडीपी के लगभग 40% और व्यापार के 26% का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वैश्विक सहयोग पर इसका काफी प्रभाव है।
- भारत ने वैश्विक दक्षिण की चिंताओं और 'मानवता सर्वोपरि' के सिद्धांत पर केंद्रित जन-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है।
- मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम पारिस्थितिकी बहाली, सामुदायिक भागीदारी, जैव-विविधता संरक्षण, लचीलापन एवं आजीविका संवर्धन को एकीकृत करते हैं।

### पर्यावरण प्राथमिकताएँ

- सतत जीवनशैली मिशन लाइफ सिद्धांतों के माध्यम से जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, व्यवहार परिवर्तन, नागरिक जागरूकता और ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देती है।
- भूदृश्य लचीलापन में वनीकरण, भूमि पुनर्स्थापन, जंगल की आग से बचाव की तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, रिमोट सेंसिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संयोजन शामिल है।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था अस्थिर 'टेक-मेक-डिस्पोज' मॉडल की जगह लेती है। साथ ही, हरित रोजगार, नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं क्षमता निर्माण का समर्थन करती है।
- सामुदायिक आधारित अनुकूलन, संदर्भ-विशिष्ट और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त जलवायु समाधानों के लिए पारंपरिक, स्वदेशी व स्थानीय ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करता है।
- CBDR-RC एवं समानता विकासशील देशों की असमान कमजोरियों को पहचानते हैं और एक संतुलित वैश्विक पर्यावरणीय प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक बने हुए हैं।

### परिणाम और कार्यान्वयन

- भारत की अध्यक्षता में सतत जीवनशैली, भूदृश्य प्रबंधन, वन-अग्नि से बचाव की तैयारी और सामुदायिक अनुकूलन पर व्यावहारिक सिद्धांत के साथ ही तकनीकी रिपोर्ट एवं सहयोग मंच तैयार किए गए।
- ये परिणाम निरंतर सहमति निर्माण को दर्शाते हैं और साझा पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षीय सहयोग के महत्त्व को प्रदर्शित करते हैं।
- भारत ने 2005-2022 के दौरान अपनी उत्सर्जन तीव्रता में 37.38% की कमी की है जबकि जून 2026 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से स्थापित बिजली क्षमता का 54.18% हिस्सा प्राप्त हुआ।
- भारत का 2031-2035 का राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी घोषणापत्र समावेशी विकास एवं ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ जलवायु संबंधी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।
- ब्रिक्स की सफलता का आकलन केवल अपनाए गए सिद्धांतों या घोषणाओं के आधार पर नहीं, बल्कि मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका के माध्यम से किया जाना चाहिए।

### संपादकीय के अतिरिक्त

#### *ब्रिक्स जलवायु सहयोग के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएँ*

- **भिन्न प्राथमिकताएँ :** चीन ने 2024 में वैश्विक कोयले का 58% उपभोग किया, जबकि ब्राजील जलविद्युत पर काफी हद तक निर्भर है जिससे ब्रिक्स देशों के भीतर सामान्य संक्रमण मार्गों में जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **वित्तीय घाटा :** यूएनईपी (UNEP) ने अनुमान लगाया है कि विकासशील देशों को 2035 तक सालाना 310-365 बिलियन डॉलर की अनुकूलन आवश्यकता होगी, जबकि 2023 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक प्रवाह केवल 26 बिलियन डॉलर था।
- **प्रौद्योगिकी संकेंद्रण :** आईईए (IEA) ने पाया कि 2025 में 20 रणनीतिक खनिजों में से 19 के शोधन में चीन का वर्चस्व होगा, जिससे स्वच्छ प्रौद्योगिकी आपूर्ति शृंखलाओं के भीतर असममित निर्भरता पैदा होगी।
- **संस्थागत कमजोरी :** ब्रिक्स के पास कोई संस्थापक चार्टर, स्थायी सचिवालय और साझा परिचालन निधि नहीं है जिससे इसका कार्यान्वयन बारी-बारी से होने वाली अध्यक्षता व निरंतर राजनीतिक सहमति पर निर्भर करता है।
- **डेटा असंगतता :** भारत का लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन-तीव्रता में 45% की कमी लाना है जबकि ब्राजील का लक्ष्य 2035 तक 59-67% की पूर्ण कमी लाना है जिससे तुलनात्मक निगरानी जटिल हो जाती है।
- **भू-राजनीतिक तनाव :** न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2025 में भी नए रूसी लेनदेन को निलंबित बताया है जो दर्शाता है कि भू-राजनीतिक प्रतिबंध ब्रिक्स देशों के वित्तपोषण को किस प्रकार सीमित कर सकते हैं।
- **स्थानीय क्षमता :** यूएनईपी (UNEP) की अनुकूलन अंतर रिपोर्ट, 2024 में पाया गया कि अनुकूलन योजना कार्यान्वयन की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रही है, जो वित्त, कौशल एवं संस्थागत क्षमता की लगातार कमी को दर्शाती है।

## मुख्य परीक्षा

### पर्यावरण प्रभाव आकलन ढाँचे में संशोधन

#### संदर्भ

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने राज्य स्तरीय परियोजना मूल्यांकन में होने वाली देरी को कम करने के लिए EIA ढाँचे में संशोधन अधिसूचित किए हैं।

#### अधिसूचित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ

- **राज्य-स्तरीय बैकअप निकाय :** MoEFCC ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए SAEIA और SCEIA का गठन किया है ताकि नियमित SEIAA या SEAC निकायों के निष्क्रिय होने की स्थिति में श्रेणी B की परियोजनाओं को अस्थायी रूप से संसाधित किया जा सके।
- **सीमित परिचालन अवधि :** प्रत्येक स्थायी निकाय प्रारंभ में छह महीने के लिए कार्य कर सकता है, जिसे स्वचालित रूप से एक वर्ष का कार्यकाल प्राप्त करने के बजाय एक बार और छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- **परिभाषित संरचना :** SAEIA में वरिष्ठ प्रशासक और वन अधिकारी शामिल होते हैं जबकि SCEIA में पर्यावरण, वन्यजीव, स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण एवं IIT, NIT या NEERI के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- **विस्तारित कार्यकाल :** ईएसी (EAC), एसईएसी (SEAC) और एसईआईएए (SEIAA) में नियुक्त व्यक्तियों का कार्यकाल तीन से बढ़ाकर चार वर्ष कर दिया गया है, जिसमें अधिकतम दो कार्यकाल व अग्रिम पुनर्गठन योजना शामिल है।
- **आयु एवं निष्कासन संबंधी प्रावधान :** नियुक्ति की आयु सीमा 70 वर्ष है, जिसे असाधारण परिस्थितियों में 75 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। समय से पहले हटाने के लिए आरोपों का प्रमाण आवश्यक है, जिसमें मूल्यांकन में देरी भी शामिल हो सकती है।
- **फॉलबैक तंत्र में परिवर्तन :** राज्य निकायों के कार्यकाल समाप्त होने पर श्रेणी बी के प्रस्ताव अब स्वचालित रूप से केंद्रीय स्तर पर स्थानांतरित नहीं होंगे क्योंकि एसएईआईए (SAEIA) एवं एससीईआईए (SCEIA) स्थानीय स्तर पर उनका निपटान करेंगे।
- **विशेषज्ञता संबंधी चिंता :** आलोचकों का तर्क है कि स्थायी निकायों में एसईएसी की तुलना में अधिक नौकरशाही प्रतिनिधित्व और सीमित विशेषज्ञता होती है, हालाँकि, एससीईआईए (SCEIA) में डोमेन विशेषज्ञ शामिल होते हैं और उन्हें सह-चयनित भी किया जा सकता है।




#### पर्यावरण प्रभाव आकलन ढाँचे के बारे में

- **अर्थ :** ईआईए (EIA) एक पूर्व मूल्यांकन प्रक्रिया है जो परियोजना की मंजूरी से पहले पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्वानुमान लगाती है और उनसे बचाव, शमन या क्षतिपूर्ति के उपायों की पहचान करती है।
- **कानूनी आधार :** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी ईआईए अधिसूचना, 2006 में इसकी अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता है।
- **श्रेणी ए :** उच्च प्रभाव या क्षमता की सीमा को पूरा करने वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन एक केंद्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है और MoEFCC द्वारा मंजूरी दी जाती है या अस्वीकार कर दी जाती है।
- **श्रेणी बी :** राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर, निर्धारित न्यूनतम सीमा के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं पर SEIAA द्वारा विचार किया जाता है।
  - **उप-श्रेणी बी1:** इन परियोजनाओं के लिए प्रायः एक विस्तृत EIA रिपोर्ट और सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता होती है जब तक कि अधिसूचना के तहत विशेष रूप से छूट न दी गई हो।
  - **उप-श्रेणी बी2:** इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत ईआईए रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है और प्रायः इन्हें सार्वजनिक परामर्श से छूट दी जाती है किंतु ये निर्धारित मूल्यांकन आवश्यकताओं का पालन करती हैं।
- **मूल्यांकन प्रक्रिया :** इसमें श्रेणी बी परियोजनाओं की स्क्रीनिंग, कार्यक्षेत्र निर्धारण, सार्वजनिक परामर्श, मूल्यांकन एवं मंजूरी शामिल हैं। मंजूरी के बाद नियमों के अनुपालन की निगरानी की जाती है।

### न्यायिक हस्तक्षेप

- **वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ (1996):** न्यायालय ने एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषण फैलाने वाले से भुगतान लेने के सिद्धांत को सतत विकास की आवश्यक विशेषताओं के रूप में मान्यता दी।
- **नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (2000):** सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण उपायों और पुनर्वास के अधीन सरदार सरोवर परियोजना की अनुमति दी, जिसमें सतत विकास को लागू किया गया।
- **हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम भारत संघ (2019):** न्यायालय ने माना कि पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) संबंधी सार्वजनिक परामर्श में हितधारकों की चिंताओं को सार्थक रूप से संबोधित किया जाना चाहिए, जिससे सूचित और जवाबदेह निर्णय लेने को सुनिश्चित किया जा सके।

## ईआईए (EIA) प्रक्रिया के समक्ष चुनौतियाँ

- **प्रक्रियात्मक विलंब :** सीएजी की 2016 की रिपोर्ट संख्या 39 में पाया गया कि जाँच की गई 89% स्वीकृतियों में निर्धारित समय-सीमा से अधिक देरी हुई; 2015 में औसत देरी 238 दिन थी।
- **मूल्यांकन की कमजोर गुणवत्ता :** खराब आधारभूत डेटा और अपर्याप्त प्रभाव विश्लेषण निर्णयों को कमजोर करते हैं; हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर (2019) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मोपा हवाई अड्डे के मूल्यांकन में कमियों को गलत ठहराया।
- **हितों का टकराव :** परियोजना प्रस्तावक द्वारा EIA सलाहकारों को नियुक्त किया जाता है, जिससे मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से मान्यता संबंधी आवश्यकताओं के बावजूद प्रतिकूल प्रभावों को कम करके आँकने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
- **कमजोर जन परामर्श :** तकनीकी दस्तावेज अनुपलब्ध रह सकते हैं या वे अनूदित नहीं हो पाते हैं। साथ ही, CAG ने पाया कि सार्वजनिक सुनवाई में कुछ कमियाँ थीं और समुदाय की समस्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी।
- **मंजूरी के बाद अपर्याप्त निगरानी :** नियामक प्राय: मंजूरी की शर्तों के अनुपालन को सत्यापित करने में विफल रहते हैं, जिससे कागज पर पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं व जमीनी स्तर पर उनके कार्यान्वयन के बीच एक अंतर पैदा हो जाता है।
- **नियामकीय शिथिलता :** ईआईए अधिसूचना, 2020 के मसौदे में सार्वजनिक सुनवाई की सूचना अवधि को 30 दिनों से घटाकर 20 दिन करने और अतिरिक्त बी2 परियोजनाओं को परामर्श से छूट देने का प्रस्ताव किया गया था।
- **कार्योत्तर विनियमितीकरण :** मसौदा अधिसूचना ने पूर्व मंजूरी के बिना संचालित होने वाली परियोजनाओं को बाद में अनुमोदन प्राप्त करने की अनुमति दी, जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान के अपरिवर्तनीय होने की स्थिति में एहतियाती सिद्धांत कमजोर हो गया।
- **सीमित सीमा पार मूल्यांकन :** भारत का ईआईए ढाँचा सीमा पार पर्यावरणीय प्रभावों को अपर्याप्त रूप से संबोधित करता है जबकि भारत सीमा पार ईआईए पर 1991 के एस्पू कन्वेंशन (Espoo Convention) का पक्षकार नहीं है।

### प्रमुख पहल

- **पूर्व में ENVIS और अब EIACP:** यह विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर्यावरणीय जानकारी एकत्र करता है और उसका प्रसार करता है। साथ ही, विषय-विशिष्ट केंद्रों के माध्यम से शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं, छात्रों एवं जन जागरूकता का समर्थन करता है।
- **परिवेश पोर्टल :** यह एकल-खिड़की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर्यावरण, वन, वन्यजीव एवं सीआरजेड (CRZ) स्वीकृतियों को ऑनलाइन जमा करने, मूल्यांकन करने और ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, जिससे पारदर्शिता व प्रशासनिक दक्षता में सुधार होता है।
- **प्रस्तावित SEIAA स्टार रेटिंग :** वर्ष 2022 की योजना में समयसीमा, प्रस्तावों के निपटान, शिकायतों एवं साइट विजिट के आधार पर SEIAA को रेटिंग देने का प्रस्ताव था; हालाँकि, MoEFCC ने इसे 2025 में वापस ले लिया, जिससे यह निष्क्रिय हो गई।

## EIA ढाँचे को सुदृढ़ बनाना

- **विशेषज्ञ निकायों को मजबूत करना :** बहुविषयक विशेषज्ञों के पारदर्शी चयन के माध्यम से एसईआईएए और एसईएसी का शीघ्र पुनर्गठन करना, रिक्तियों को भरना और अस्थायी नौकरशाही व्यवस्थाओं पर निर्भरता को कम करना।
- **स्वतंत्र अनुपालन निगरानी :** एक स्वायत्त नियामक की स्थापना करना और परियोजना-वार अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना; यूरोपीय संघ के ईआईए निर्देश में महत्त्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पैदा करने वाली परियोजनाओं की निगरानी अनिवार्य है।
- **समावेशी जनभागीदारी :** पर्याप्त सूचना, क्षेत्रीय भाषा में सारांश और सुलभ तकनीकी जानकारी प्रदान करना। साथ ही, यह भी दर्ज करना कि सामुदायिक चिंताओं ने अंतिम मंजूरी निर्णय को किस प्रकार प्रभावित किया।

- **एक स्वतंत्र पर्यावरण प्रभाव आकलन कानून लागू करना :** चीन के पर्यावरण प्रभाव आकलन कानून, 2002 के अनुरूप एक समर्पित कानून से कानूनी संधारणीयता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, जो योजनाओं व परियोजनाओं को कवर करता है।
- **रणनीतिक आकलन अपनाना :** रणनीतिक पर्यावरण आकलन में नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए जबकि सामाजिक और स्वास्थ्य आकलन में आजीविका, संस्कृति, विस्थापन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की जाँच की जानी चाहिए।
- **रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार करना :** प्रस्तावक द्वारा वित्तपोषित ईआईए अध्ययनों से उत्पन्न होने वाले विवादों को कम करने के लिए मान्यता प्राप्त सलाहकारों को यादृच्छिक रूप से आवंटित करना, स्वतंत्र सहकर्मी समीक्षा करना और मनगढ़ंत डेटा को दंडित करना।
- **प्रौद्योगिकी और भू-भाग-स्तरीय योजना का उपयोग करना :** सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग, एआई और सार्वजनिक डैशबोर्ड अनुपालन को ट्रैक कर सकते हैं और कई क्षेत्रीय परियोजनाओं के संचयी प्रभावों का आकलन कर सकते हैं।

## फ्लैश फ्लड

### संदर्भ

प्रतिवर्ष होने वाली सैकड़ों मौतों के बीच असम एवं गुजरात में हाल ही में आई फ्लैश फ्लड (अचानक बाढ़) भारत के जलवायु के प्रति बढ़ते जोखिम को उजागर करती है।

### फ्लैश फ्लड के बारे में

- फ्लैश फ्लड ऐसी बाढ़ होती हैं जिनमें जल स्तर तेजी से बढ़ता व घटता है और प्रायः भारी बारिश या अन्य कारणों के छह घंटे के भीतर ही ये बाढ़ उत्पन्न होती हैं।
- देश में फ्लैश फ्लड की लगभग 75% घटनाएँ जून से सितंबर तक चलने वाले दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान होती हैं।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, फ्लैश फ्लड की दर्ज की गई घटनाओं की संख्या 2020 में 132 से बढ़कर 2022 में 184 हो गई।
- हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी तट एवं मध्य भारत में प्रायः फ्लैश फ्लड की समस्या होती रहती है।
- ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में सबसे अधिक घटनाएँ दर्ज की गई हैं, उसके बाद गंगा एवं कृष्णा नदी के बेसिन का स्थान आता है।

### फ्लैश फ्लड के प्रेरक कारक

| प्राकृतिक कारक | मानवजनित कारक |
|---|---|
| **अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ :** केवल 25% फ्लैश फ्लड ही पूरी तरह से अत्यधिक वर्षा के कारण होती हैं; 2013 की केदारनाथ आपदा का कारण तेज वर्षा व क्लाउड बर्स्ट था। | **जल विज्ञान में परिवर्तन :** बाँध संचालन, नहर प्रणालियाँ व जलमार्ग परिवर्तन प्राकृतिक प्रवाह को बदल देते हैं; 2019 में तिवाड़े बाँध के टूटने से निचले इलाकों के गाँवों में फ्लैश फ्लड आ गई थी। |
| **मृदा संतृप्ति :** गीली या संतृप्त मृदा पानी के अवशोषण को कम करती है और तत्काल अपवाह उत्पन्न करती है, जैसा कि पिछली बारिश ने 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई फ्लैश फ्लड को और तीव्र कर दिया था। | **अतिक्रमण :** बाढ़ के मैदानों का निर्माण, आर्द्रभूमि का क्षरण और अपर्याप्त जल निकासी जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसा कि 2015 की चेन्नई की भीषण बाढ़ के दौरान देखा गया था। |
| **स्थलाकृति एवं ढलान :** हिमालय की खड़ी ढलानें और संकरी घाटियाँ पानी के प्रवाह को तेज करती हैं, जैसा कि उत्तराखंड में 2021 की ऋषिगंगा की फ्लैश फ्लड से स्पष्ट होता है। | **जलवायु परिवर्तन :** बढ़ते तापमान से वर्षा और ग्लेशियर पिघलने की तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होती है; 2023 का दक्षिण ल्होनक GLOF हिमालयी जोखिमों में वृद्धि को दर्शाता है। |

### जलवायु-प्रेरित फ्लैश फ्लड

- **वायुमंडलीय आर्द्रता :** तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से वायुमंडलीय आर्द्रता धारण क्षमता में लगभग 7% की वृद्धि होती है, जिससे वर्षा व फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि 2023 में हिमाचल प्रदेश में हुई आपदा के दौरान देखा गया था।
- **अत्यधिक वर्षा :** 1981-2020 के दौरान मानसून से पहले होने वाली अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ 1951-1980 की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई, जिसमें मई 2022 की असम बाढ़ बढ़ती संवेदनशीलता को दर्शाती है।
- **जोखिम का विस्तार :** अधिकांश दर्ज की गई फ्लैश फ्लड ब्रह्मपुत्र, गंगा व कृष्णा बेसिन में होती हैं जबकि कम संवेदनशील उप-बेसिन में बढ़ती अत्यधिक वर्षा हॉटस्पॉट के स्थानांतरण का संकेत देती है।
- **क्रायोस्फेरिक अस्थिरता :** ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियरों और पर्वतीय ढलानों को अस्थिर कर देती है, जैसा कि 2021 के

चमोली रॉक-आइस हिमस्खलन एवं 2023 के साउथ ल्होनाक GLOF से प्रदर्शित होता है।

## फ्लैश फ्लड के प्रभाव

- **संपत्ति का नुकसान :** फ्लैश फ्लड घरों, सड़कों, पुलों और कृषि भूमि को नष्ट कर देती है; 2021 की चमोली आपदा ने दो जलविद्युत परियोजनाओं को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था।
- **आर्थिक नुकसान :** संपत्ति का विनाश आजीविका को बाधित करता है और पुनर्निर्माण लागत को बढ़ाता है, जैसा कि 2023 में सिक्किम में आई GLOF के बाद देखा गया, जिसमें बांधों, सड़कों व पुलों को नुकसान पहुँचा था।
- **पर्यावरणीय क्षति :** तेज बहाव से मृदा का कटाव, तलछट का जमाव और जल प्रदूषण होता है; 2013 की केदारनाथ आपदा ने मंदाकिनी घाटी में भारी मात्रा में मलबा जमा कर दिया था।
- **मानवीय क्षति :** अचानक शुरुआत और तेज गति के कारण बचाव कार्य के लिए बहुत कम समय बचता है; 2013 की उत्तराखंड आपदा में हजारों लोगों की मौत हुई और कई लोग लापता हो गए।
- **जनसंख्या विस्थापन :** बाढ़ के कारण समुदायों को अस्थायी आश्रयों में शरण लेनी पड़ती है और भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवा व शिक्षा की व्यवस्था बाधित हो जाती है, जैसा कि 2022 में असम में आई बाढ़ के दौरान देखा गया था।
- **बीमारियों का प्रकोप :** दूषित जल एवं स्वच्छता में कमी के कारण डायरिया और वेक्टर जनित बीमारियों में वृद्धि होती है; केरल में 2018 की बाढ़ के बाद लेप्टोस्पाइरोसिस के मामलों में वृद्धि हुई थी।

### भारत में फ्लैश फ्लड से निपटने के उपाय

- **दक्षिण एशिया FFGS:** IMD एवं WMO दक्षिण एशिया में वास्तविक समय में फ्लैश फ्लड का पूर्वानुमान व प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करते हैं।
- **सचेत पोर्टल :** एनडीएमए का कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल और सचेत ऐप स्थान-विशिष्ट आपदा चेतावनी प्रदान करते हैं।
- **एनडीएमए की बाढ़ संबंधी दिशा-निर्देश :** भेद्यता मानचित्रण, तैयारी, निकासी और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को मानकीकृत करना।
- **सुरक्षा प्रोटोकॉल :** एनडीएमए के भूस्खलन संबंधी दिशा-निर्देश ढलान के जोखिमों को संबोधित करते हैं, जबकि बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 बांध की निगरानी और आपातकालीन योजना को मजबूत करता है।

## फ्लैश फ्लड के लिए अनुकूलन रणनीतियाँ

- **स्थानीय स्तर पर योजना बनाना :** स्थलाकृति, मृदा की स्थिति, वर्षा व उप-बेसिन की भेद्यता का उपयोग करते हुए क्षेत्रीय रणनीतियों को डिजाइन करना, यह मानते हुए कि हिमालयी भूभाग और पश्चिमी तट की जल विज्ञान के लिए अलग-अलग प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है।
- **वैज्ञानिक मानचित्रण :** NRSC-इसरो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एटलस के आधार पर जोखिम मानचित्र तैयार करना, उभरते हॉटस्पॉट की पहचान करना और संवेदनशील क्षेत्रों को नामित करना।
- **प्रारंभिक चेतावनी :** AWS, डॉप्लर रडार, उपग्रह निगरानी और वास्तविक समय पूर्वानुमान का विस्तार करना; आईएमडी की दक्षिण एशिया फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम जलक्षेत्र स्तर के खतरों और जिला स्तर के जोखिमों की जानकारी प्रदान करती है।
- **तैयारी :** एनडीएमए की आपदा मित्र सामुदायिक स्वयंसेवी योजना जैसी पहलों के माध्यम से निकासी योजनाओं, जागरूकता, आपातकालीन संचार और स्थानीय प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना।
- **जलवायु-संवेदनशील विकास :** बाढ़ क्षेत्रीकरण (फ्लडप्लेन जोनिंग) को लागू करना, भूमि उपयोग को विनियमित करना, लचीला बुनियादी ढाँचा बनाना और जलाशय प्रबंधन में सुधार करना; बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में निचले इलाकों में चेतावनी प्रणाली और आपातकालीन योजनाओं को अनिवार्य किया गया है।
- **प्रकृति आधारित समाधान :** जल अपवाह को धीमा करने के लिए आर्द्रभूमि, वन, मैंग्रोव और प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों को बहाल करना; चेन्नई का पल्लीकरनई दलदल शहरी आर्द्रभूमि के बाढ़-रोधी मूल्य को दर्शाता है।

**प्रारंभिक परीक्षा**

## नो ट्रांजिशन विदाउट जस्टिस रिपोर्ट

### संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की नो ट्रांजिशन विदाउट जस्टिस रिपोर्ट बताती है कि पर्यावरण संबंधी कानून का शासन किस प्रकार एक न्यायसंगत संक्रमण को संभव बनाता है।

### न्यायसंगत संक्रमण बारे में

यह एक निष्पक्ष, समावेशी व अधिकार-आधारित संक्रमण है जो कमजोर समूहों को पीछे छोड़े बिना टिकाऊ एवं लचीली अर्थव्यवस्थाओं की ओर ले जाता है।

### पर्यावरणीय विधि के शासन की भूमिका

- मजबूत कानून पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन बनाते हैं, जैसा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत है।
- अधिकार-आधारित भागीदारी पर्यावरण रक्षकों की रक्षा करती है और निर्णय लेने में स्वदेशी और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शामिल करती है।
- पारदर्शी संक्रमणकालीन वित्त व्यवस्था प्रभावित श्रमिकों का समर्थन करती है, जिसका उदाहरण यूरोपीय संघ का न्यायसंगत संक्रमण कोष है।
- झारखंड में गठित टास्क फोर्स में समन्वित शासन व्यवस्था की झलक मिलती है, जिसमें राज्य के 17 विभाग शामिल हैं।
- न्यायसंगत न्याय ने नियामगिरि खनन मामले में ग्राम सभा के निर्णयों के माध्यम से डोंगरिया कोंध के अधिकारों की रक्षा की।
- विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप बनाई गई रणनीतियों में मेघालय में असुरक्षित तरीके से की जाने वाली रैट-होल खनन विधियों पर प्रतिबंध शामिल हैं।

### सिफारिशें

- राज्यों को ऐतिहासिक रूप से स्वदेशी लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, अधिकार-आधारित उचित परिश्रम को संस्थागत रूप देना चाहिए और पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करना चाहिए।
- व्यवसायों को संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और प्रभावित समुदायों के साथ समान रूप से लाभ साझाकरण सुनिश्चित करना चाहिए।
- वित्तीय संस्थानों को न्यायसंगत परिवर्तन मानकों को अपनाना चाहिए और समावेशी, निम्न उत्सर्जन वाले विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- सरकारों को अनपेक्षित परिणामों का अनुमान लगाते हुए एकीकृत अंतर-क्षेत्रीय शासन के साथ पृथक नीतियों को प्रतिस्थापित करना चाहिए।

## पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, 2026

### संदर्भ

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, 2026 में भारत 177 देशों में 176वें स्थान पर रहा है, जो लाओस से थोड़ा ही आगे है।

### सूचकांक के बारे में

- यह द्विवार्षिक सूचकांक येल विश्वविद्यालय द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार किया जाता है।
- यह 12 पर्यावरणीय श्रेणियों में 47 संकेतकों के माध्यम से 177 देशों का आकलन करता है।
- इन संकेतकों में पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंतता और जलवायु परिवर्तन नीति के उद्देश्य शामिल हैं।
- यह सतत विकास लक्ष्यों, पेरिस समझौते और वैश्विक जैव विविधता ढाँचे की दिशा में हुई प्रगति पर नजर रखता है।

### भारत का प्रदर्शन

- भारत ने 22.46 अंक प्राप्त किए, जिससे वह वैश्विक स्तर पर 176वें स्थान पर और दक्षिण एशिया के आठ देशों में 8वें स्थान पर रहा।
- 74.79 अंकों के साथ एस्टोनिया शीर्ष पर रहा, जबकि लाओस 21.78 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
- भारत की रैंकिंग 2016 में 141वीं, 2022 में 180वीं और 2024 एवं 2026 में 176वीं थी।
- प्रमुख कमजोरियों में वायु गुणवत्ता, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, जैव विविधता, वृक्षावरण और कीटनाशक प्रदूषण शामिल हैं।
- जलवायु, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कुछ संकेतकों में सापेक्षिक सुधार देखा गया।
- भारत का तर्क है कि EPI विकास के स्तर, जनसंख्या, ऐतिहासिक उत्सर्जन और सामान्य किंतु विभेदित जिम्मेदारियों की अनदेखी करता है।
  - येल विश्वविद्यालय का कहना है कि यह सूचकांक वर्तमान पर्यावरणीय परिणामों को मापता है, न कि ऐतिहासिक जिम्मेदारी या भविष्य की नीतिगत प्रतिबद्धताओं को।

## ग्लॉ झील : भारत की 101वीं रामसर साइट

### संदर्भ

ग्लॉ (ग्लाव) झील भारत का 101वाँ रामसर स्थल और अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल बन गया है। भारत में ऐसे स्थलों की संख्या 2014 में 26 से बढ़कर 2026 में 101 हो गई।

### ग्लॉ झील के बारे में

- यह पूर्वी हिमालय में स्थित कमलांग टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर एक निर्मल मीठे पानी की झील है।
- बारहमासी पहाड़ी धाराओं से सिंचित यह सघन प्राकृतिक वनस्पति से घिरा हुआ है।
- इसके आर्द्रभूमि और जलग्रहण क्षेत्र में 150 से अधिक वृक्ष प्रजातियाँ और 49 ऑर्किड प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- यह पदनाम जैव विविधता संरक्षण, जल एवं जलवायु सुरक्षा व टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देता है।

EK ACADEMY YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

### रामसर अभिसमय

- इसे 1971 में ईरान के रामसर में अपनाया गया और यह आर्द्रभूमि संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। यूनेस्को इसका निक्षेपागार (Depositary) है।
- यह भारत में 1 फरवरी, 1982 से लागू हुआ।
- किसी आर्द्रभूमि को नामित किए जाने के लिए नौ पारिस्थितिक, जलवैज्ञानिक या जैव विविधता मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना आवश्यक है।
- मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में रामसर स्थलों की सूची दी गई है जो पारिस्थितिकी विशेषताओं में वास्तविक या संभावित प्रतिकूल परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं।

## आर्द्रभूमि अभयारण्य के आसपास खनन पर प्रतिबंध

### संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत दिया कि आसन आर्द्रभूमि के आसपास लागू किए गए सुरक्षा उपाय देशभर में इसी तरह के संरक्षण क्षेत्रों तक विस्तारित किए जा सकते हैं।

### सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बारे में

- इसके फरवरी 2024 के आदेश के अनुसार, आसन आर्द्रभूमि के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।
- इसके लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति या पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी।
- समानता सुनिश्चित करने के लिए ये सुरक्षा उपाय अन्य आर्द्रभूमि एवं सामुदायिक संरक्षण क्षेत्रों पर भी लागू हो सकते हैं।
- प्रतिबंध लागू करने से पहले विशेषज्ञ अधिकारियों को यह निर्धारित करना होगा कि आसन आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है या नहीं।

### आसन आर्द्रभूमि एवं नियामक ढाँचे के बारे में

- आसन आर्द्रभूमि उत्तराखंड में आसन-यमुना के संगम पर स्थित है और 2020 में इसे रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ।
- न तो रामसर कन्वेंशन और न ही आर्द्रभूमि नियम, 2017 में एक समान (समरूप) वैधानिक बफर निर्धारित किया गया है।
- 2017 के नियम राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों को सशक्त बनाते हैं और 2010 के नियमों में निहित विस्तृत प्रतिबंधों का स्थान लेते हैं।
- राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के एक किलोमीटर के दायरे में खनन निषिद्ध है, जब तक कि कोई बड़ा पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र लागू न हो।
- वन भूमि पर खनन के लिए केंद्रीय अनुमोदन और प्रायः 2006 की अधिसूचना के तहत पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है।

## थामिरबरानी नदी

### संदर्भ

मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धार्मिक समारोहों से थामिरबरानी नदी में असनुष्ठानिक अपशिष्ट फेंकने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

### थामिरबरानी नदी के बारे में

- थामिरबरानी पूरी तरह से तमिलनाडु के भीतर बहने वाली एक दुर्लभ बारहमासी नदी है।
- इसे ताम्रपर्णी और पोरुनई भी कहा जाता है। इसका नाम इसके पानी के तांबे जैसे रंग को दर्शाता है।
- यह पश्चिमी घाट की पोथिगई पहाड़ियों में स्थित अगस्त्यर्कूडम शिखर से उत्पन्न होती है।
- यह नदी लगभग 128 किलोमीटर तक बहती है, पहले उत्तर की ओर और फिर तिरुनेलवेली और थूथुकुडी से होते हुए पूर्व की ओर।
- यह मन्नार की खाड़ी में गिरती है और दक्षिण-पश्चिम एवं उत्तर-पूर्व दोनों मानसूनों से पानी प्राप्त करती है।
- प्रमुख सहायक नदियों में सर्वलार, मणिमुथर, गदाननाथी, पचौयार, चित्तार, रामनाथी और कोरैयार शामिल हैं।
- यह अपने ऊपरी मार्ग पर बानातीर्थम, अगस्तियार और कल्याण तीर्थम झरने का निर्माण करती है।
- महत्त्वपूर्ण बाँधों में पापनासम, करैयार, मणिमुथर, सर्वलार एवं गदाननाथी शामिल हैं। इस नदी में मछलियों की असाधारण रूप में समृद्ध विविधता पाई जाती है और यह विशेष रूप से देशी स्नेकहेड मछलियों के लिए प्रसिद्ध है।
- यह भारत के तीन ऊदबिलाव (Otter) प्रजातियों का समर्थन करती है, जिसमें यूरेशियन, स्मूथ-कोटेड और एशियाई छोटे पंजे वाले ऊदबिलाव शामिल हैं।

❑❑❑

IAS ACADEMY YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

# अर्थव्यवस्था



## संपादकीय

### हथकरघा- भारत की विरासत को वैश्विक विकास में पिरोना

'हैंडलूम- भारत की विरासत को वैश्विक विकास में पिरोना' (Handloom–weaving India's heritage into global growth) शीर्षक वाला यह संपादकीय 7 अगस्त, 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसमें नीति, प्रौद्योगिकी एवं वैश्विक बाज़ार एकीकरण के माध्यम से भारत की हथकरघा विरासत को रूपांतरित करने पर प्रकाश डाला गया है।

#### रणनीतिक एवं सामाजिक-आर्थिक महत्त्व

- हथकरघा सांस्कृतिक विरासत को आत्मनिर्भरता, संधारणीयता, ग्रामीण उद्यम व वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़कर विकसित भारत 2047 को आगे बढ़ाता है।
- भारत की वस्त्र विरासत में सिंधु घाटी कपास, बंगाल मलमल, बनारसी रेशम, कांचीपुरम बुनाई और पोचमपल्ली इकत शामिल हैं जो ब्रांड इंडिया का समर्थन करते हैं।
- प्रामाणिक और टिकाऊ उत्पादों की बढ़ती मांग भारत को हस्तशिल्प, नवाचार एवं विश्वास को हस्तनिर्मित उत्पादों व मज़बूत आपूर्ति शृंखलाओं के माध्यम से निर्यात करने का अवसर प्रदान करती है।
- भारत का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग 35 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करता है जिनमें से लगभग 72% महिलाएँ हैं, जिससे समावेशी आजीविका को मज़बूती मिलती है।

#### नीति और संस्थागत समर्थन

- कच्चा माल आपूर्ति योजना, 797 क्लस्टर और 1.24 लाख से अधिक उन्नत करघों ने उत्पादन अवसंरचना को मज़बूत किया है।
- कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 97,000 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है जबकि उत्पादक कंपनियाँ और जीआई-टैग वाले उत्पाद संगठन व बाज़ार पहचान को बढ़ावा देते हैं।
- हैंडलूम मार्क, इंडिया हैंडमेड सर्टिफिकेशन, अर्बन हाट और डिजाइन रिसोर्स सेंटर प्रामाणिकता, दृश्यता एवं बाज़ार तक पहुँच को बढ़ावा देते हैं।
- उनतीस बुनकर सेवा केंद्र प्रशिक्षण, डिजाइन, सामग्री और बाज़ार संपर्क प्रदान करते हैं जबकि 11 संस्थान उन्नत हथकरघा प्रशिक्षण का विस्तार करते हैं।
- राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम 500 से अधिक जिलों में फैले 1,800 समूहों को मज़बूत करेगा, जिससे 65 लाख कारीगरों को लाभ होगा और 'हैंडमेड इन इंडिया' ब्रांड का निर्माण होगा।

#### प्रौद्योगिकी-आधारित वैश्विक परिवर्तन

- गांधीजी के अंबर चरखे से लेकर असम के मैना करघे और चित्ररंजन हथकरघा तक के नवाचारों ने उत्पादकता एवं आत्मनिर्भरता में सुधार किया है।
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हल्के, मज़बूत एवं सुलभ करघों का विकास कर रहा है जबकि हैंडलूम 4.0 परियोजना 100 करघों पर एआई-आधारित निगरानी का परीक्षण कर रही है।
- प्रौद्योगिकी को कारीगरों को सशक्त बनाना चाहिए; VisioNXT मांग का पूर्वानुमान लगा सकता है, उत्पादों की प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकता है, प्रवृतियों की पहचान कर सकता है और बुनकरों को वैश्विक बाज़ारों से जोड़ सकता है।
- प्रीमियम रेशम, प्राकृतिक रेशे, टिकाऊ सामग्री एवं अभिनव मिश्रण उच्च मूल्य वाले उत्पाद बना सकते हैं और नए बाज़ार क्षेत्रों को खोल सकते हैं।
- बेहतर ब्रांडिंग, मूल्यवर्धन और प्रत्यक्ष बिक्री से बुनकरों की आय को प्रति माह ₹50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, उनकी उद्यमशीलता की भूमिका को भी संरक्षित किया जा सकता है।

### संपादकीय के अतिरिक्त

#### *हथकरघा क्षेत्र में लगातार बनी रहने वाली संरचनात्मक चुनौतियाँ*

- **आय संबंधी संकट :** हथकरघा की सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्ता के बावजूद चौथी हथकरघा गणना में पाया गया कि 66.3% बुनकर परिवारों की मासिक आय ₹5,000 से कम है।
- **अल्प-रोज़गार :** बुनकरों का औसत वार्षिक कार्य दिवस केवल 208 था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में घटकर 201 दिन और शहरी क्षेत्रों में 262 दिन रह गया था।
- **उत्पादन का विखंडन :** हथकरघा श्रमिकों में से लगभग 73.2% स्वतंत्र रूप से काम करते थे, जबकि केवल 6.3% सहकारी समितियों के माध्यम से काम करते थे, जिससे सामूहिक सौदेबाजी और खरीद क्षमता कमजोर हो गई।
- **बाज़ार अपवर्जन :** लगभग 64.1% माल खुले बाज़ारों के माध्यम से और 17.6% माल कुशल बुनकरों के माध्यम से बेचा गया, जबकि ई-कॉमर्स और निर्यात में भागीदारी नगण्य रही।
- **पावरलूम की नकल :** हथकरघा आरक्षण अधिनियम, 1985 के बावजूद सस्ते मशीन से बने उत्पाद बनारसी साड़ियों जैसे प्रामाणिक उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करना जारी रखे हुए हैं।
- **सामाजिक भेद्यता :** जनगणना के अनुसार, हथकरघा कामगारों के 60.2% परिवार कच्चे घरों में रहते हैं जबकि केवल लगभग 4% कामगारों के पास ही बीमा कवरेज है।
- **पीढ़ीगत गिरावट :** 18-35 आयु वर्ग के ग्रामीण बुनकरों का हिस्सा 2009-10 में 50% से घटकर 2019-20 में 43% हो गया है जिससे कौशल हस्तांतरण खतरे में पड़ गया है।

YOUR GUIDE TO THE CIVIL SERVICES

## MSME को क्लस्टर में समूहबद्ध करने के निहितार्थ

'एमएसएमई के लिए अवसर उन्हें क्लस्टर में संगठित करने में निहित है' (The MSME opportunity lies in clustering them) शीर्षक वाला यह संपादकीय 11 अगस्त, 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ। इसमें एमएसएमई को रोज़गार, उत्पादकता एवं निर्यात के इंजन में बदलने की कुंजी के रूप में क्लस्टर-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र विकास पर प्रकाश डाला गया है।

### सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) की क्षमता और संरचनात्मक बाधाएँ

- बढ़ती युवा बेरोज़गारी और एआई-संचालित व्यवधान के कारण बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) महत्त्वपूर्ण हो गए हैं।
- MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 विलंबित भुगतान, विवाद समाधान एवं अनुपालन संबंधी बोझ को संबोधित करता है किंतु गहरी संरचनात्मक कमजोरियों को अनसुलझा छोड़ देता है।
- भारत के 63 मिलियन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) 320 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं और जीडीपी में 31%, विनिर्माण उत्पादन में 35% और निर्यात में 49% का योगदान करते हैं।
- अपने विशाल आकार के बावजूद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनौपचारिक और खंडित बने हुए हैं जो निम्न मूल्य वाली गतिविधियों में केंद्रित हैं और किफायती ऋण तक उनकी पहुँच सीमित है।
- छोटे उद्यमों को जीएसटी, श्रम, पर्यावरण और कराधान संबंधी आवश्यकताओं से जुड़े भारी अनुपालन बोझ का सामना करना पड़ता है।

### औद्योगिक क्लस्टर के आर्थिक लाभ

- अमेरिका और चीन ने अलग-थलग फर्म्स का समर्थन करने के बजाय आपूर्तिकर्ताओं, श्रमिकों, अनुसंधान संस्थानों और पूंजी को जोड़ने वाले सघन समूहों के माध्यम से औद्योगिक शक्ति का निर्माण किया।
- नॉर्थ कैरोलिना के रिसर्च ट्रायंगल ने विश्वविद्यालयों और उद्योग को आपस में जोड़ा है जिससे मज़बूत जैव-प्रौद्योगिकी और फार्मास्युटिकल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ।
- ग्वांगडोंग के औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि, बुनियादी ढाँचा और कर प्रोत्साहन का संयोजन है जिससे सघन आपूर्तिकर्ता नेटवर्क और तीव्र डिजाइनिंग, निर्माण और प्रोटोटाइपिंग संभव हो पाती है।
- क्लस्टर्स श्रमिकों की गतिशीलता, अनौपचारिक संवाद एवं साझा सेवा प्रदाताओं के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करते हैं। साथ ही, विशिष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करते हैं।
- साझा परीक्षण प्रयोगशालाएँ, उपचार संयंत्र, शीत भंडारण और रसद व्यवस्था से नियत लागत कम होती है और छोटी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है।
- चीन का लिटिल जायंट कार्यक्रम वित्त, कराधान एवं अनुसंधान सहायता के माध्यम से तकनीकी रूप से सक्षम विशिष्ट फर्मों का समर्थन करता है।

### पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण की दिशा में आवश्यक बदलाव

- MSME क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पीएम मित्र पार्क जैसी मौजूदा पहलें प्रायः संपूर्ण औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किए बिना बुनियादी ढाँचा प्रदान करती हैं।
- भारत को सामान्य औद्योगिक संपदाओं के स्थान पर पुणे में ऑटो कंपोनेंट्स और श्रीपेरुम्बुदुर में इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए विशिष्ट क्लस्टर स्थापित करने चाहिए।
- एक भारतीय लिटिल जायंट कार्यक्रम को छिपे हुए चैंपियनों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें समर्पित ऋण, तेजी से पेटेंट, अनुसंधान एवं विकास सहायता व खरीद में प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए।
- क्लस्टर-आधारित ऋण साझा संपार्श्विक, क्रेता-आपूर्तिकर्ता संबंधों और सामूहिक प्रदर्शन का आकलन कर सकता है जिससे सूचना विषमता एवं वित्तीय जोखिम कम हो जाते हैं।
- तिरुप्पुर कपड़ा क्लस्टर मॉडल को सिडबी (SIDBI) और विशेष रूप से क्लस्टर वित्तपोषण पर केंद्रित एनबीएफसी (NBFC) के माध्यम से विस्तारित किया जा सकता है।
- विश्वविद्यालयों को सफल चीनी और अमेरिकी मॉडलों का अनुसरण करते हुए कुशल प्रतिभा, प्रयोगशाला अवसंरचना और नवाचार प्रदान करके सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर्स के समूहों को मज़बूत आधार प्रदान करना चाहिए।

### संपादकीय के अतिरिक्त

#### *जलवायु-लचीले MSME क्लस्टर*

- **सामान्य हरित अवसंरचना :** MSE-CDP साझा परीक्षण केंद्रों एवं अपशिष्ट जल उपचार सुविधाओं का समर्थन करता है, जिससे छोटे क्लस्टर-आधारित उद्यमों के लिए पर्यावरणीय अनुपालन किफायती हो जाता है।
- **चक्रीय उत्पादन :** MSE-SPICE चक्रीय अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए 25% पूंजी सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे पुनर्चक्रण, सामग्री रिकवरी एवं उत्पादक अपशिष्ट पुनः उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है।
- **हरित वित्त :** MSE-गिफ्ट हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए 2% ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे संसाधन-सीमित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर वित्तपोषण का बोझ कम होता है।
- **जलवायु जोखिम योजना :** नीति आयोग के 2026 के MSME रोडमैप में संसाधनों की कमी, बढ़ती बीमा लागत और आपूर्ति में व्यवधान पर प्रकाश डाला गया है, जिसके लिए क्लस्टर-स्तर पर भेद्यता आकलन की आवश्यकता है।

- **निर्यात की तैयारी :** कार्बन लेखांकन और स्वच्छ उत्पादन सक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बहिष्कार से बचा सकते हैं क्योंकि वैश्विक खरीदार मूल्य शृंखलाओं में संधारणीयता संबंधी आवश्यकताओं को तेजी से लागू कर रहे हैं।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाना :** ADEETIE 60 औद्योगिक समूहों में फैले 14 ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को कवर करता है और ऑडिट, बैंक योग्य परियोजना रिपोर्ट एवं 3-5% ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करता है।
- **गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन :** MSME सस्टेनेबल ZED कार्यक्रम के तहत पात्र इकाइयों को परामर्श के लिए 2 लाख रुपये तक और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 3 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है।

## भारत के माल निर्यात में वृद्धि का विश्लेषण

'द हिंदू' में 18 अगस्त, 2026 को प्रकाशित संपादकीय 'भारत के माल निर्यात में वृद्धि का विश्लेषण' इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत की लगभग 20% माल निर्यात वृद्धि मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों द्वारा संचालित थी, न कि व्यापक विविधीकरण द्वारा।

### निर्यात प्रदर्शन और क्षेत्रवार कारक

- पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत का माल निर्यात जुलाई 2026 में 44.2 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20% अधिक है।
- आयात में निर्यात की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि होने के कारण व्यापार घाटा लगभग 28 अरब डॉलर से बढ़कर 32 अरब डॉलर हो गया।
- पेट्रोलियम उत्पादों का योगदान 2.8 बिलियन डॉलर या कुल निर्यात वृद्धि का 39% था, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का योगदान 30% और इंजीनियरिंग वस्तुओं का योगदान 25% रहा।
- अप्रैल-जुलाई 2026 के दौरान पेट्रोलियम निर्यात में 42.6% की वृद्धि हुई, जो 21 बिलियन डॉलर से बढ़कर 30 बिलियन डॉलर हो गया, जो ईरान संघर्ष के बाद बढ़ी कीमतों को दर्शाता है।
- इंजीनियरिंग निर्यात में 18.2% की वृद्धि हुई और यह 46.4 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान में 30.7% की वृद्धि हुई और यह 21.2 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जिससे सीमित क्षेत्रीय विविधीकरण को समर्थन मिला।
- समुद्री उत्पादों में लगभग 18%, मांस, डेयरी एवं मुर्गी उत्पादों में 41% और हस्तशिल्प में 16% की वृद्धि हुई, जो व्यापक किंतु छोटे निर्यात लाभों को दर्शाता है।

### बाज़ार संरचना और विविधीकरण

- नए टैरिफ लागू होने के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाज़ार बना रहा, जहाँ निर्यात का लगभग पाँचवां हिस्सा जाता है जबकि सिंगापुर का हिस्सा 2.7% से बढ़कर 4.7% हो गया।
- पश्चिम एशिया संकट के कारण चीन की हिस्सेदारी लगभग स्थिर रही है जबकि संयुक्त अरब अमीरात की हिस्सेदारी 8.5% से घटकर 6.5% हो गई।
- दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, श्रीलंका, मलेशिया और केन्या को निर्यात में सबसे तेजी से वृद्धि हुई किंतु यह बाज़ार विस्तार मुख्य रूप से परिष्कृत पेट्रोलियम द्वारा संचालित था।
- भारत के निर्यात में तंजानिया की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी होकर 1.1% से 2% हो गई, हालाँकि इसके निर्यात मूल्य में वृद्धि में पेट्रोलियम का दबदबा रहा।
- वियतनाम और ताइवान को निर्यात में वृद्धि पेट्रोलियम-प्रेरित नहीं थी; क्षेत्रीय तनावों में किसी भी प्रकार की कमी से निर्यात विविधीकरण की वास्तविक सीमा का पता चलेगा।

### संपादकीय के अतिरिक्त

#### *निर्यात में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना*

- **मूल्यवर्धित मापन :** 2025-26 में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा विशिष्ट निर्यात बन गया किंतु इलेक्ट्रॉनिक्स में घरेलू मूल्यवर्धन लगभग 18-20% ही रहा, जो आयातित इनपुट पर इसकी पर्याप्त निर्भरता को दर्शाता है।
- **घटक पारिस्थितिकी तंत्र :** इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का उद्देश्य सब-असेंबली और पार्ट्स के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना है जिससे निर्यात धीरे-धीरे अंतिम चरण की असेंबली से आगे बढ़ सके।
- **फार्मास्युटिकल अपग्रेडिंग :** बल्क-ड्रग पीएलआई के समर्थन से भारत को 2021-22 में 1,930 करोड़ रुपये के व्यापार घाटे से उबरने और 2024-25 तक 2,280 करोड़ रुपये के अधिशेष तक पहुँचने में मदद मिली।
- **जीवीसी एकीकरण :** आरबीआई ने पहले भारत की वैश्विक मूल्य शृंखला में भागीदारी का अनुमान सकल निर्यात के 34% के रूप में लगाया था, जबकि आसियान अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह 45.9% था।
- **MSME की क्षमता :** नवंबर 2024 तक 176 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पीएलआई योजनाओं में भाग ले रही हैं, जिससे विस्तारित परीक्षण, प्रमाणीकरण और प्रौद्योगिकी सहायता के माध्यम से छोटे उद्यमों को निर्यात आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत किया जा सकेगा।
- **ब्रांडिंग की क्षमता :** 2026 की एक संसदीय समिति ने रत्नों के निर्यात को उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों की ओर मोड़ने के लिए डिजाइनर आभूषणों, ब्रांडेड उत्पादों एवं प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी।
- **व्यापार संरचना :** भारत-ईयू व्यापार समझौते के तहत उत्पत्ति के नियमों में निर्दिष्ट घरेलू प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है जो निर्यातकों को आयातित इनपुट को केवल पुनः निर्यात करने के बजाय स्थानीय मूल्य निर्माण के लिए प्रोत्साहित करता है।

## मुख्य परीक्षा

### प्रतिभूति बाज़ार संहिता विधेयक, 2025

#### संदर्भ

वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रतिभूति बाज़ार संहिता विधेयक, 2025 में महत्त्वपूर्ण संशोधनों की सिफारिश की।

#### प्रतिभूति बाज़ार संहिता विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान

- **कानूनी समेकन :** यह विधेयक प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956; सेबी अधिनियम, 1992 और डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 को समेकित, तर्कसंगत और प्रतिस्थापित करते हुए एक एकीकृत ढाँचा प्रस्तुत करता है।
- **सेबी बोर्ड का विस्तार :** बोर्ड में सदस्यों की संख्या 9 से बढ़कर 15 हो जाएगी, जिसमें अध्यक्ष, एक आरबीआई अधिकारी, दो सरकारी अधिकारी और 11 अन्य सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम पांच पूर्णकालिक सदस्य होंगे।
- **प्रतिनिधि पंजीकरण :** सेबी अपने पंजीकरण कार्यों के कुछ हिस्सों को एमआईआई (MII) और एसआरओ (SRO) को सौंप सकता है, जिससे विशेषीकृत संस्थानों को अधिक कुशल बाज़ार विनियमन में सहायता करने में सक्षम बनाया जा सके।
- **सरलीकृत ढाँचा :** यह विधेयक अप्रचलित प्रावधानों को हटाता है, दोहराव को कम करता है, कानूनी भाषा को सरल बनाता है और प्रतिभूति बाज़ारों में एक समान नियामक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है।
- **प्रतिभूतियों की व्यापक परिभाषा :** इस परिभाषा में हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स, जीरो-कूपन जीरो-प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स और बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए ऑनशोर रुपी बॉण्ड शामिल हैं।
- **संघर्ष सुरक्षा उपाय :** सेबी के सदस्यों को अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक हितों का खुलासा करना होगा, संबंधित मामलों से खुद को अलग रखना होगा और यदि वित्तीय हित उनके कार्यों को प्रभावित करते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है।
- **कार्यात्मक पृथक्करण :** यह विधेयक जाँच एवं न्यायनिर्णय को अलग करता है, जिससे उन चिंताओं का समाधान होता है कि वर्तमान में दोनों शक्तियाँ एक ही नियामक संगठन के अंतर्गत काम करती हैं।
- **आनुपातिक दंड :** बाज़ार के गंभीर दुरुपयोग, जिनमें इनसाइडर ट्रेडिंग एवं निवेशक धोखाधड़ी शामिल हैं, के लिए आपराधिक दायित्व बरकरार रहता है, जबकि मामूली या तकनीकी उल्लंघन नागरिक दंड में परिवर्तित हो जाते हैं।

#### विधेयक के संबंध में चिंताएँ

- **शक्तियों का केंद्रीकरण :** सेबी के पास नियम बनाने, कार्यकारी, जांच एवं न्यायनिर्णयन का अधिकार बरकरार है जिससे शक्तियों के पृथक्करण, संस्थागत नियंत्रण और संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
- **अत्यधिक प्रत्यायोजन :** नियामक दायरे, पंजीकरण, दंड, छूट एवं प्रतिभूतियों की परिभाषा जैसे मुख्य मामले अधीनस्थ कानूनों पर छोड़ दिए गए हैं।
- **कमजोर संसदीय निगरानी :** कार्यपालिका एवं सेबी को दिए गए व्यापक विवेकाधिकार से संसद की भूमिका ठोस कानून बनाने से घटकर केवल एक सक्षम ढाँचा स्थापित करने तक सीमित हो सकती है।
- **कठोर प्रवर्तन :** तलाशी, जब्ती, संपत्ति कुर्क करने, बैंक खाते फ्रीज करने और एकतरफा अंतरिम आदेश जारी करने की शक्तियों का प्रयोग पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के बिना किया जा सकता है।

#### भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के बारे में

- सेबी का गठन अप्रैल 1988 में एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में हुआ था और इसे सेबी अधिनियम के तहत 12 अप्रैल, 1992 को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
- यह वित्त मंत्रालय के अधीन भारत का प्रमुख प्रतिभूति बाज़ार नियामक एवं पूंजी बाज़ार निगरानी निकाय है।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एवं दिल्ली में स्थित हैं।
- इसके नौ सदस्यों में अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय के दो अधिकारी, आरबीआई का एक प्रतिनिधि और सरकार द्वारा नियुक्त पांच सदस्य शामिल हैं जिनमें कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं।

#### संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें

- **अधिक स्पष्ट प्रस्तावना :** प्रस्तावना में संशोधन करके इस बात पर स्पष्ट रूप से जोर दिया जाए कि निवेशक संरक्षण, बाज़ार विकास और प्रभावी विनियमन इस विधेयक के केंद्रीय उद्देश्य हैं।
- **अपराधों पर संसदीय नियंत्रण:** विनियमों के माध्यम से आपराधिक जुर्म की सेबी की शक्ति को समाप्त किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल संसद ही कानून के माध्यम से आपराधिक दायित्व को परिभाषित करे।
- **पूर्व जाँच सूचना :** पूर्व सूचना को सामान्य नियम बनाया जाएँ, सिवाय उन मामलों के जहाँ इससे साक्ष्यों को नष्ट करने, छिपाने या उनमें हेरफेर करने की संभावना हो सकती है।
- **लोकपाल की समयरेखा :** लोकपाल के समक्ष निवेशकों की शिकायतों का सामान्यत: 120 दिनों के भीतर समाधान करना अनिवार्य हो, जिससे शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित हो सके।
- **सेबी अधिशेष हस्तांतरण :** सेबी की संस्थागत स्वतंत्रता और जवाबदेही की रक्षा करते हुए सेबी के अधिशेष हिस्से को भारत की समेकित निधि में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को बरकरार रखा जाए।

## विकास के इंजन के रूप में शहर

### संदर्भ

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और अर्न्स्ट एंड यंग (EY) ने 'विकास इंजन के रूप में शहर' नामक रिपोर्ट जारी की।

### भारत में शहरीकरण की स्थिति

- **बस्ती का स्वरूप :** भारत में एक बहुस्तरीय शहरी प्रणाली है जिसमें प्रमुख महानगर केंद्र और 7,400 से अधिक शहर एवं कस्बे शामिल हैं।
- **आर्थिक योगदान :** शहरों में लगभग एक-तिहाई आबादी रहती है किंतु वे जीडीपी का 60% उत्पन्न करते हैं, जिसके 2050 तक 75% तक पहुँचने का अनुमान है।

### क्षेत्रीय विकास के इंजन के रूप में शहर

- **क्षेत्रीय समूह :** सैटेलाइट शहर महानगरों की अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार करते हैं। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर के प्रमुख औद्योगिक व व्यावसायिक केंद्र हैं।
- **नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र :** विश्वविद्यालय और प्रौद्योगिकी पार्क अनुसंधान एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देते हैं। हैदराबाद की जीनोम वैली में 18 देशों की 200 से अधिक जीवन विज्ञान कंपनियाँ स्थित हैं।
- **सेवा-आधारित विकास :** बेंगलुरु, दिल्ली एवं हैदराबाद कुशल श्रमिकों को आकर्षित करते हैं जिससे सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त व पेशेवर सेवाओं में मज़बूत श्रम बाज़ार का निर्माण होता है।
- **क्षेत्रीय संपर्क :** पुणे एवं अहमदाबाद की मेट्रो प्रणालियाँ आवागमन को बेहतर बनाती हैं। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से बाज़ार तक पहुँच और अंतरराज्यीय आर्थिक एकीकरण को मज़बूती मिलती है।
- **सतत विकास :** वर्षा जल संचयन, हरित भवन और स्मार्ट जल प्रणालियाँ संसाधन दक्षता में सुधार करती हैं। सभी 100 स्मार्ट शहरों में डेटा-आधारित कमांड और नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- **अचल संपत्ति में निवेश :** निर्माण कार्य से रोज़गार एवं पूंजी निर्माण होता है। कोलियर्स का अनुमान है कि रेरा (RERA) और जीएसटी (GST) के समर्थन से 2024 में संस्थागत रियल एस्टेट निवेश 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- **नीतिगत समर्थन :** 'अमृत योजन' जल एवं सीवरेज सेवाओं में सुधार करती है जबकि पारगमन-उन्मुख विकास परिवहन और भूमि उपयोग को एकीकृत करता है, जैसा कि भोपाल व वाराणसी में शहरी परियोजनाओं में परिलक्षित होता है।

### भारतीय शहरों के समक्ष समस्याएँ

- **वित्तीय बाधाएँ :** जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम बुनियादी ढाँचे के लिए शहरों को 2050 तक लगभग 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, जबकि नगरपालिकाओं का राजस्व जीडीपी का लगभग 0.6% ही रहता है, जिससे आवश्यक सेवाओं में निवेश सीमित हो जाता है।
- **पूंजी तक सीमित पहुँच :** केवल 20 नगर निगमों ने पूंजी बाज़ारों तक पहुँच बनाई है, जिससे लगभग 476 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए गए हैं; वडोदरा का 2024 का ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड अभिनव वित्तपोषण की क्षमता को दर्शाता है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी :** 2047 तक आवश्यक शहरी बुनियादी ढाँचे का लगभग 70% हिस्सा अभी भी निर्माणाधीन है, जबकि विश्व बैंक का अनुमान है कि 15 वर्षों में 840 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी।
- **असमान शहरीकरण :** शीर्ष दस शहर जीडीपी का लगभग 30% उत्पन्न करते हैं, जबकि अवैध आप्रवासन सहित तीव्र प्रवासन और दिल्ली में भीषण गर्मी तथा बेंगलुरु में बाढ़ जैसी जलवायु संबंधी आपदाएँ शहरी दबाव को अधिक बढ़ा देती हैं।
- **परिवहन का दबाव :** मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली एवं पुणे में अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन और निजी वाहनों की बढ़ती संख्या उत्पादकता को कम करती है और प्रदूषण को बढ़ाती है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन संकट :** कचरे के अपर्याप्त पृथक्करण और पुनर्चक्रण से लैंडफिल पर अत्यधिक दबाव पड़ता है; दिल्ली में प्रतिदिन 10,000 टन से अधिक कचरा उत्पन्न होता है, जिससे गाजीपुर, भलस्वा व ओखला लैंडफिल पर बोझ बढ़ जाता है।
- **प्रशासनिक बिखराव :** एजेंसियों के बीच परस्पर संबंध एवं नौकरशाही की देरी जवाबदेही को कमजोर करती है और परियोजनाओं को धीमा करती है, जैसा कि मुंबई के मेट्रो और तटीय सड़क विकास में देखा गया है।

### आगे की राह : छः रणनीतिक बदलाव

- **आर्थिक नेतृत्व के लिए सेवा वितरण :** शहरी संस्थानों को नागरिक सेवाओं के साथ-साथ निवेश आकर्षित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और रोज़गार सृजित करना चाहिए। GIFT सिटी यह दर्शाता है कि किस प्रकार नियोजित शहरी पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक वित्तीय केंद्र बन सकते हैं।
- **बहुकेंद्रीय वृद्धि की ओर केंद्रित :** टियर II एवं टियर III स्तर के शहरों को क्षेत्रीय विकास केंद्रों के रूप में विकसित करना; कोयंबटूर, इंदौर और गुवाहाटी जैसे शहरों में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों का विस्तार विकेंद्रीकृत विकास को बढ़ावा देता है।
- **निवेश के लिए तैयार शहरों पर वित्तीय निर्भरता :** नगरपालिकाओं की साख, पूंजी बाज़ार तक पहुँच और परिसंपत्ति मुद्रीकरण को मज़बूत करना; इंदौर नगर निगम ने 2023 में एक सौर ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से ₹244 करोड़ जुटाए।
- **प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अवसंरचना निर्माण :** परियोजनाओं का मूल्यांकन केवल निर्मित संपत्तियों के आधार पर नहीं, बल्कि उत्पादकता, गतिशीलता, रोज़गार और जीवन की गुणवत्ता जैसे

परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इस प्रकार के परिणाम-आधारित शहरी मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है।

- **डेटा संग्रह से लेकर आर्थिक जानकारी तक :** योजना और निवेश संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए एआई और उन्नत विश्लेषण का उपयोग करना; उम्मीद (UMEED) डैशबोर्ड पहले से ही 2,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों से प्रदर्शन डेटा एकत्रित करता है।
- **जलवायु संबंधी भेद्यता से लचीलापन तक :** निवासियों और निवेशों की सुरक्षा के लिए शहरी नियोजन में गर्मी, बाढ़ एवं जल संबंधी जोखिमों को एकीकृत करना; 2013 में शुरू की गई अहमदाबाद की हीट एक्शन प्लान एक प्रारंभिक चेतावनी मॉडल प्रदान करती है।

## प्रारंभिक परीक्षा

## कोर उद्योग सूचकांक : नई 2022–23 शृंखला

### संदर्भ

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने 2022-23 आधार वर्ष शृंखला के तहत पहला अनंतिम कोर उद्योग सूचकांक (ICI) जारी किया।

### कोर उद्योग सूचकांक के बारे में

- कोर उद्योग सूचकांक (ICI) भारत के मूलभूत औद्योगिक क्षेत्रों में मासिक उत्पादन को मापता है।
- अनंतिम सूचकांक प्राय: अगले महीने की 20 तारीख या अगले कार्य दिवस पर जारी की जाती है।
- 2022-23 की शृंखला 2011-12 की शृंखला का स्थान लेती है और अप्रैल 2023 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होती है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कोर उद्योग का भारांश अब 32.88% है जबकि पहले यह 40.27% था।

| क्रमांक | सेक्टर | भारांश (%) |
|---|---|---|
| 1 | कोयला | 5.596 |
| 2 | प्राकृतिक गैस | 3.841 |
| 3 | कच्चा तेल | 7.430 |
| 4 | रिफाइनरी उत्पाद | 22.572 |
| 5 | उर्वरक | 2.731 |
| 6 | इस्पात | 17.584 |
| 7 | सीमेंट | 4.410 |
| 8 | बिजली | 30.932 |
| 9 | लौह अयस्क | 4.905 |
| | **समग्र सूचकांक** | **100.000** |

### नई शृंखला में बदलाव

- लौह अयस्क को शामिल करने से कोर उद्योग क्षेत्रों का विस्तार आठ से बढ़कर नौ क्षेत्रों तक हो जाता है।
- इनमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली एवं लौह अयस्क शामिल हैं।
- अब इस्पात सूचकांक शुद्ध उत्पादन के बजाय सकल उत्पादन का उपयोग करता है, जिससे यह संशोधित IIP के अनुरूप हो जाता है।
- केवल कच्चे कोयले (Raw Coal) को ही रखा गया है; दोहरी गणना से बचने के लिए धौत कोयले (Washed Coal) और कोल मिड्लिंग को हटा दिया गया है।
- क्षेत्रवार भारांश 2022-23 IIP शृंखला से प्राप्त किए गए हैं और आनुपातिक रूप से 100 के बराबर सामान्यीकृत किए गए हैं।
- बिजली (30.93%), रिफाइनरी उत्पादों (22.57%) और स्टील (17.58%) का भारांश सबसे अधिक है।
- अन्य भारांशों में कच्चा तेल (7.43%), कोयला (5.59%), लौह अयस्क (4.90%), सीमेंट (4.41%), प्राकृतिक गैस (3.84%) और उर्वरक (2.73%) शामिल हैं।
- समग्र लिंकिंग फैक्टर 1.47 है जो पुरानी और नई शृंखलाओं के बीच तुलना को सक्षम बनाता है।
- यह 2022-23 के दौरान मासिक ICI के पुराने व नए ज्यामितीय माध्य के अनुपात के बराबर है।

## मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन समझौता

### संदर्भ

भारत मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 123वाँ विश्व व्यापार संगठन (WTO) सदस्य बन गया है जिससे वह औपचारिक रूप से इसका पक्षकार बन गया है।

### मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते के बारे में

- यह पहला डब्ल्यूटीओ (WTO) समझौता है जो मुख्य रूप से पर्यावरणीय संधारणीयता पर केंद्रित है।
- इसे जून 2022 में जिनेवा में आयोजित 12वें विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाया गया।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद यह 15 सितंबर, 2025 को लागू हुआ।
- यह ऐसे बाध्यकारी नियम स्थापित करता है जो सरकारी सब्सिडी को समुद्री मत्स्य संसाधनों की स्थिरता को कमजोर करने से रोकते हैं।
- इसमें समुद्री वन्य-मत्स्यन और समुद्र में की जाने वाली मत्स्यन संबंधी गतिविधियों को शामिल किया गया है।

IAS ACADEMY YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

- जलीय कृषि और अंतर्देशीय मत्स्य पालन को इस समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है।
- यह अवैध, बिना सूचना दिए और अनियमित मत्स्यन और अत्यधिक मात्रा में पकड़ी गई मछलियों के भंडार में मछली पकड़ने का समर्थन करने वाली सब्सिडी पर रोक लगाता है।
- यह विकासशील एवं अल्पविकसित देशों, विशेष रूप से पारंपरिक और छोटे पैमाने के मछुआरों के लिए उपयुक्त लचीलापन प्रदान करता है।
- बड़े औद्योगिक मछली पकड़ने वाले बेड़ों को दी जाने वाली हानिकारक सब्सिडी को कम करने से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और टिकाऊ मत्स्यन को बढ़ावा मिलता है।

## निफ्टी 500 अहिंसा सूचकांक

### संदर्भ

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी 'एनएसई सूचकांक (NSE Indices)' ने अहिंसा पर आधारित नैतिक निवेश मानदंड प्रदान करने के लिए इस सूचकांक को लॉन्च किया है।

### निफ्टी 500 अहिंसा सूचकांक के बारे में

- यह निफ्टी 500 कंपनियों को ट्रैक करता है जिनके उत्पाद, सेवाएँ एवं कार्यप्रणाली जानवरों को जान-बूझकर होने वाले नुकसान को कम करती हैं।
- अहिंसागेन फाउंडेशन (Ahimsagain foundation) के सहयोग से विकसित यह परियोजना अहिंसा इन्वेस्टमेंट मूवमेंट (AIM) ढाँचे का अनुसरण करती है।
- यह ढाँचा पशु-संबंधी व्यावसायिक प्रथाओं के आधार पर कंपनियों को ग्रीन, ऑरेंज एवं रेड श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।
- समीक्षा तिथि पर निफ्टी 500 में शामिल केवल ग्रीन श्रेणी की कंपनियाँ ही इसमें शामिल होने के लिए पात्र हैं।
- प्रत्येक घटक का भारांश उसके फ्री-फ्लोट बाज़ार पूंजीकरण के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।
- इसकी आधार तिथि 1 अप्रैल, 2016 है और इसका आधार मूल्य 1,000 है।
- इस सूचकांक की समीक्षा हर छः महीने में मार्च एवं सितंबर में की जाती है।
- इसमें शुरू में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में फैली 326 कंपनियाँ शामिल थीं।
- ऑटोमोबाइल क्षेत्र 13.05% के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद पूंजीगत वस्तुएँ (12.20%), सूचना प्रौद्योगिकी (11.80%) और वित्तीय सेवाएँ (10.35%) रहीं।
- अन्य क्षेत्रों में धातु, दूरसंचार, बिजली, ईंधन, निर्माण सामग्री, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ, स्वास्थ्य सेवा और सेवाएँ शामिल हैं।
- प्रमुख घटकों में भारती एयरटेल, इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मारुति सुजुकी, एनटीपीसी, बीएसई, टाटा स्टील, हिंडाल्को और अदानी पोर्ट्स शामिल हैं।

## निर्यात के लिए इन्वेंटरी-आधारित ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

### संदर्भ

सरकार ने भारत निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए ही इन्वेंट्री-आधारित ई-कॉमर्स में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है।

### ई-कॉमर्स मॉडलों के बारे में

- इन्वेंट्री-आधारित मॉडल में ई-कॉमर्स इकाई उत्पादों का स्वामित्व रखती है और उन्हें सीधे उपभोक्ताओं को बेचती है।
- मार्केटप्लेस मॉडल के तहत यह इकाई इन्वेंट्री का स्वामित्व रखे बिना स्वतंत्र विक्रेताओं को खरीदारों से जोड़ती है।

### संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के बारे में

- विदेशी वित्त पोषित इन्वेंट्री संस्थाएँ केवल भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं का ही निर्यात कर सकती हैं।
- विदेशी वित्त पोषित इन्वेंट्री-आधारित घरेलू व्यापार-से-उपभोक्ता खुदरा व्यापार पर प्रतिबंध अपरिवर्तित रहेगा।
- इस छूट से यह स्पष्ट होता है कि इन्वेंट्री संबंधी प्रतिबंध घरेलू खुदरा बिक्री पर लागू होते हैं, न कि केवल निर्यात-उन्मुख कार्यों पर।
- 2016 से मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।
- वर्ष 2000 से बिजनेस-टू-बिजनेस ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।
- यह नीति भारतीय निर्माताओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, विशेष रूप से टियर-II व टियर-III शहरों में स्थित उद्यमों के लिए वैश्विक बाज़ार तक पहुँच का विस्तार करती है।

## भारत में व्यापार सुगमता

### संदर्भ

संसद की वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति ने व्यापार सुगमता (EoDB) पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका उद्देश्य व्यापार के पूरे जीवनचक्र में अनावश्यक नियामक बोझ को कम करना है।

LK ACADEMY YOUR GUIDE TO THE FINAL MILESTONE

## रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है जो 2015 में 190 अर्थव्यवस्थाओं के बीच 142वें स्थान से बढ़कर 2020 में 63वें स्थान पर पहुँच गई।
- आईएमडी (IMD) वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, 2022 में भारत 63 अर्थव्यवस्थाओं में छः पायदान ऊपर चढ़कर 37वें स्थान पर पहुँच गया है।
- मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2016 में 502 से बढ़कर 2026 तक 2.23 लाख से अधिक हो जाएगी, जिससे 23.3 लाख औपचारिक नौकरियाँ सृजित होंगी।
- 'डिस्ट्रिक्ट एस एक्सपोर्ट हब' पहल के तहत जिला स्तर पर नियामक सरलीकरण और आपूर्ति-शृंखला अवसंरचना को बेहतर बनाने का काम किया जाता है।

## मुद्दे और सिफारिशें

| मुद्दा | सिफारिश |
|---|---|
| ओवरलैपिंग कानूनों, लाइसेंसों व अनुपालनों के नियामक विखंडन से व्यावसायिक लागत बढ़ जाती है। | लाइसेंसों का विलय करना, एक लाइसेंस, एक नवीनीकरण प्रणाली लागू करना और जोखिम-आधारित विनियमन को अपनाना। |
| राज्य व स्थानीय सुधार में कमजोरी प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों के बाहर सुधारों को सीमित करती है। | जिला व्यापार सुधार कार्य योजना का विस्तार करना और अनुमोदनों को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत करना। |
| अनुमोदन में देरी से लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र और नवीनीकरण प्रभावित होते हैं। | समयबद्ध प्रक्रिया, स्वीकृत अनुमोदन और स्वचालित नवीनीकरण की व्यवस्था शुरू करना। |
| राज्यों में असमान कार्यान्वयन से रिपोर्ट किए गए सुधारों व व्यावसायिक अनुभव के बीच अंतर पैदा होता है। | जमीनी हकीकत का सत्यापन और तृतीय-पक्ष ऑडिट के माध्यम से व्यापार सुधार कार्य योजना को परिणाम-आधारित बनाना। |
| एमएसएमई ऋण बाधाएँ संपार्श्विक आवश्यकताओं और व्यापक दस्तावेजीकरण से उत्पन्न होते हैं। | उद्यम पंजीकरण, ऋण गारंटी, बिना गिरवी के ऋण और नकदी प्रवाह आधारित वित्तपोषण का विस्तार करना। |
| निर्यात और सीमा शुल्क संबंधी अड़चन से खंडित प्रक्रियाओं के कारण मंजूरी में देरी होती है। | व्यापार प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित मंजूरी प्रणाली के साथ भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे को उन्नत करना। |

## फ्लोटिंग-रेट लोन

### संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक ने 'लोन एवं एडवांस ब्याज दर निर्देश, 2026' का प्रस्ताव रखा है जिससे फ्लोटिंग-रेट लोन में पारदर्शिता और विनियमन मज़बूत होगा।

### फ्लोटिंग-रेट लोन के बारे में

- इनकी ब्याज दर किसी निर्दिष्ट आंतरिक या बाहरी बेंचमार्क में होने वाले बदलावों के अनुसार समय-समय पर बदलती रहती है।
- लागू दर में प्रायः बेंचमार्क दर एवं ऋणदाता द्वारा निर्धारित स्प्रेड शामिल होता है।
- रेपो दर विनियमित ऋणदाताओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के लिए एक बाह्य मानदंड के रूप में काम कर सकती है।
- इन्हें परिवर्तनीय या समायोज्य दर वाले ऋण भी कहा जाता है और ये प्रायः बंधक व उपभोक्ता ऋणों पर लागू होते हैं।

### फिक्स्ड-रेट एवं फ्लोटिंग-रेट लोन

| आधार | फिक्स्ड-रेट लोन | फ्लोटिंग-रेट लोन |
|---|---|---|
| **अर्थ** | निर्धारित ऋण अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहता है। | मानक दर और बाज़ार की स्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते हैं। |
| **पुनर्भुगतान का प्रभाव** | यह अनुमानित इंस्टालमेंट्स और पुनर्भुगतान अनुसूची की सुविधा प्रदान करता है। | ब्याज दरों में बदलाव से किश्तों या ऋण की अवधि में परिवर्तन हो सकता है। |
| **प्रमुख लाभ** | यह उधारकर्ताओं को बढ़ती ब्याज दरों से बचाता है और वित्तीय नियोजन में सहायता करता है। | इससे उधारकर्ताओं को बेंचमार्क दरों में गिरावट आने पर लाभ उठाने की अनुमति मिलती है। |
| **मुख्य सीमा** | बाज़ार दरों में गिरावट आने पर कर्जदारों को शायद लाभ न मिले। | ब्याज दरों में वृद्धि से किश्तें बढ़ सकती हैं या चुकौती की अवधि बढ़ सकती है। |
| **उपयुक्तता** | उन उधारकर्ताओं के लिए उपयुक्त है जो पुनर्भुगतान की निश्चितता को प्राथमिकता देते हैं। | यह उन उधारकर्ताओं के लिए उपयुक्त है जो संभावित बचत के लिए उतार-चढ़ाव को स्वीकार करने को तैयार हैं। |

EKAM ACADEMY YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

# सामाजिक मुद्दे



## संपादकीय

### यौन कार्य पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विश्लेषण

'सेक्स वर्क पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विश्लेषण' (Analysing the SC's judgment on sex work) शीर्षक वाला यह संपादकीय 3 अगस्त, 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसमें सेक्स वर्क के प्रति सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार-आधारित दृष्टिकोण और इसके कार्यान्वयन में संस्थागत बाधाओं पर प्रकाश डाला गया है।

#### संवैधानिक महत्त्व

- 29 मई, 2026 के फैसले में यह स्वीकार किया गया है कि मानव तस्करी रोधी उपायों ने जबरन रेस्क्यू, अनिश्चितकालीन हिरासत, बच्चों से अलगाव और यौनकर्मियों के जीवन को खतरे में डालने जैसी स्थितियों को संभव बनाया है।
- लगभग 300 पृष्ठों के इस फैसले में यह स्वीकार किया गया है कि स्वायत्तता एवं संवेदनशीलता एक साथ मौजूद हो सकती हैं और प्रवासन को मानव तस्करी के साथ भ्रमित करने की बात को खारिज किया गया है।
- सामाजिक अस्वीकृति के बावजूद यौनकर्मियों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं; सहमति देने वाले वयस्कों का जबरन रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है और हस्तक्षेप की शुरुआत सहमति स्थापित करने से होनी चाहिए।
- अनुच्छेद 142 के तहत जारी निर्देश इस अधिकार-आधारित ढाँचे को कानूनी बल प्रदान करते हैं किंतु न्यायालय यौनकर्मियों एवं राष्ट्रीय यौनकर्मी नेटवर्क जैसे संगठनों के योगदान को नजरअंदाज करता है।

#### संस्थागत मान्यताएँ और त्रुटियाँ

- इस फैसले में यह माना गया है कि स्पष्ट कानूनी मानक पुलिसिंग, न्यायनिर्णय, आश्रय स्थलों और कानूनी सहायता तक पहुँच में संस्थागत पूर्वाग्रह को दूर करने में सहायक होंगे।
- कानूनी तौर पर अधिकार मिलने के बाद भी जातिगत भेदभाव और आर्थिक रूप से हाशिए पर धकेले जाने की वजह से दलित व आदिवासी महिलाओं का सरकारी तंत्र से सामना अलग तरह का होता है।
- एक महिला को गलत तरीके से तस्कर करार दिया गया और उसने सात साल तक पुलिस को रिपोर्ट करने और सुनवाई में भाग लेने में बिताए किंतु उसका बयान दर्ज नहीं किया गया, जिससे गहरी जड़ें जमा चुकी नौकरशाही अन्याय का पर्दाफाश हुआ।
- न्यायालय जाति को यौन कार्य के एक संरचनात्मक चालक के रूप में मान्यता देता है किंतु इस बात की अपर्याप्त रूप से जाँच करता है कि यह संस्थागत कार्यान्वयन को किस प्रकार प्रभावित करता है।
- मानव तस्करी रोधी उद्योग, जिसमें छापेमारी एवं शेल्टर्स में शामिल नागरिक समाज संगठन भी शामिल हैं, वित्तीय प्रोत्साहन, कमजोर जवाबदेही और कैद में रखी गई महिलाओं पर अधिकार के माध्यम से कारागार से बचाव को बढ़ावा दे सकता है।
- अनिश्चितकाल तक शेल्टर में कैद जबरदस्ती नियंत्रण का एक अन्य रूप बन सकता है जिससे बचाव स्वयं सुरक्षा के बजाय हिंसा का स्रोत बन जाता है।

#### कार्यान्वयन प्राथमिकताएँ

- यौनकर्मियों के संघों को दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए, अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए, पुलिस प्रशिक्षण को आकार देना चाहिए और आश्रय स्थलों के मानक स्थापित करने चाहिए।
- गैर सरकारी संगठन क्षेत्र की गहन जाँच की आवश्यकता है जहाँ संगठन सीमित सामुदायिक जवाबदेही, वित्तपोषण निरीक्षण और कानूनी प्रतिरक्षा का आनंद लेते हुए जबरन रेस्क्यू कार्यों में भाग लेते हैं।
- भारत की मौजूदा कल्याणकारी व्यवस्था को अतिरिक्त संस्थानों का निर्माण किए बिना अधिकार प्राप्त नागरिकों के रूप में यौनकर्मियों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए।

### संपादकीय के अतिरिक्त

#### *यौन कार्य के लिए वैश्विक नियामक मॉडल*

- **वैधीकरण मॉडल :** नीदरलैंड नगरपालिका लाइसेंस के तहत सहमति से वयस्क यौन कार्य की अनुमति देता है किंतु जबरन व नाबालिग वेश्यावृत्ति को अपराध मानता है।
- **खरीदार को अपराधी मानने का मॉडल :** स्वीडन ने 1999 में यौन सेवाओं की खरीद को अपराध घोषित किया, लेकिन बिक्री को नहीं; आयरलैंड ने 2017 में इसी तरह का मॉडल अपनाया।
- **अपराधमुक्ति मॉडल :** न्यूजीलैंड के वेश्यावृत्ति सुधार अधिनियम, 2003 ने प्रमाणन, सुरक्षा नियमों और शोषण-रोधी दंडों को बरकरार रखते हुए वयस्क यौन कार्य को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।

- **आंशिक-अपराधीकरण मॉडल :** इंग्लैंड और वेल्स में यौन संबंध बेचना तो अनुमत है किंतु वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना, वेश्यालय चलाना, लाभ के लिए वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करना और शोषणकारी खरीदारी को अपराध माना जाता है।
- **स्थानीय विनियमन :** नेवादा में वेश्यावृत्ति की अनुमति केवल पात्र काउंटियों द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्राप्त वेश्यालयों में ही है जो स्थानीय विनियमन को व्यापक प्रतिबंधों के साथ जोड़ती है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी साक्ष्य :** WHO का अनुमान है कि यौनकर्मियों के बीच एचआईवी संक्रमण को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से दस वर्षों में एचआईवी के नए संक्रमणों में 46% की कमी आ सकती है।
- **भारतीय प्रासंगिकता :** बुधदेव कर्मस्कर (2022) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यौनकर्मियों की गरिमा को बरकरार रखा और सहमति देने वाले वयस्कों की छापेमारी के दौरान पुलिस उत्पीड़न से रक्षा की।

## लिव-इन पार्टनर्स के लिए सुरक्षा उपाय

'एससी सेफगार्ड्स फॉर लिव-इन पार्टनर्स आर ओवरड्यू' (SC safeguards for live-in partners are overdue) शीर्षक वाला यह संपादकीय 6 अगस्त, 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घरेलू क्रूरता के खिलाफ आपराधिक कानून के तहत दी गई सुरक्षा को विवाह जैसे लिव-इन संबंधों तक विस्तारित करने पर प्रकाश डाला गया है।

### कानूनी संरक्षण का विस्तार

- सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और बीएनएस की धारा 85 का विस्तार करते हुए इसे विवाह करने के वास्तविक इरादे पर आधारित लिव-इन रिलेशनशिप पर भी लागू कर दिया है।
- यह फैसला औपचारिकताओं के बजाय सार को महत्त्व देने वाले दृष्टिकोण को अपनाता है, यह मानते हुए कि औपचारिक विवाह के बिना भी घरेलू हिंसा उतनी ही हानिकारक बनी रहती है।
- महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत पहले से ही नागरिक उपचार प्राप्त हैं जबकि यह निर्णय अतिरिक्त रूप से आपराधिक कानून संरक्षण को सक्षम बनाता है।
- अभियुक्त के मौजूदा विवाह के कारण बाद में स्थापित विवाह जैसे संबंध को कानूनी रूप से अमान्य घोषित करके क्रूरता के आरोपों को स्वतः ही समाप्त नहीं किया जा सकता है।

### तर्क और सुरक्षा उपाय

- घरेलू हिंसा असमान शक्ति और जबरदस्ती से उत्पन्न होती है जिसके लिए बदलते सामाजिक संबंधों के अनुरूप कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- NFHS ने पाया कि विवाहित महिलाओं में से 22% से अधिक ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक साथी हिंसा का अनुभव किया है।
- वित्तीय और सामाजिक विवशताएँ गंभीर रूप से कम रिपोर्टिंग का कारण बनती हैं, जबकि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को अतिरिक्त कानूनी, प्रक्रियात्मक एवं सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- डी. वेलुसामी बनाम डी. पचैअम्मल (2010) और इंद्र शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा (2013) ने विवाह जैसे संबंधों के लिए अवधि, स्थायित्व व प्रतिबद्धता को परीक्षण के रूप में पहचाना है।
- अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य वाद में निर्धारित सुरक्षा उपायों को लागू करने से पीड़ित संरक्षण और मनमानी गिरफ्तारी तथा कानूनी दुरुपयोग की रोकथाम के बीच संतुलन बना रहता है।

### संपादकीय के अतिरिक्त

#### *लिव-इन पार्टनर के अनसुलझे अधिकार*

- **खंडित ढाँचा :** घरेलू हिंसा अधिनियम विवाह जैसे संबंधों को मान्यता देता है, जबकि उत्तराखंड में पंजीकरण अनिवार्य है, जिससे राज्यों में अधिकारों में असमानता पैदा होती है।
- **मान्यता अनिश्चितता :** धन्नूलाल बनाम गणेशराम (2015) वाद में लंबे समय तक सहवास के बाद अनुमानित विवाह को स्वीकार किया गया, लेकिन छोटे या निजी संबंधों को साबित करना अभी भी मुश्किल है।
- **मेंटेनेंस पहुँच :** ललिता टोप्पो बनाम झारखंड राज्य (2018) मामले में लिव-इन पार्टनर को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मौद्रिक राहत का दावा करने की अनुमति दी गई थी।
- **संपत्ति की असुरक्षा :** लिव-इन रिलेशनशिप खत्म होने पर संपत्ति के बंटवारे के लिए कोई व्यापक ढाँचा नहीं होता है, इसलिए मालिकाना हक टाइटल, दर्ज किए गए योगदान और साथ रहने के समझौतों पर निर्भर करता है।
- **बच्चों की स्थिति :** तुलसा बनाम दुर्घाटिया (2008) मामले में लंबे समय तक साथ रहने (लिव-इन रिलेशनशिप) से जुड़े मामलों में बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन विरासत के लिए अभी भी विवाह जैसे संबंध को साबित करना आवश्यक हो सकता है।
- **समावेशिता का अंतर :** सुप्रियो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2023) मामले में समलैंगिक युगल को समान उत्तराधिकार, संयुक्त दत्तक ग्रहण और पति-पत्नी के लाभों से संबंधित सुरक्षा से वंचित कर दिया गया।
- **निजता के मुद्दे :** उत्तराखंड में अनिवार्य पंजीकरण से मान्यता और भरण-पोषण के अधिकार तो मिलते हैं लेकिन निजता, स्वायत्तता और पारिवारिक निगरानी को लेकर चिंताएँ भी पैदा होती हैं।

YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

## उपभोक्ता संरक्षण एवं प्रवर्तन

'ड्यू डिलिजेंस' (Due diligence) शीर्षक वाला यह संपादकीय 20 अगस्त, 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ। यह सेलिब्रिटी की जवाबदेही के माध्यम से सरोगेट विज्ञापन (Surrogate Advertising) पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और साक्ष्य-आधारित व आनुपातिक प्रवर्तन सुनिश्चित करता है।

### नियामक कार्रवाई और कानूनी सीमा

- महाराष्ट्र एफडीए (FDA) ने उन सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स को निशाना बनाया है, जिनका उद्देश्य उस मार्केटिंग को रोका जा सके जो निर्माताओं के ब्रांड रिकॉल को तो बनाए रखती है जबकि उपभोक्ता स्वास्थ्य लागतों को दूसरों पर डाल देती है।
- एफडीए का आरोप है कि विमल इलायची की कोई स्वतंत्र बाजार पहचान नहीं है और वह शाहरुख खान, अजय देवगन एवं टाइगर श्रॉफ के विज्ञापन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से तंबाकू को बढ़ावा देती है।
- COTPA नियमों के तहत इस तरह का ब्रांड-संबंधित प्रचार सेरोगेट विज्ञापन का कारण बन सकता है किंतु नियामक संदेह को ठोस सबूतों द्वारा समर्थित होना चाहिए।
- डीजीएचएस (DGHS) बनाम सोम पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड (2024) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरोगेट विज्ञापन को साबित करने का भार राज्य पर डाल दिया।
- न तो किसी पुराने ब्रांड का पंजीकरण स्वत: ही सरोगेट प्रोत्साहन को सिद्ध करता है और न ही कोई तकनीकी रूप से वैध उत्पाद असीमित विज्ञापन अधिकारों की गारंटी देता है।
- इसलिए, COTPA और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत FDA की जाँच को कठोर कानूनी एवं साक्ष्य संबंधी जाँच का सामना करना पड़ता है।

### उपभोक्ता संरक्षण और प्रवर्तन संबंधी चुनौतियाँ

- भारत में मुख कैंसर की बढ़ती संख्या को देखते हुए तंबाकू से जुड़े प्रचारों को गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों वाली अनुचित व्यापार प्रथाओं के रूप में मानना उचित है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 विज्ञापनदाताओं पर दायित्व एवं दंड का प्रावधान करता है जिससे निर्माताओं के इरादों के बारे में अनभिज्ञता जताने की हस्तियों की क्षमता कमजोर हो जाती है।
- विज्ञापनदाताओं से उनकी उचित सावधानी के बारे में स्पष्टीकरण की अपेक्षा करना तार्किक रूप से संपूर्ण प्रचार शृंखला में प्रवर्तन जिम्मेदारी का विस्तार करता है।
- इसी तरह की चिंताएँ 'प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली दवाओं' से जुड़े निराधार दावों और भ्रामक शैक्षिक या वित्तीय उत्पादों को लेकर भी हैं।
- भारत में कई अधिनियमों एवं नियमों के तहत खंडित विनियमन के कारण प्राय: प्रशासनिक कार्रवाई व न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
- उचित दंड से अप्रत्यक्ष विज्ञापन को सीमित किया जा सकता है किंतु मनमानी प्रवर्तन से नियामक अतिचार का खतरा होता है और इससे लक्षित प्रथाओं को मज़बूती मिल सकती है।

### संपादकीय के अतिरिक्त

***सरोगेट विज्ञापन को सक्षम बनाने वाला डिजिटल इकोसिस्टम***

- **इन्फ्लुएंसर माइग्रेशन :** मार्च 2024 में जारी एक सरकारी सलाह में मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली व्यक्तियों को ब्रांडेड डिजिटल सामग्री के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी।
- **एल्गोरिथम प्रवर्धन :** डब्ल्यूएचओ (WHO) के 2024 के आकलन में पाया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अस्वास्थ्यकर उत्पादों के विज्ञापन को लक्षित करने के लिए ऑनलाइन गतिविधि एवं व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करते हैं जिससे उपभोक्ताओं के बार-बार संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है।
- **ब्रांड विस्तार में अस्पष्टता :** वर्ष 2022 के CCPA दिशा-निर्देश साझा लोगो, रंगों या लेआउट को संभावित वैकल्पिक प्रचार के रूप में मानते हैं जबकि यह स्पष्ट करते हैं कि केवल एक समान ब्रांड नाम ही पर्याप्त नहीं है।
- **प्रकटीकरण की सीमाएँ :** ASCI के 2021 के इन्फ्लुएंसर दिशा-निर्देशों में प्रमुख विज्ञापन लेबल की आवश्यकता होती है किंतु इस तरह के खुलासे यह नहीं बताते हैं कि प्रचारित उत्पाद किसी प्रतिबंधित ब्रांड को छुपाता है या नहीं।
- **प्लेटफॉर्म की जवाबदेही :** वर्ष 2024 की सरकारी सलाह में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 का हवाला देते हुए मध्यस्थों को चेतावनी दी गई कि वे अधिसूचित गैरकानूनी सट्टेबाजी प्रचारों को तुरंत हटा दें।
- **सीमा पार कर चोरी :** भारतीय उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाले ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के कारण 2022 और 2024 के बीच सरकार द्वारा बार-बार सलाह जारी की गई, जिससे घरेलू विनियमन की अधिकार क्षेत्रीय सीमाएँ उजागर हुईं।
- **मीडिया साक्षरता :** 2026 के डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय कार्य योजना ढाँचे ने युवाओं के बीच तंबाकू के अप्रत्यक्ष प्रचार का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया जागरूकता अभियान और स्कूल स्तर पर डिजिटल साक्षरता की सिफारिश की थी।

## मुख्य परीक्षा

### सोशल मीडिया पर प्रतिबंध

#### संदर्भ

फ्राँस 15 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है किंतु इसके संवैधानिक परिषद ने इसे रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश था, जिसके बाद इंडोनेशिया ने भी ऐसा ही किया।

#### बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुँच पर वैश्विक प्रतिबंध

- **ऑस्ट्रेलिया :** विश्व का पहला राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध दिसंबर 2025 में लागू हुआ और जिसमें 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कोई अपवाद नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्मों पर 54.6 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **इंडोनेशिया :** मार्च 2026 से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स एवं रोब्लॉक्स (Roblox) सहित उच्च जोखिम वाले प्लेटफार्मों पर अकाउंट नहीं रख सकते हैं।
- **फ्राँस :** संसद ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध को मंजूरी दे दी थी, लेकिन संवैधानिक परिषद ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं निजता संबंधी चिंताओं के कारण अगस्त 2026 में इसे रद्द कर दिया।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका :** यूटाह एवं अर्कांसस जैसे राज्यों ने माता-पिता की सहमति और आयु सत्यापन संबंधी कानून बनाए किंतु अदालती चुनौतियों ने उनके प्रवर्तन को सीमित कर दिया है।
- **चीन :** पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय चीन युवाओं पर केंद्रित नियंत्रणों को अपनाता है जो स्क्रीन टाइम को सीमित करते हैं और अनुपयुक्त सामग्री को प्रतिबंधित करते हैं।
- **यूनाइटेड किंगडम :** ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम, 2023 में आयु संबंधी आश्वासन और हानिकारक सामग्री से सुरक्षा की आवश्यकता है लेकिन यह सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता है।
- **भारत :** कर्नाटक ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध की घोषणा की, जबकि आंध्र प्रदेश ने 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंध प्रस्तावित किए; ये राज्य स्तरीय पहल हैं।

| आयु-आधारित सोशल मीडिया प्रतिबंध के पक्ष में तर्क | आयु-आधारित सोशल मीडिया प्रतिबंध के विरुद्ध तर्क |
|---|---|
| **विकासशील मस्तिष्कों का संरक्षण :** बच्चों में आवेग पर नियंत्रण सीमित होता है जिससे वे व्यसनकारी प्रवृत्तियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। टिकटॉक की अंतहीन फीड और यूट्यूब के ऑटोप्ले उनकी नींद, पढ़ाई व दैनिक दिनचर्या बाधित हो सकती है। | **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :** सोशल मीडिया बच्चों को जानकारी प्राप्त करने और अपने विचार साझा करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, फ्राँस की संवैधानिक परिषद ने अभिव्यक्ति एवं निजता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए 2026 में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध को रोक दिया था। |
| **मानसिक स्वास्थ्य :** इसके अत्यधिक उपयोग से चिंता, अवसाद, आत्मसम्मान में कमी, सामाजिक तुलना और नींद संबंधी विकार जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में डिजिटल व्यसन को प्रमुखता से दर्शाया गया है जबकि निमहंस (NIMHANS) शट (SHUT) क्लिनिक का संचालन करता है। | **सामाजिक संबंध :** ऑनलाइन समुदाय अलग-थलग पड़े, LGBTQ+ और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को सहायता प्रदान करते हैं। LGBTQ+ युवाओं के लिए एक मॉडरेटेड प्लेटफॉर्म 'ट्रेवरस्पेस' के वैश्विक स्तर पर 700,000 से अधिक सदस्य हैं। |
| **ऑनलाइन सुरक्षा :** ये प्रतिबंध साइबरबुलिंग, अनुचित संपर्क, हानिकारक सामग्री और निरंतर उत्पीड़न को कम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लगाया गया प्रतिबंध बच्चों को इस तरह के अकाउंट-आधारित जोखिमों से बचाने के उद्देश्य से है। | **प्रवर्तन संबंधी चुनौतियाँ :** बच्चे गलत जानकारी, दूसरों के अकाउंट या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नियामक अपने प्रवर्तन दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से फर्जी आईडी, डीपफेक एवं VPN-आधारित धोखाधड़ी को संबोधित करता है। |
| **गलत सूचना पर नियंत्रण :** एल्गोरिद्म स्वास्थ्य, राजनीतिक एवं जन-सुरक्षा से जुड़े सनसनीखेज दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर सकते हैं। कोविड-19 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑनलाइन व्यापक रूप से फैले गलत उपचार, टीकाकरण विरोधी संदेशों और भ्रामक उपचारों का दस्तावेजीकरण किया। | **शैक्षिक पहुँच :** सोशल मीडिया विशेषज्ञों के व्याख्यान और शिक्षण समुदाय प्रदान करता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित NPTEL के यूट्यूब पाठ्यक्रम इस शैक्षिक महत्त्व को दर्शाते हैं। |

- **ध्रुवीकरण में कमी :** एक जैसी विचारधारा वाले समूह चरमपंथी विचारों को बढ़ावा दे सकते हैं और ऑफलाइन शत्रुता का कारण बन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक जाँच में फेसबुक पर म्यांमार के सैन्य नेटवर्क से जुड़े 10,000 से अधिक रोहिंग्या-विरोधी नफरत भरे पोस्ट की पहचान की गई।
- **डेटा सुरक्षा :** बच्चे सहमति, प्रोफाइलिंग या स्थायी डिजिटल फुटप्रिंट्स को नहीं समझ पाते हैं। वर्ष 2022 में आयरलैंड ने इंस्टाग्राम द्वारा बच्चों के व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण के लिए मेटा पर 405 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया।
- **नागरिक भागीदारी :** ये प्लेटफॉर्म युवाओं को जलवायु परिवर्तन और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अभियान चलाने में मदद करते हैं। ग्रेटा थनबर्ग द्वारा अपनी स्कूल स्ट्राइक को ऑनलाइन साझा करने के बाद फ्राइडेज फॉर फ्यूचर का वैश्विक स्तर पर विस्तार हुआ।
- **माता-पिता की स्वायत्तता :** पूर्ण प्रतिबंध लगाने से परिवार का विवेक नजरअंदाज हो सकता है। गूगल फैमिली लिंक जैसे टूल माता-पिता को स्क्रीन-टाइम सीमा निर्धारित करने, सामग्री को फिल्टर करने और एप्लिकेशन की निगरानी करने की अनुमति देते हैं।

## सोशल मीडिया के युवा उपयोगकर्ताओं के लिए भारत का नियामक ढाँचा

- **डीपीडीपी अधिनियम, 2023 :** 18 वर्ष से कम आयु के लोग बच्चे कहलाते हैं। प्लेटफॉर्मों को माता-पिता की सत्यापित सहमति की आवश्यकता होती है और वे बच्चों को लक्षित करके विज्ञापन नहीं दिखा सकते हैं, न ही उन पर निगरानी रख सकते हैं। उल्लंघन करने पर ₹200 करोड़ का जुर्माना लग सकता है।
- **आईटी नियम, 2021 :** ऑनलाइन सामग्री को U, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+ एवं A के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें प्रतिबंधित सामग्री के लिए माता-पिता की सुरक्षा व आयु सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है।
- **प्लेटफॉर्म संबंधी कर्त्तव्य :** वैध आधिकारिक आदेश मिलने के तीन घंटे के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाना अनिवार्य है और शिकायत मिलने के दो घंटे के भीतर विशेष रूप से आपत्तिजनक या रूपांतरित सामग्री को हटाना होगा। 2026 के संशोधनों के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित सामग्री के लिए लेबल लगाना आवश्यक है।
- **बाल संरक्षण कानून :** पोक्सो अधिनियम, आईटी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, ग्रूमिंग, बाल यौन शोषण सामग्री, तस्करी, अनिवार्य रिपोर्टिंग व पुनर्वास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हैं।

## बच्चों के लिए सुरक्षित सोशल मीडिया की ओर

- **बच्चों की सुरक्षा के लिए डिजाइन :** प्राइवेट अकाउंट, आयु-उपयुक्त सामग्री, प्रतिबंधित एल्गोरिदम, लोकेशन साझाकरण पर प्रतिबंध, अजनबियों द्वारा भेजे गए संदेशों पर रोक और लक्षित विज्ञापन निषेध अनिवार्य हैं। ब्रिटेन का आयु-उपयुक्त डिजाइन कोड एक मॉडल प्रस्तुत करता है।
- **स्तरित पहुँच :** 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सख्त नियम लागू करना, 13-15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पर्यवेक्षित पहुँच और 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का COPPA पहले से ही 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अधिक मज़बूत सुरक्षा प्रदान करता है।
- **प्लेटफॉर्म की जवाबदेही :** कानूनी कर्त्तव्यों, जोखिम आकलन, स्वतंत्र लेखापरीक्षणें और आनुपातिक दंडों को अनिवार्य करना चाहिए। यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत बहुत बड़े प्लेटफार्मों की वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य है।
- **डिजिटल साक्षरता :** स्कूलों को एल्गोरिदम के बारे में जागरूकता, गलत सूचना का पता लगाना, गोपनीयता, स्क्रीन-टाइम प्रबंधन और साइबरबुलिंग से निपटने के तरीके सिखाने चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में डिजिटल वेलनेस पाठ्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया है।
- **माता-पिता का सहयोग :** माता-पिता को स्क्रीन टाइम के नियम बनाने और खुलकर संवाद बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। Google Family Link जैसे टूल एप्लिकेशन नियंत्रण, सामग्री फिल्टर और निगरानी पहुँच की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय समन्वय :** संयुक्त राष्ट्र और बीस देशों के समूह को सुरक्षा, गोपनीयता एवं आयु सत्यापन मानकों को एकरूप करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की सामान्य टिप्पणी संख्या 25 एक साझा बाल अधिकार ढाँचा प्रदान करती है।

## युवा वैश्विक रोजगार प्रवृत्ति, 2026 रिपोर्ट

### संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 'ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2026 : बैक टू द फ्यूचर' नामक रिपोर्ट जारी की है जिसमें विश्व स्तर पर बढ़ती युवा बेरोजगारी एवं निष्क्रियता के बारे में चेतावनी दी गई है।

### मुख्य निष्कर्ष

- **युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी :** वैश्विक स्तर पर युवा बेरोजगारी दर 2025 में बढ़कर 12.4% हो गई, जिससे 15-24 वर्ष की आयु के लगभग 67 मिलियन लोग बेरोजगार रह गए।

EKA ACADEMY YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

- **NEET आबादी में वृद्धि :** रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में संलग्न रहित (NEET) युवाओं की संख्या 2023 में 19.7% से बढ़कर 2025 में 20% हो गई है जो वैश्विक स्तर पर 257 मिलियन तक पहुँच गई।
- **निरंतर लैंगिक असमानता :** NEET महिलाओं की दर 27.4% तक पहुँच गई है जो पुरुषों की दर 13.1% से दोगुनी से भी अधिक है; सभी NEET युवाओं में दो-तिहाई से अधिक महिलाएँ थीं।
- **अनौपचारिक कार्य का प्रभुत्व :** निम्न एवं निम्न-मध्यम आय वाले देशों में लगभग दस में से नौ युवा कर्मचारी अनौपचारिक रूप से काम करते रहे और उन्हें प्रायः सामाजिक सुरक्षा, आय स्थिरता या श्रम संरक्षण नहीं प्राप्त है।

## रोजगार संकट के पीछे के कारक

- **मध्यम कौशल वाले रोजगारों में गिरावट :** लिपिकीय कार्य, प्रशासन, बिक्री एवं विनिर्माण क्षेत्रों में प्रवेश स्तर की भूमिकाएँ कम हो रही हैं जिससे शिक्षा से रोजगार की ओर संक्रमण कमजोर हो रहा है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव :** 15-29 आयु वर्ग के युवाओं द्वारा धारित लगभग 6.1% नौकरियों में कार्य प्रतिस्थापन या परिवर्तन का जोखिम उच्च होता है।
- **लैंगिक बाधाएँ :** अवैतनिक देखभाल कार्य, भेदभाव एवं गुणवत्तापूर्ण रोजगार तक सीमित पहुँच युवा महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी को प्रतिबंधित करती रहती है।
- **कमजोर आर्थिक विकास :** धीमी वृद्धि एवं सीमित रोजगार सृजन से नए प्रवेशकों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-2025 के दौरान ग्यारह वैश्विक उपक्षेत्रों में से आठ में युवा बेरोजगारी बढ़ी या अपरिवर्तित रही है।
- **कौशल का बेमेल होना :** शिक्षा एवं रोजगार के बीच कमजोर तालमेल बेरोजगारी या अत्यधिक योग्यता की कमी का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में रिक्त पदों के लिए अक्सर व्यावहारिक कौशल की आवश्यकता होती है जो सामान्य अकादमिक पाठ्यक्रमों में नहीं प्राप्त होते हैं।

## युवा रोजगार में संरचनात्मक बाधाएँ

- **अनौपचारिकता का जाल :** निम्न एवं निम्न-मध्यम आय वाले देशों में लगभग दस में से नौ युवा श्रमिकों के पास औपचारिक अनुबंध और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, जिससे श्रम कानून प्रवर्तन व लाभ वितरण जटिल हो जाता है।
- **मुद्रास्फीति का अनुभव करना :** डिजिटल भर्ती से आवेदकों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे नियोक्ता प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए भी पूर्व अनुभव और उन्नत कौशल की मांग कर सकते हैं, जिससे पहली बार नौकरी चाहने वालों के लिए अनुभव संबंधी एक विरोधाभास सृजित होता है।
- **डिजिटल विभाजन :** खराब कनेक्टिविटी, महँगे डिजिटल उपकरण और अपर्याप्त प्रशिक्षण उभरते रोजगारों तक पहुँच को सीमित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दक्षिण अफ्रीका में डिजिटल कौशल में लगातार मौजूद असमानताओं की पहचान की है।
- **लिंग आधारित अपवर्जन :** अवैतनिक देखभाल कार्य, अपर्याप्त बाल देखभाल एवं भेदभाव, विशेषकर दक्षिण एशिया, उत्तरी अफ्रीका व अरब देशों में महिलाओं के रोजगार को सीमित करते हैं। युवा महिलाओं की वैश्विक स्तर पर NEET दर 2025 में 27.4% तक पहुँच गई।
- **जनसांख्यिकीय दबाव :** विकासशील क्षेत्रों में युवा आबादी की तीव्र वृद्धि औपचारिक रोजगार सृजन की तुलना में कहीं अधिक है। प्रतिवर्ष लगभग 10-12 मिलियन अफ्रीकी युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं जबकि औपचारिक रोजगारों की संख्या केवल लगभग तीन मिलियन है।
- **असमान राष्ट्रीय क्षमता :** निम्न आय वाले देशों में औपचारिक रोजगार सृजित करने और तकनीकी बदलावों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षमता का अभाव है। ये स्वास्थ्य सेवा सहित सामाजिक सुरक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल लगभग 2% ही खर्च करते हैं।

## युवा रोजगार के लिए नीतिगत प्राथमिकताएँ

- **रोजगार सृजन :** लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए रोजगार नीतियाँ अपनाना और हरित उद्योगों एवं उद्यमिता में युवा महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार करना। भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, 2030 तक छः लाख से अधिक रोजगार सृजित कर सकता है।
- **कौशल विकास :** तकनीकी, सामाजिक एवं अनुकूलन कौशल को एकीकृत करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षुता, तकनीकी शिक्षा व आजीवन सीखने का विस्तार करना। जर्मनी की दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली व्यावसायिक शिक्षा को कार्यस्थल के अनुभव के साथ एकीकृत करती है।
- **रोजगार संक्रमण :** करियर मार्गदर्शन, भर्ती प्रोत्साहन एवं वेतन सब्सिडी के माध्यम से सार्वजनिक रोजगार सेवाओं (PES) का आधुनिकीकरण करना। यूरोपीय संघ की युवा गारंटी योजना योग्य

युवाओं को चार महीने के भीतर रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करती है।

- **सामाजिक सुरक्षा :** गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अनौपचारिक श्रमिकों एवं पहली बार काम करने वाले श्रमिकों को पोर्टेबल लाभ और श्रम अधिकार प्रदान करना। भारत का ई-श्रम वन-स्टॉप सॉल्यूशन पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत करता है।
- **मानव-केंद्रित एआई :** एआई-आधारित भर्ती में पूर्वाग्रह परीक्षण, पारदर्शिता एवं मानवीय समीक्षा अनिवार्य है। साथ ही, अनुचित विस्थापन के खिलाफ पुनर्कौशल प्रशिक्षण भी आवश्यक है। यूरोपीय संघ एआई अधिनियम रोजगार संबंधी एआई प्रणालियों को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखता है।

## प्रारंभिक परीक्षा

### विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति, 2026

#### संदर्भ

विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति (SOFI), 2026 रिपोर्ट से पता चलता है कि भूख से पीड़ित आबादी के मामले में अफ्रीका ने पहली बार एशिया को पीछे छोड़ दिया है। यह रिपोर्ट FAO, IFAD, UNICEF, WFP और WHO द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है और SDG लक्ष्य 2.1 और 2.2 का अनुसरण करती है।

#### मुख्य निष्कर्ष

- वैश्विक भूखमरी में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट दर्ज की गई है जो 2022 में 8.6% से घटकर 2025 में 7.8% हो गई है।
- स्थिति में सुधार के बावजूद 64.5 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार बने रहे, जो महामारी से पहले के स्तर से अधिक है।
- अफ्रीका में 309 मिलियन (20%) लोग भूखे थे, जो एशिया के 292 मिलियन (6%) से अधिक है।
- 2030 तक अफ्रीका में विश्व की कुपोषित आबादी का 56% हिस्सा हो सकता है।
- जलवायु परिवर्तन, गरीबी, सूडान व डीआर कांगो में संघर्ष, खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतें और भू-राजनीतिक तनाव भूख की समस्या को अधिक बदतर बना देते हैं।
- ऊर्जा, उर्वरक और पौष्टिक भोजन की बढ़ती लागत पूरे अफ्रीका में खाद्य उत्पादन एवं उसकी उपलब्धता को अधिक सीमित कर देती है।
- लगभग 2.1 अरब लोग (25.8%) मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे, जो अभी भी कोविड-पूर्व के स्तर से ऊपर है।
- स्वस्थ आहार की लागत (CoHD), 2025 में प्रतिदिन 4.28 क्रय-शक्ति-समता डॉलर तक बढ़ गई।
- लगभग 2.69 अरब लोग (32.7%) स्वस्थ आहार वहन नहीं कर सकते; अफ्रीका में यह अक्षमता 66.6% दर्ज की गई।
- मार्च 2025 में एमडीडी-सी (MDD-C) और एमडीडी-डब्ल्यू (MDD-W) एसडीजी 2.2 के आहार-गुणवत्ता आयाम के लिए आधिकारिक संकेतक बन गए।
- 6 से 23 महीने की आयु के केवल 30.8% बच्चे ही आहार विविधता प्राप्त कर सके, जबकि एक दशक पहले यह आँकड़ा 29.4% था।
- 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की केवल 62.7% महिलाओं ने ही आहार में विविधता हासिल की है जिससे लगभग एक-तिहाई महिलाएँ अपर्याप्त पोषण से ग्रस्त रह गई।
- स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया, जन्म के समय निम्न वजन एवं मोटापे पर हुई प्रगति 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त बनी हुई है।
- निम्न कृषि उत्पादकता, कमजोर मूल्य श्रृंखलाएँ, महँगे इनपुट, खराब रसद व्यवस्था और मुख्य खाद्य पदार्थों पर केंद्रित नीतियां पौष्टिक भोजन की लागत को बढ़ाती हैं।

#### भारत की स्थिति

- भारत ने दक्षिण एशिया में कुपोषण के स्तर को 2021 में 13.9% से घटाकर 2025 में 9.3% करने में मदद की।
- भारत को बाहर रखने से निम्न-मध्यम आय वाले देशों में घटती सामर्थ्य की प्रवृत्ति वृद्धि में परिवर्तित हो जाएगी।
- भारत दक्षिण एशिया में बच्चों में स्टंटिंग एवं मोटापे की समस्या से निपटने में हुई प्रगति का समर्थन करता है। हालाँकि, मातृ एनीमिया अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है।
- दक्षिण एशियाई बाजारों में फलों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों से स्वस्थ आहार की लागत में असमान रूप से वृद्धि होती है।

### नूतन सकला

#### संदर्भ

ओडिशा सरकार ने महिलाओं एवं लड़कियों की तस्करी के खिलाफ एक व्यापक राज्य नीति के रूप में नूतन सकला (नई सुबह) का प्रस्ताव रखा।

#### नूतन सकला के बारे में

- यह मानव तस्करी रोधी समन्वित प्रतिक्रिया के लिए चार स्तंभों का अनुसरण करता है जिसमें रोकथाम, संरक्षण, अभियोजन और साझेदारी शामिल हैं।

EK ACADEMY YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

- रोकथाम के प्रयासों के तहत जीवन कौशल शिक्षा एवं प्रवासन रजिस्टरों के माध्यम से कमजोर समुदायों, स्कूलों, पंचायतों व डिजिटल माध्यमों को लक्षित किया जाएगा।
- एकीकृत पीड़ित सहायता केंद्र एक ही विंडो के माध्यम से चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता, परामर्श और रेफरल प्रदान करेगा।
- समर्पित, गैर-व्यपगत नूतन सकल कोष मानव तस्करी रोधी उपायों एवं पीड़ितों के पुनर्वास के लिए वित्तपोषण करेगा।

## देखभाल की पुनर्कल्पना : विकसित भारत@2047 में केयरगिवर्स को सशक्त बनाना

### संदर्भ

नीति आयोग की रिपोर्ट गुणवत्तापूर्ण देखभाल, कार्यबल कल्याण और संस्थागत समर्थन पर केंद्रित एक पेशेवर, गरिमापूर्ण एवं सुलभ देखभाल प्रणाली का प्रस्ताव करती है।

### भारत में देखभाल अर्थव्यवस्था

- देखभाल अर्थव्यवस्था में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सशुल्क व अवैतनिक गतिविधियाँ शामिल हैं।
- इसमें जीवन चक्र के दौरान बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य सेवा, बुजुर्गों की देखभाल, दिव्यांगता सहायता, शिक्षा व घरेलू देखभाल शामिल है।
- औपचारिक देखभालकर्ता एक प्रशिक्षित पेशेवर होता है जबकि अनौपचारिक एवं अवैतनिक पारिवारिक देखभालकर्ता इससे भिन्न होते हैं।
- वेतनभोगी कर्मचारियों में स्वास्थ्य सेवा पेशेवर, शिक्षक, बाल देखभाल कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, घरेलू कामगार एवं व्यक्तिगत देखभाल सहायक शामिल हैं।
- अवैतनिक कार्यों में खाना बनाना, सफाई करना, पानी या ईंधन लाना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और विकलांगों की सहायता करना शामिल है।
- वैश्विक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र 381 मिलियन नौकरियाँ प्रदान करता है जो कुल रोजगार का 11.5% है।
- अवैतनिक देखभाल कार्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में सालाना लगभग 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है।
- भारत के समय उपयोग सर्वेक्षण, 2024 से पता चलता है कि महिलाएँ असमान रूप से अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल संबंधी कार्य करती हैं।
- भारत की बुजुर्ग आबादी लगभग 104 मिलियन है जबकि 2050 तक इसका हिस्सा 19.5% तक पहुँच सकता है।
- भारत में 75% से अधिक बुजुर्ग लोग दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त हैं जिससे दीर्घकालिक पेशेवर देखभाल की मांग बढ़ रही है।
- देखभाल संबंधी कार्यों को औपचारिक रूप देने से महिला श्रमबल भागीदारी, रोजगार सृजन और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा में सुधार हो सकता है।
- भारत नर्सिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिली सफलता की तरह ही प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन सकता है।

### मुख्य सिफारिशें

- स्वास्थ्य, दिव्यांगता, सामाजिक न्याय एवं कौशल विकास कार्यक्रमों में बिखराव को एकीकृत करते हुए एक राष्ट्रीय देखभाल नीति तैयार करना।
- विनियमन, मानक, मान्यता, कार्यबल नियोजन और शिकायत निवारण के लिए एक राष्ट्रीय देखभालकर्ता परिषद की स्थापना करना।
- प्रमाणित देखभालकर्ताओं को परिवारों से जोड़ने वाला एक सत्यापित राष्ट्रीय देखभालकर्ता रजिस्ट्री एवं डिजिटल पोर्टल बनाना।
- प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देते समय पाठ्यक्रम, दक्षताओं, प्रमाणन एवं सतत व्यावसायिक विकास को मानकीकृत करना।
- उपशामक एवं दीर्घकालिक देखभाल के लिए विशेष कैडर विकसित करना और पाठ्यक्रम-आधारित व डिजिटल प्रशिक्षण का विस्तार करना।
- देखभाल करने वालों को श्रम सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा व व्यावसायिक दुर्घटना एवं रोग बीमा का विस्तार प्रदान करना।
- दुर्व्यवहार को रोकने के लिए बहुभाषी प्रशिक्षण, सहायक प्रौद्योगिकियों, अनिवार्य रिपोर्टिंग, ब्लैकलिस्टिंग और शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करना।
- प्रशिक्षण, नैतिक भर्ती, योग्यता मान्यता, सुरक्षित प्रवासन एवं श्रमिक पुनर्एकीकरण को कवर करने वाले द्विपक्षीय समझौतों का विकास करना।

## भारत में साइबर अपराध पर संसदीय समिति की रिपोर्ट

### संदर्भ

गृह मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने भारत की साइबर अपराध प्रतिक्रिया को मज़बूत करने के लिए संस्थागत, तकनीकी एवं विधायी सुधारों की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

IAS ACADEMY YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

## मुख्य अवलोकन एवं सिफारिशें

| मुख्य मुद्दा | समिति की सिफारिशें |
|---|---|
| **शिकायत निवारण में अंतराल:** इन प्लेटफॉर्मों में मानक प्रारूपों, शिकायत ट्रैकिंग, सार्वजनिक आँकड़ों और डेटा-सुरक्षा एकीकरण का अभाव है। | एक सुलभ, बहुभाषी और डेटा सुरक्षा के अनुरूप प्रणाली बनाना जिसमें अद्वितीय ट्रैकिंग नंबर, स्वचालित एस्केलेशन और गुमनाम सांख्यिकी शामिल हों। |
| **ओटीटी सामग्री :** स्व-नियमन नाबालिगों को उनकी उम्र के लिए अनुपयुक्त सामग्री से अपर्याप्त रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। | एक स्वतंत्र पोस्ट-रिलीज समीक्षा पैनल, प्रौद्योगिकी-आधारित आयु सत्यापन, माता-पिता के नियंत्रण और वर्गीकरण उल्लंघनों के लिए दंड की स्थापना करना। |
| **भ्रामक ऑफशोर विज्ञापन :** धोखाधड़ी करने वाले विज्ञापनदाता विश्वसनीय पहचान सत्यापन से बच निकलते हैं। | डिजिटल दस्तावेज सत्यापन, लाइव-वीडियो पहचान और जीरो-ट्रस्ट सिद्धांतों पर आधारित निरंतर निगरानी अनिवार्य है। |
| **म्यूल अकाउंट्स :** डेटा में बिखराव से परिष्कृत रूप से किए गए भुगतान-धोखाधड़ी नेटवर्क का पता लगाने में समस्या आती है। | केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री को एक अंतरसंचालनीय, वास्तविक समय के खतरे के विश्लेषण मंच के रूप में कार्यान्वित करना। |
| **सीबीआई का अधिकार क्षेत्र:** राज्य की सहमति वापस लेने से अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय जाँच में देरी होती है। | केंद्र-राज्य सहयोग को बढ़ावा देना और राज्य की सहमति के बिना बड़े साइबर अपराधों की जाँच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन करना। |
| **शिकायत से एफआईआर दर्ज होने में देरी :** मैनुअल पंजीकरण से धन की त्वरित वसूली और पीड़ितों को धन वापसी में बाधा आती है। | भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को स्वचालित रूप से इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में परिवर्तित करना चाहिए। |
| **कमजोर साइबर शिक्षा :** स्कूलों में साइबर स्वच्छता व ऑनलाइन सुरक्षा संबंधी निर्देशों का निरंतर अभाव है। | सभी बोर्डों में एक क्रमबद्ध, अनिवार्य साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम लागू करना, जिसे शिक्षक प्रशिक्षण एवं बहुभाषी सामग्री द्वारा समर्थित किया जाए। |
| **अप्रचलित साइबर कानून :** तेजी से हो रहे तकनीकी बदलाव मौजूदा नियामक ढाँचों से कहीं आगे निकल जाते हैं। | साइबर कानूनों की आवधिक समीक्षा व अद्यतन के लिए एक स्थायी, बहुविषयक तंत्र स्थापित करना। |
| **खंडित कानून :** विभिन्न कानूनों में साइबर अपराध से संबंधित प्रावधान जाँच व न्यायनिर्णय को जटिल बनाते हैं। | एकीकृत, प्रौद्योगिकी-तटस्थ साइबर अपराध कानून लागू करना और राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के साथ एक एकीकृत साइबर अपराध कार्य बल की स्थापना करना। |

IAS ACADEMY
YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

❑❑❑

# कला एवं संस्कृति



## प्रारंभिक परीक्षा

### धिमसा नृत्य

#### संदर्भ

भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 13,000 से अधिक आदिवासी महिलाओं और छात्राओं द्वारा किए गए धिमसा नृत्य प्रदर्शन को सबसे बड़े धिमसा नृत्य के लिए गिनीज रिकॉर्ड प्राप्त हुआ।



#### धिमसा नृत्य के बारे में

- धिमसा आंध्र प्रदेश की बागता, वाल्मिकी, पोराजा, खोंड (Khond), गदाबा, कोंडाडोरा, मुकाडोरा एवं कोटिया जनजातियों द्वारा किया जाता है।
- इसकी उत्पत्ति कोरापुट क्षेत्र से मानी जाती है जो घोंड (Ghond) जनजाति का आवास है और इसके 12 प्रकार हैं।
- यह उत्सवों, शादियों और अप्रैल में होने वाले शिकार उत्सव के दौरान किया जाता है जब समुदाय कई घंटों तक नृत्य करते हैं।
- समूहों में आम तौर पर 15-20 महिलाएँ होती हैं जो रंगीन पारंपरिक साड़ियां और आभूषण पहने होती हैं।
- नर्तक एक साथ गोलाकार रूप में घूमते हैं जबकि समुदाय के पुरुष सदस्य पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं।
- इसमें हाथों एवं पैरों की गतिविधियों पर अधिक जोर दिया जाता है जबकि चेहरे के हाव-भाव या साहित्यिक ग्रंथों पर कम ध्यान दिया जाता है।
- मोरी, थुडम एवं डप्पू की संगत में संगीत के साथ-साथ चाल में भी बदलाव आता है।
- इसके विषय जनजातीय पौराणिक कथाओं, लोककथाओं, रीति-रिवाजों, आजीविका, नातेदारी एवं वैवाहिक जीवन पर आधारित हैं।

### नीरागुंडा वीरगल्लू शिलालेख

#### संदर्भ

कर्नाटक के नीरागुंडा में एक 12वीं सदी का वीरगल्लू (एक प्रकार का पत्थर) मिला है जिस पर प्राचीन कन्नड़ भाषा में एक शिलालेख है जो संभवतः होयसल शासक विष्णुवर्धन की मृत्यु के बारे में स्पष्टीकरण दे सकता है।



#### नीरागुंडा वीरगल्लू के बारे में

- यह नीरागुंडा में होयसल काल के लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान पाया गया।
- माराव्वे (Maravve) ने इसे अपने पति बोप्पा (Boppa) के लिए बनवाया था, जो होयसल सैनिक थे और विष्णुवर्धन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी।
- इस शिलालेख में वर्तमान हावेरी जिले के बांकापुरा में विष्णुवर्धन की मृत्यु का वर्णन है।

YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

- इसकी तिथि पुष्य मास की एकादशी, दुर्मति संवत्सर, वर्ष 1064 है जो 11 दिसंबर, 1141 ई. से मेल खाती है।
- यदि यह प्रमाणित हो जाता है तो यह विष्णुवर्धन की मृत्यु के 1149 या 1152 ईस्वी में होने वाले पहले के अनुमानों को प्रतिस्थापित कर सकता है।
- वीरगल्लू या 'हीरो स्टोन्स' उन व्यक्तियों की स्मृति में बनाए जाते हैं जो अपने राजा, गाँव या मवेशियों की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं।
- उनके तीन पैनलों में प्रायः युद्ध, स्वर्गारोहण एवं देवता पूजा को दर्शाया गया है जो मोक्ष का प्रतीक है।
- ये होयसल गरुड़ परंपरा को दर्शाते हैं जिसमें शाही अंगरक्षकों द्वारा अत्यधिक निष्ठा और आत्म-बलिदान शामिल होता है।

### होयसल के बारे में

- विष्णुवर्धन, जिनका मूल नाम बिट्टी देव था, होयसल वंश के महानतम शासकों में से एक थे।
- सन् 1116 ईस्वी में तलक्कड़ में चोलों पर उनकी विजय ने होयसल शक्ति को मजबूत किया।
- उन्होंने इस विजय की स्मृति में 1117 ईस्वी में बेलूर के चेन्नाकेशव मंदिर का अभिषेक किया।
- इस मंदिर को मूल रूप से विजया नारायण मंदिर कहा जाता था और यह होयसल वास्तुकला की उत्कृष्टता का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर विष्णुवर्धन ने जैन धर्म एवं शैव धर्म का संरक्षण करते हुए श्रीवैष्णव धर्म को अपनाया।
- होयसल वंश ने 11वीं से 14वीं सदी के बीच कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया।
- उनकी राजधानियाँ बेलूर और बाद में हलेबिड थीं, जिसे द्वारसमुद्र भी कहा जाता था।
- होयसल मंदिरों में ताराकृति योजनाएँ, उभरी हुई जगतियाँ, स्तरित फ्रिज और वेसर शैली में जटिल सोपस्टोन नक्काशी देखने को मिलती है।
- बेलूर, हलेबिड एवं सोमनाथपुरा के पवित्र स्थल 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गए।

## वाग्देवी की मूर्ति

### संदर्भ

भोपाल में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत ने लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय से 11वीं सदी की वाग्देवी की मूर्ति को वापस लाने के प्रयासों को फिर से शुरू किया।

### वाग्देवी प्रतिमा के बारे में



- सफेद संगमरमर की यह मूर्ति धार के भोजशाला और परमार वंश के राजा भोज से संबंधित है।
- मूल रूप से चार भुजाओं वाली इस मूर्ति की अब केवल दो भुजाएँ हैं, शेष दो टूट गई हैं।
- इसके आधार पर संस्कृत एवं देवनागरी लिपि में राजा भोज, वररुचि व मूर्तिकार मनथला का उल्लेख करने वाले शिलालेख अंकित हैं।
  - वररुचि की पहचान राजा भोज के दरबारी कवि धनपाल के रूप में की जाती है।
- भारतीय विद्वान इसे वाग्देवी या सरस्वती के रूप में पहचानते हैं जबकि ब्रिटिश संग्रहालय इसे जैन देवी अंबिका के रूप में सूचीबद्ध करता है।
- मेजर जनरल विलियम किंकेड ने 1875 में धार के पुराने शहर-महल के खंडहरों से इस मूर्ति का उत्खनन किया था।
- वापसी की यह पहल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद शुरू की गई है जिसमें विवादित भोजशाला परिसर को देवता को समर्पित मंदिर के रूप में मान्यता दी गई है।

## वैश्य टेकरी टीला

### संदर्भ

उज्जैन स्थित वैश्य टेकरी टीले ने लगभग 90 वर्षों के बाद पुरातात्विक ध्यान आकर्षित किया है जब उत्खनन में मौर्य काल के एक विशाल बौद्ध स्तूप के होने के संकेत मिले थे।



### वैश्य टेकरी टीले के बारे में

- मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित यह स्थल सम्राट अशोक के तीसरी सदी ईसा पूर्व के शासनकाल से संबंधित है।
  - प्राचीन उज्जैन, अवंति महाजनपद का एक महत्त्वपूर्ण शहरी केंद्र था, जिसके मौर्य वंश से गहरे संबंध थे।
- 1938-39 के दौरान किए गए उत्खनन से एक बड़े बौद्ध स्तूप के संकेत मिले हैं किंतु बाद में जाँच बंद कर दी गई।
- प्रस्तावित संरचना की ऊँचाई लगभग 100 फीट थी, जो संभवतः साँची के 54 फीट ऊँचे ग्रेट स्तूप से भी अधिक थी।
- इसका अनुमानित 350 फुट व्यास वाला आधार असाधारण रूप से एक विशाल एवं स्मारकीय संरचना का संकेत देता है।
- इससे पहले के पुरातत्वविदों ने अन्य ज्ञात स्थलों से भिन्न असामान्य निर्माण एवं इंजीनियरिंग तकनीकों की जानकारी दी थी।
- आगे के उत्खनन से मौर्य काल के दौरान बौद्ध धर्म एवं स्तूप वास्तुकला के प्रसार को स्पष्ट किया जा सकता है।
- मध्य प्रदेश सरकार ने दोबारा जाँच की मांग की है जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी शामिल है।

## वंदे मातरम्

### संदर्भ

भारत के 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले में वंदे मातरम् का गायन किया गया।

### वंदे मातरम के बारे में

- इसका उच्चारण बंदे मातरम् भी किया जाता है। इसकी रचना बंकिम चन्द्र चटर्जी ने की थी।
- यह पहली बार 7 नवंबर, 1875 को बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ और बाद में इसे आनंदमठ (1882) में शामिल किया गया।
- रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध की गई यह रचना एकता, त्याग एवं मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है।
- 1937 में कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने इसके पहले दो छंदों को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया।
- 24 जनवरी, 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रगान के समान ही सम्मानित घोषित किया।
- संविधान में राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है; अनुच्छेद 51A(a) के तहत संविधान, ध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की आवश्यकता है।

### स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- यह एक राष्ट्रवादी युद्धघोष बन गया, जिसके चलते औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसके सार्वजनिक गायन एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया।
- टैगोर ने इसे 1896 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में गाया था; इसके पहले दो छंद को कांग्रेस की सभा में गाए जाने की प्रथा बन गई।
- यह 7 अगस्त, 1905 को कलकत्ता में विभाजन विरोधी छात्र जुलूसों के दौरान एक राजनीतिक नारा बन गया।
- 1905 के वाराणसी कांग्रेस अधिवेशन में इसे अखिल भारतीय अवसरों के लिए अपनाया गया, जबकि कर्जन ने गायकों की गिरफ्तारी का आदेश दिया।
- अक्टूबर 1905 में गठित बंदे मातरम् संप्रदाय ने रविवार प्रभात फेरी का आयोजन किया और चंदा इकट्ठा किया।
- अंग्रेजी दैनिक 'बंदे मातरम' की शुरुआत 1906 में बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें श्री अरबिंदो संयुक्त संपादक थे।
- इसे आजाद हिंद की अंतरिम सरकार की घोषणा के दौरान भी गाया गया था।
- 1938 के वंदे मातरम् आंदोलन के दौरान हैदराबाद-कर्नाटक के छात्रों को अवज्ञापूर्ण गीत गाने के लिए गिरफ्तारियों एवं निष्कासन का सामना करना पड़ा।
- 1907 में मैडम भीकाजी कामा के स्टुटगार्ट ध्वज पर वंदे मातरम् शब्द अंकित थे।
- कहा जाता है कि मदन लाल ढिंगरा ने फाँसी से पहले 'बंदे मातरम' का उच्चारण किया था; इसी नाम की एक पत्रिका 1909 में जिनेवा से प्रकाशित हुई थी।
- 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले का केप टाउन में वंदे मातरम् के उच्चारण के साथ स्वागत किया गया।

EKACADEMY YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

# अंतर्राष्ट्रीय संबंध



## संपादकीय

### भारत की विदेश नीति में समुद्र आधारित दृष्टिकोण

'भारत की विदेश नीति को समुद्र की ओर देखना चाहिए' (India's foreign policy must look seaward) शीर्षक वाला यह संपादकीय 25 जुलाई, 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसमें समुद्री कूटनीति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है जो सीमाओं, झंडों और अधिकार क्षेत्रों के पार भारतीय नाविकों की रक्षा करती है।

### एक खंडित समुद्री सुरक्षा प्रणाली

- भारतीय नाविक अक्सर विदेशी नियोक्ताओं के माध्यम से कई अधिकार क्षेत्रों में विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर काम करते हैं जिससे हमलों, हिरासत या परित्याग के दौरान जिम्मेदारी का बिखराव होता है।
- हाल ही में पश्चिम एशिया में हुए संघर्ष से जुड़े हमलों में मारे गए 14 भारतीयों में से कम से कम आठ वाणिज्यिक नाविक थे जो ऐसे युद्धों में फँस गए थे, जिससे कांसुलर सुरक्षा में मौजूद कमियाँ उजागर होती हैं।
- जून 2025 में भारत में लगभग 3.2 लाख नाविक थे, जो 2014 के आँकड़े से लगभग तीन गुना अधिक है और वैश्विक कार्यबल का 12% से अधिक हिस्सा भारत से आता है, जो केवल फिलीपींस के बाद दूसरे स्थान पर है।
- भारत की वाणिज्य दूतावास प्रणाली क्षेत्रीय रूप से संगठित होने के कारण नाविक लगातार विभिन्न क्षेत्राधिकारों को पार करते रहते हैं; दूतावासों को उनकी उपस्थिति के बारे में केवल जब्ती या परित्याग के बाद ही पता चलता है, जिससे कोई भी प्राधिकरण लगातार जवाबदेह नहीं रहता है।
- इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने 2025 में 1,125 परित्यक्त भारतीय नाविकों को दर्ज किया, जो दुनिया में सबसे अधिक संख्या है और इसकी जिम्मेदारी ध्वज राज्यों, मालिकों, बीमाकर्ताओं, बंदरगाहों और मिशनों के बीच वितरित है।

### आपातकालीन प्रतिक्रिया से लेकर निरंतर सुरक्षा तक

- संघर्ष के बाद की सीफेरर फर्स्ट प्रतिक्रिया में प्रत्येक भारतीय नाविक, जहाज और खतरे पर नजर रखी जानी चाहिए, चाहे जहाज का झंडा किसी भी देश का हो, साथ ही प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।
- जोखिम पश्चिम एशिया से परे काला सागर और लाल सागर में मिसाइलों, ड्रोन और बारूदी सुरंगों तक तथा अदन की खाड़ी और पश्चिम अफ्रीका के आसपास समुद्री डकैती या बंधक बनाने की घटनाओं तक फैला हुआ है, जिसके लिए निरंतर जोखिम-आधारित निगरानी की आवश्यकता है।
- एक ट्रैकिंग डैशबोर्ड मालिकों या ध्वज राज्यों को कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है; अतः भर्ती एजेंसियों को संकट संकेतों के बाद स्पष्ट जिम्मेदारी वाले एक स्थायी समुद्री प्रोटोकॉल के तहत सक्रिय होने पर अद्यतन चालक दल और मार्ग डेटा प्रदान करना होगा।
- प्रमुख शिपिंग केंद्रों में भारतीय मिशनों को बंदरगाहों, अस्पतालों, बीमाकर्ताओं और वकीलों से जुड़े नामित अधिकारियों की आवश्यकता होती है क्योंकि समुद्री आपातकाल के बाद स्थानीय प्रतिक्रिया नेटवर्क को तात्कालिक रूप से तैयार नहीं किया जा सकता है।
- जब वेतन मिलना बंद हो जाए या चालक दल को बचाव, परित्याग सहायता और स्वदेश वापसी की आवश्यकता हो, तो भारत को ध्वज राज्यों पर समुद्री श्रम अभिसमय को लागू करने के लिए दबाव डालना चाहिए।

### राजनयिक समन्वय और नाविकों के अधिकार

- भारत के द्विपक्षीय समुद्री समझौते प्रमाणपत्रों को मान्यता देते हैं और रोजगार का विस्तार करते हैं, लेकिन कानूनी सहायता, कांसुलर पहुँच, हिरासत और स्वदेश वापसी जैसे मुद्दों को अपर्याप्त रूप से संबोधित करते हैं।
- भारत, फिलीपींस और इंडोनेशिया को आईएमओ व आईएलओ के माध्यम से सामान्य मानकों का पालन करना चाहिए, जिससे जहाज मालिकों को कहीं और से भर्ती करके एकतरफा सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने से रोका जा सके।
- भारत को वाणिज्यिक जहाजों पर होने वाले हमलों का विरोध करना चाहिए, चाहे हमलावर कोई भी हो, क्योंकि नागरिक चालक दल लड़ाके नहीं होते हैं और खुले समुद्री मार्ग उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।
- अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से पहले, नाविकों को पोत के स्वामित्व, मार्ग, प्रतिबंधों के जोखिम, बीमा की वैधता और परित्याग के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही, उन्हें बिना किसी दंड के निर्दिष्ट उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनाती से इनकार करने का अधिकार भी होना चाहिए।
- जहाजरानी महानिदेशालय ने लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों को नियमों का पालन न करने पर 366 परित्यक्त जहाजों पर भारतीयों को

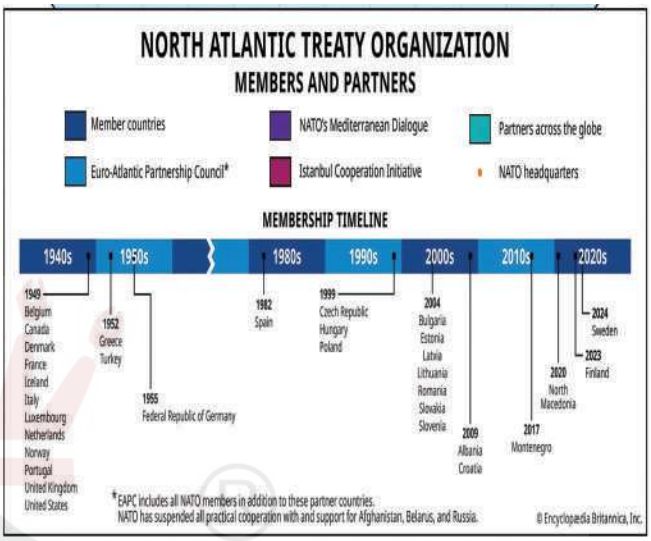
नियुक्त करने से रोक दिया है; एजेंसियों को भर्ती से पहले इस सूची का खुलासा करना होगा और उल्लंघन के लिए दंड का सामना करना पड़ेगा।

### घरेलू नाविक संरक्षण कानून को मज़बूत करना

- **कानूनी समेकन :** मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025 ने जहाजों को छोड़ने के खिलाफ सुरक्षा उपाय पेश किए और घरेलू व विदेशी जहाजों के लिए भारतीयों की भर्ती करने वाली एजेंसियों के विनियमन को मज़बूत किया।
- **एकीकृत रजिस्ट्री :** भारत नाविकों के रिकॉर्ड को आईएमओ-आईएलओ डेटाबेस से जोड़ सकता है जो विशिष्ट जहाजों, मालिकों और ध्वज राज्यों से जुड़े परित्याग के मामलों की पहचान करता है।
- **एजेंसी की जवाबदेही :** समुद्री श्रम नियम, 2016 भर्ती एजेंसियों को विनियमित करते हैं, जबकि संयुक्त दायित्व धोखाधड़ी वाले अनुबंधों और असुरक्षित जहाजों पर नियुक्ति को रोक सकता है।
- **वित्तीय सुरक्षा :** समुद्री श्रम सम्मेलन के तहत जहाज मालिकों द्वारा अपने कर्मचारियों को छोड़ने की स्थिति में अवैतनिक वेतन, आवश्यक आपूर्ति और स्वदेश वापसी को कवर करने वाली वित्तीय गारंटी की आवश्यकता होती है।
- **आपातकालीन सहायता :** सीफेरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी बीमा व गंभीर बीमारियों के लिए सहायता प्रदान करती है और आपातकालीन प्रत्यावर्तन कोष के लिए एक संस्थागत आधार प्रदान करती है।
- **कानूनी संरक्षण :** आईएमओ के 2025 के दिशा-निर्देश हिरासत में लिए गए नाविकों को मनमानी हिरासत से बचाते हैं, साथ ही उचित प्रक्रिया, वेतन, स्वास्थ्य सेवा और स्वदेश वापसी के अधिकारों को भी संरक्षित करते हैं।
- **अनुपालन निरीक्षण :** वैश्विक स्तर पर जहाजों को छोड़ने के मामलों में 2023 में 142 से बढ़कर 2024 में 310 की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप ऑडिट, लाइसेंस निलंबन और जहाजों को ब्लैकलिस्ट करने की आवश्यकता पड़ी।

## रणनीतिक परिवर्तन के एक नए युग में नाटो

'नाटो परिवर्तन के एक नए रणनीतिक युग में प्रवेश करता है' (NATO enters a new strategic era of transformation) शीर्षक वाला यह संपादकीय 5 अगस्त, 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसमें नाटो के यूरोपीय रक्षा जिम्मेदारी की ओर बदलाव, अमेरिकी सैन्य निर्भरता में कमी और भारत के लिए उभरते रणनीतिक अवसरों पर प्रकाश डाला गया है।




### अमेरिका का रणनीतिक पुनर्संतुलन

- अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, 2025 में नाटो को बरकरार रखा गया है, लेकिन यूरोप से इसकी पारंपरिक रक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी संभालने की अपेक्षा की गई है।
- अमेरिका नाटो के जीडीपी के 5% रक्षा-खर्च लक्ष्य का समर्थन करता है जबकि खुद को एकमात्र सैन्य रीढ़ के बजाय रणनीतिक सहायक, परमाणु गारंटर और राजनीतिक संयोजक के रूप में पुनर्स्थापित कर रहा है।
- रूस द्वारा 2022 में किए गए आक्रमण के बाद यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाकर लगभग 1,00,000 करने के बाद, अमेरिका ने इसे घटाकर 75,000-80,000 कर दिया, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर केंद्रित नीति को दर्शाता है।
- अंकारा शिखर सम्मेलन, 2026 ने अनुच्छेद 5 की पुष्टि की, यूक्रेन के लिए 70 अरब यूरो देने का वादा किया और यूरोपीय देशों की लंबी दूरी की मारक क्षमता और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया।

### नाटो का विकास और यूरोपीय क्षमता में मौजूद कमियाँ

- नाटो 1.0 (1949-1991) सोवियत संघ को रोकने और ट्रांसअटलांटिक एकता को बनाए रखने के लिए अमेरिकी सैन्य और परमाणु शक्ति पर निर्भर था।
- नाटो 2.0 (1991-2022) का विस्तार पूर्व की ओर हुआ और इसने बाल्कन एवं अफगान अभियानों का संचालन किया, जबकि यूरोपीय खर्च में गिरावट से अमेरिकी क्षमताओं पर निर्भरता बढ़ गई।
- यूक्रेन के बाद के नाटो 3.0 में यूरोप की परिकल्पना की गई है, जो पारंपरिक रक्षा का नेतृत्व करेगा जबकि अमेरिका परमाणु प्रतिरोध, खुफिया जानकारी, सटीक हमले और वैश्विक शक्ति प्रदर्शन प्रदान करेगा।

YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

- हेग शिखर सम्मेलन, 2025 की प्रतिबद्धता के तहत सदस्य देशों को 2034 तक रक्षा पर होने वाले मुख्य खर्च को जीडीपी के 3.5% तक बढ़ाना होगा, जबकि जर्मनी का लक्ष्य इसे 2029 तक हासिल करना है।
- यूरोप अभी भी अमेरिकी खुफिया व निगरानी, उपग्रह सहायता, हवाई परिवहन, मिसाइल रक्षा कमान प्रणाली, सटीक हमले और परमाणु प्रतिरोध पर निर्भर है।
- इसलिए यूरोप को एकीकृत क्षमताओं का विकास करना चाहिए जो नाटो की प्रभावशीलता को आधार प्रदान करें, जिसका लक्ष्य अमेरिकी सैन्य शक्ति की नकल करने के बजाय रूस से अधिक मज़बूत बनना हो।

## भारत के लिए रणनीतिक निहितार्थ

- यूरोप की अधिक जिम्मेदारी से अमेरिका का राजनयिक ध्यान, सैन्य संसाधन और निवेश हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ओर केंद्रित हो सकेगा, जिससे चीन के विरुद्ध क्षेत्रीय संतुलन मज़बूत होगा।
- एक मज़बूत यूरोप रक्षा विनिर्माण, उन्नत प्रौद्योगिकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष सहयोग में भारत का समर्थन कर सकता है।
- भारत को नाटो के रूपांतरण को एक रणनीतिक अवसर के रूप में लेना चाहिए और रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना अमेरिका व यूरोप के साथ पूरक साझेदारी का उपयोग करना चाहिए।

### संपादकीय के अतिरिक्त

### *भारत के लिए रणनीतिक जोखिम*

- **रणनीतिक स्वायत्तता :** भारत एक साथ क्वाड और शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेता है; नाटो के साथ घनिष्ठ संबंध इस लचीली, मुद्दे-आधारित बहु-संरेखण रणनीति को कमजोर कर सकता है।
- **रूसी साझेदारी :** नाटो की बढ़ती भागीदारी के चलते भारत के रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा संबंधों पर दबाव पड़ सकता है जिनमें ब्रह्मोस, एस-400 प्रणाली और कुडनकुलम रिएक्टर शामिल हैं।
- **यूक्रेन पर मतभेद :** भारत ने रूस की निंदा करने वाले अधिकांश संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों से परहेज किया और संवाद को प्राथमिकता दी, जो नाटो के सैन्य सहायता और प्रतिबंध-आधारित दृष्टिकोण के विपरीत था।
- **चीन का परिप्रेक्ष्य :** नाटो की 2022 की रणनीतिक अवधारणा में चीनी नीतियों को सहयोगी देशों के हितों के लिए चुनौती के रूप में वर्णित किया गया है; परिणामस्वरूप भारतीय सहयोग को चीन को नियंत्रित करने में भागीदारी के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है।
- **यूरेशियाई असंतुलन :** नाटो द्वारा मॉस्को पर डाले गए दबाव ने रूस-चीन अभिसरण को मज़बूत किया है जिसे 2024 के वाशिंगटन शिखर सम्मेलन में एक प्रमुख रणनीतिक चिंता के रूप में पहचाना गया था।
- **क्षेत्रीय ध्रुवीकरण :** ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड के साथ नाटो की प्रमुख इंडो-पैसिफिक परियोजनाएँ एशियाई सुरक्षा में यूरो-अटलांटिक ब्लॉक की प्रतिद्वंद्विता को आयात कर सकती हैं।
- **संस्थागत विषमता :** भारत का नाटो के साथ केवल परामर्शदात्री संबंध है जबकि जापान और अन्य हिंद-प्रशांत साझेदारों के पास अंतरसंचालनीयता, साइबर-रक्षा एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को कवर करने वाले विशिष्ट कार्यक्रम हैं।

## मक्का समझौते के रूप में एक नया सुरक्षा त्रिकोण

'मक्का समझौते के साथ एक नया सुरक्षा त्रिकोण उभरता है' (A new security triangle emerges with the Makkan Pact) शीर्षक वाला यह संपादकीय 10 अगस्त, 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसमें सऊदी अरब-तुर्की-पाकिस्तान रक्षा समझौते के अनिश्चित रणनीतिक महत्त्व एवं भारत पर इसके प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।

## समझौते का रणनीतिक संदर्भ

- 7 अगस्त, 2026 को हस्ताक्षरित मक्का संयुक्त रक्षा समझौता अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद पहला क्षेत्रीय पुनर्गठन है।
- इसके सामूहिक रक्षा प्रावधान के तहत किसी एक सदस्य पर हमले को सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है जो नाटो के अनुच्छेद 5 के समान है।
- यह समझौता सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रक्षा समझौते और 14 देशों के एमएमडीए (MMDA) के बाद हुआ है जो रियाद द्वारा सुरक्षा विकल्पों की तलाश को दर्शाता है।
- सऊदी अरब किसी सैन्य या सांप्रदायिक गुट के गठन से इनकार करता है, फिर भी यह समझौता परमाणु महत्त्वाकांक्षाओं, हथियारों की होड़ और विशिष्ट खतरों पर मौन बना हुआ है।
- इजराइल, ईरान और अमेरिकी प्रभाव को लेकर मतभेदों के कारण मुस्लिम नाटो की संभावना कम ही रहती है जबकि मौजूदा अरब-इस्लामी संस्थाएँ इससे बाहर ही रहती हैं।

## आंतरिक विरोधाभास और अनिश्चित उपयोगिता

- सऊदी अरब की ऑटोमन शासन की यादें, एर्दोगन की क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाएँ और खशोगी विवाद रियाद व तुर्की के बीच रणनीतिक विश्वास को जटिल बनाते हैं।
- तुर्की द्वारा मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास व सीरियाई मिलिशिया को दिया गया समर्थन खाड़ी राजतंत्रों की सुरक्षा प्राथमिकताओं तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है।

YOU GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

- ईरान, यमन या शिया बलों का सामना करने में पाकिस्तान की अनिच्छा, साथ ही सैन्य कमान को लेकर विवाद, सऊदी सुरक्षा के प्रति उसकी सैन्य प्रतिबद्धता को सीमित करते हैं।
- पाकिस्तान की ईरान सीमा, शिया आबादी और भारत तथा अफगानिस्तान के साथ तनाव व्यापक रक्षा दायित्वों को पूरा करने की उसकी क्षमता को अधिक सीमित कर देते हैं।
- रियाद को तेल अवसंरचना, होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब अल-मंडेब के लिए असममित खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें अमेरिकी केंद्रीय कमान भी पूरी तरह से बेअसर नहीं कर सकी है।
- सऊदी अरब के वित्तपोषण, तुर्की के हथियार उत्पादन और पाकिस्तान की विशाल सेना के माध्यम से साझेदार रक्षा क्षेत्र में पर्याप्त पूरकता प्रदान करते हैं जिससे अभ्यास, अंतरसंचालन क्षमता एवं सह-उत्पादन संभव हो पाता है।
- क्षेत्रीय तनाव के लंबे समय तक बने रहने के दौरान यह समझौता मज़बूत हो सकता है किंतु शांति की स्थिति में यह अप्रासंगिक हो जाएगा या ईरान के साथ संघर्ष के दौरान अप्रभावी हो जाएगा यदि तुर्की व पाकिस्तान प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बचते हैं।
- सऊदी अरब द्वारा सुरक्षा के क्षेत्र में विविधता लाना वाशिंगटन से पूरी तरह अलग होना नहीं है क्योंकि तीनों साझेदार अमेरिकी प्रभाव से काफी हद तक बंधे हुए हैं।

### भारत के लिए निहितार्थ

- भारत को पाकिस्तान द्वारा अपने खिलाफ समझौते को लागू करने के प्रयासों पर नजर रखनी चाहिए किंतु साझेदारों के परस्पर विरोधी हितों और बाधाओं को देखते हुए रणनीतिक अतिप्रतिक्रिया से बचना चाहिए।
- कच्चे तेल के प्रमुख आयातक के रूप में भारत की स्थिति और सऊदी अरब के प्रमुख व्यापारिक भागीदार होने के कारण टिकाऊ आर्थिक पूरकता तथा साझा यथास्थिति अभिविन्यास को समर्थन मिलता है।
- रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण भारत के खिलाफ पाकिस्तानी दुस्साहस का सऊदी अरब द्वारा समर्थन किए जाने की संभावना नहीं है जिससे इस्लामाबाद की राजनयिक और सैन्य रणनीति काफी हद तक अप्रभावी हो जाती है।

#### संपादकीय के अतिरिक्त

#### भारत की समुद्री ऊर्जा सुरक्षा पर इसके परिणाम

- **चेकपॉइंट भेद्यता :** होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों के सुरक्षित मार्ग के लिए खाड़ी देशों के साथ भारत का 2026 तक का समन्वय निर्बाध क्षेत्रीय नौवहन पर उसकी निर्भरता को दर्शाता है।
- **शिपिंग में व्यवधान :** 2019 में ओमान की खाड़ी में हुए टैंकर हमलों के बाद भारत ने ऑपरेशन संकल्प शुरू किया और आईएनएस चेन्नई एवं आईएनएस सुनायना को तैनात किया।
- **एस्कॉर्ट की आवश्यकता :** 2022 तक ऑपरेशन संकल्प के तहत 36 युद्धपोत तैनात किए गए थे और लगभग 36.1 मिलियन टन माल ले जाने वाले 453 भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षा प्रदान की गई थी।
- **समुद्री निगरानी :** गुरुग्राम स्थित आईएफसी-आईओआर (IFC-IOR) ने 2019 के संकट के दौरान खाड़ी देशों में जहाजों के आवागमन की निगरानी की, जिससे ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा के लिए सूचना साझाकरण के महत्त्व का पता चलता है।
- **आरक्षित सीमा :** विशाखापत्तनम, मंगलुरु एवं पड़ूर में भारत के 5.33 मिलियन मीट्रिक टन के रणनीतिक भंडार, बाहरी आपूर्ति में लंबे समय तक होने वाली बाधाओं के खिलाफ एक सीमित सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- **आपूर्तिकर्ता विविधीकरण :** भारत ने 2026 में लगभग 41 देशों से कच्चे तेल का आयात किया, जिससे भू-राजनीतिक या समुद्री संकटों के दौरान किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम हो गई।
- **साथी पर निर्भरता:** संयुक्त अरब अमीरात भारत के कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है, जिसके लिए उभरते सुरक्षा गुटों के बावजूद स्थिर खाड़ी संबंधों की आवश्यकता है।

## मुख्य परीक्षा

### मोल्डोवा और उत्तरी मैसेडोनिया

#### संदर्भ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2026 में मोल्डोवा और उत्तरी मैसेडोनिया का दौरा किया तथा दोनों देशों की राजकीय यात्रा करने वाली वे पहली भारतीय राष्ट्रपति बनीं।



## मोल्डोवा यात्रा के मुख्य बिंदु

- **क्षमता निर्माण :** भारत ने मोल्डोवा के पेशेवरों के लिए भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) में प्रशिक्षण सीटों की संख्या दोगुनी कर दी है।
- **आर्थिक सहभागिता :** राष्ट्रपति ने व्यापार, निवेश एवं सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत-मोल्डोवा व्यापार मंच को संबोधित किया।
- **रणनीतिक प्रोफाइल :** मोल्डोवा रोमानिया एवं यूक्रेन के बीच स्थित एक भू-आबद्ध पूर्वी यूरोपीय देश है जो 2022 में यूरोपीय संघ का उम्मीदवार बना और इसमें अलगाववादियों के नियंत्रण वाला ट्रांसनिस्ट्रिया भी शामिल है।




## उत्तरी मैसेडोनिया की यात्रा के मुख्य बिंदु

- **विकास सहयोग :** भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित आईटीईसी स्लॉट्स की संख्या दोगुनी कर दी और उत्तरी मैसेडोनिया द्वारा आईएसए, सीडीआरआई और जीबीए में शामिल होने के इरादे का स्वागत किया।
- **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध :** राष्ट्रपति ने क्रांतिकारी गोसे डेलचेव को सम्मानित किया, जबकि मदर टेरेसा के साथ स्कोप्जे का संबंध सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करता है।
- **रणनीतिक प्रोफाइल :** बाल्कन क्षेत्र का यह भू-आबद्ध देश पाँच देशों से सटा हुआ है और इसने 2019 में अपना वर्तमान नाम अपनाया। यह नाटो का सदस्य है और भूमध्य सागर को मध्य यूरोप से जोड़ता है।

## मोल्डोवा और उत्तरी मैसेडोनिया का रणनीतिक महत्त्व

- **यूरोपीय संपर्क :** मज़बूत संबंध पूर्वी यूरोप एवं बाल्कन क्षेत्रों में भारत की भागीदारी को विविधता प्रदान करते हैं। जुलाई 2026 में दोनों देशों की पहली राष्ट्रपति यात्राओं ने भारत की विस्तारित क्षेत्रीय कूटनीति को प्रतिबिंबित किया।
- **बाजार पहुँच :** मोल्डोवा 2022 से यूरोपीय संघ का उम्मीदवार देश है, जबकि उत्तरी मैसेडोनिया को 2005 से उम्मीदवार देश का दर्जा प्राप्त है, जिससे भारतीय व्यवसायों को विकसित हो रहे यूरोपीय बाजारों के साथ उपयोगी संबंध बनाने का अवसर मिलता है।
- **आर्थिक अवसर :** औषधियाँ, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, वस्त्र, पर्यटन एवं नवीकरणीय ऊर्जा में अपार संभावनाएँ हैं। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन :** रोमानिया के साथ मोल्डोवा के संबंध और यूरोपीय परिवहन गलियारों पर उत्तरी मैसेडोनिया की स्थिति पड़ोसी बाजारों की सेवा करने वाले विविध लॉजिस्टिक्स, कृषि-प्रसंस्करण एवं फार्मास्युटिकल नेटवर्क का समर्थन कर सकती है।
- **प्रौद्योगिकी साझेदारी :** भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता साझा कर सकता है। इसने उभरती प्रौद्योगिकियों में विशेष पाठ्यक्रमों सहित दोनों देशों के लिए आईटीईसी प्रशिक्षण सीटों की संख्या दोगुनी कर दी है।
- **जलवायु नेतृत्व :** मोल्डोवा पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से भारत के साथ सहयोग कर रहा है जबकि उत्तरी मैसेडोनिया ने आईएसए, सीडीआरआई और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है।
- **भू-राजनीतिक प्रासंगिकता :** मोल्डोवा यूक्रेन संघर्ष और ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करता है जबकि उत्तरी मैसेडोनिया की नाटो सदस्यता और यूरोपीय संघ की आकांक्षाएँ बाल्कन व यूरो-अटलांटिक मामलों के बारे में भारत की समझ को मज़बूत करती हैं।
- **सॉफ्ट पावर का प्रभाव :** शैक्षिक आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण से भारत की सद्भावना मज़बूत होती है। स्कोप्जे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण और मदर टेरेसा के साथ शहर का जुड़ाव सांस्कृतिक संबंधों को अधिक मज़बूत करता है।

## द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में बाधाएँ

- **सीमित व्यापार :** भारत-मोल्डोवा का व्यापार 2025-26 में केवल 11.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य के बावजूद भारत-उत्तरी मैसेडोनिया का व्यापार कम बना हुआ है।
- **छोटे घरेलू बाजार :** इन देशों में से प्रत्येक की आबादी तीन मिलियन से कम है जिससे पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ सीमित हो जाती हैं और ये देश भारतीय निवेशकों के लिए बड़े यूरोपीय बाजारों की तुलना में कम आकर्षक बन जाते हैं।

UKACADEMY YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

- **कनेक्टिविटी संबंधी बाधाएँ :** दोनों देश चारों ओर से भू-आबद्ध हैं और भारत के साथ मज़बूत सीधे परिवहन संपर्क का अभाव है जिससे रसद लागत बढ़ जाती है और व्यापार, निवेश एवं पर्यटन की आवाजाही प्रतिबंधित हो जाती है।
- **राजनयिक उपस्थिति का कमजोर होना :** बुखारेस्ट में भारत के राजदूत को मोल्डोवा के लिए भी मान्यता प्राप्त है जबकि सोफिया में भारत के राजदूत उत्तरी मैसेडोनिया का कार्यभार संभालते हैं जिससे निरंतर राजनयिक व वाणिज्यिक संपर्क सीमित हो जाते हैं।
- **नियामकीय संक्रमण :** यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए उत्पाद, पर्यावरण, निवेश और डेटा-सुरक्षा मानकों के साथ व्यापक सामंजस्य की आवश्यकता होती है जिससे भारतीय निर्यातकों व निवेशकों के लिए अल्पकालिक अनुपालन लागत उत्पन्न होती है।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता :** यूक्रेन संघर्ष एवं ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवा को प्रभावित करते हैं जबकि उत्तरी मैसेडोनिया का विलय उसके बल्गेरियाई अल्पसंख्यक और द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं से संबंधित संवैधानिक संशोधनों से जुड़ा हुआ है।
- **सीमित व्यावसायिक जागरूकता :** कमजोर व्यावसायिक नेटवर्क, भाषाई अंतर और छोटे भारतीय समुदाय आपसी सहयोग को सीमित करते हैं। अपनी तरह के पहले 2026 भारत-मोल्डोवा व्यापार मंच ने सीमित संस्थागत सहयोग को उजागर किया।

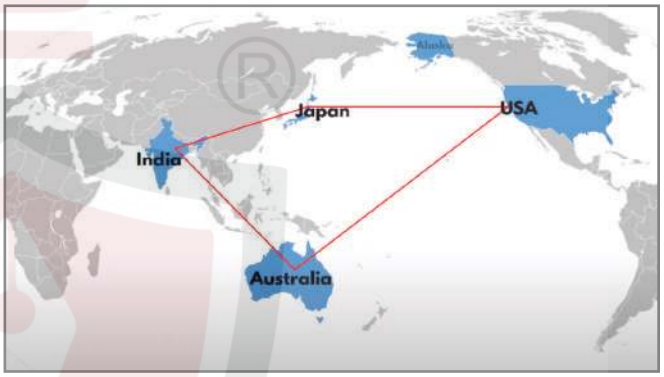
## मज़बूत द्विपक्षीय जुड़ाव के लिए ढाँचा

- **संस्थागत संवाद :** विदेश कार्यालय परामर्शों, मंत्रिस्तरीय आदान-प्रदान और व्यापार मंचों को नियमित करना, जिन्हें मज़बूत स्थानीय राजनयिक और वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व द्वारा समर्थित किया जाए।
- **व्यापार रोडमैप :** सीआईआई-इन्वेस्ट मोल्डोवा समझौते और उत्तरी मैसेडोनिया के 2030 व्यापार लक्ष्य का उपयोग करते हुए फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए क्षेत्रीय समूह बनाना।
- **क्षेत्रीय रणनीति :** मोल्डोवा के यूरोपीय संघ में एकीकरण और उत्तरी मैसेडोनिया के बाल्कन क्षेत्र में स्थित होने का लाभ उठाकर पूर्वी यूरोपीय एवं यूरोपीय बाजारों तक व्यापक पहुँच प्राप्त करना।
- **बेहतर कनेक्टिविटी :** रोमानिया एवं ग्रीस के माध्यम से लॉजिस्टिक्स को मज़बूत करना, व्यावसायिक वीजा को सरल बनाना और पेशेवर आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत-मोल्डोवा गतिशीलता ढाँचे का उपयोग करना।
- **नियामक सहयोग :** यूरोपीय संघ के उत्पाद, पर्यावरण, निवेश एवं डेटा-सुरक्षा मानकों के संबंध में भारतीय व्यवसायों की सहायता के लिए निर्यात सहायता डेस्क स्थापित करना।
- **परियोजना-आधारित सहयोग :** वुलकैनेस्टी-चिशिनाउ ट्रांसमिशन लाइन मॉडल का अनुसरण करते हुए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य सेवा व स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दृश्यमान परियोजनाएँ विकसित करना।
- **लोगों के बीच संबंध :** आईटीईसी (ITEC) प्रशिक्षण सीटों की संख्या दोगुनी करके छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालय साझेदारी, पर्यटन एवं छात्र सुरक्षा का विस्तार करना।

# क्वाड द्वारा आसियान की केंद्रीयता का समर्थन

## संदर्भ

चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) के विदेश मंत्रियों ने एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस आउटलुक ऑन द इंडो-पैसिफिक (AOIP) को लागू करने के लिए समर्थन की पुष्टि की है जिससे आसियान की केंद्रीयता और एक स्वतंत्र, मुक्त एवं समावेशी क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा सके।




## आसियान केंद्रीयता के बारे में

यह पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच और एडीएमएम-प्लस (ADMM-Plus) जैसे तंत्रों के माध्यम से क्षेत्रीय संस्थानों, एजेंडों एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया को आकार देने में आसियान की अग्रणी भूमिका को संदर्भित करता है।

## आसियान की केंद्रीयता का महत्त्व

- **तटस्थ संयोजक :** आसियान के नेतृत्व वाले मंच, जैसे कि ईस्ट एशिया समिट, प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय एवं वैश्विक शक्तियों के बीच समावेशी संवाद को बढ़ावा देते हैं।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा :** आसियान क्षेत्रीय मंच और एडीएमएम-प्लस संयुक्त समुद्री एवं आपदा राहत अभ्यासों सहित विश्वास निर्माण, रक्षा संवाद व व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं।
- **आर्थिक एकीकरण :** आसियान के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी अपने 15 सदस्य देशों में क्षेत्रीय व्यापार, निवेश एवं आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत करती है।
- **नियम-आधारित व्यवस्था :** मैत्री एवं सहयोग संधि संप्रभुता, गैर-हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और क्षेत्रीय विवादों के वार्तात्मक समाधान को बढ़ावा देती है।
- **रणनीतिक संतुलन :** आसियान की केंद्रीय भूमिका किसी एक शक्ति के प्रभुत्व को रोकने में मदद करती है और अमेरिका-चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के बीच क्षेत्रीय स्वायत्तता को संरक्षित करती है।

- **कार्यात्मक सहयोग :** आसियान तंत्र कनेक्टिविटी, आतंकवाद रोधी उपायों और अंतरराष्ट्रीय अपराध पर कार्रवाई का समन्वय करते हैं जबकि AHA केंद्र क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन एवं मानवीय सहायता का समर्थन करता है।

## आसियान की केंद्रीयता के लिए चुनौतियाँ

- **संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता :** बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दबाव के कारण आसियान के सदस्य देशों को किसी एक पक्ष का साथ देना पड़ता है जिससे क्षेत्रीय संस्थानों के भीतर एकता और आम सहमति कमजोर हो जाती है।
- **आम सहमति की सीमाएँ :** हस्तक्षेप न करने और आम सहमति पर आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया संकट के दौरान सामूहिक कार्रवाई में देरी करती है, जैसा कि म्यांमार के सैन्य तख्तापलट के प्रति आसियान की सीमित प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है।
- **लघुपक्षीयवाद का उदय :** क्वाड और ऑस्ट्रेलिया-यूनाइटेड किंगडम-संयुक्त राज्य अमेरिका (AUKUS) साझेदारी जैसे समूह आसियान की क्षेत्रीय एजेंडा-निर्धारण भूमिका को कम कर सकते हैं।
- **भिन्न राष्ट्रीय हित :** चीन पर असमान आर्थिक निर्भरता और अलग-अलग सुरक्षा चिंताओं के कारण सदस्य देशों में विभाजन है, खासकर दक्षिण चीन सागर विवादों को लेकर।
- **संस्थागत सीमाएँ :** आसियान की कमजोर प्रवर्तन शक्तियाँ एवं सीमित सचिवालय क्षमता समझौतों के कार्यान्वयन और समन्वित क्षेत्रीय प्रतिक्रियाओं में बाधा डालती हैं।

### क्वाड

- क्वाड भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बना एक अनौपचारिक रणनीतिक समूह है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और जबरदस्ती से मुक्ति पर आधारित एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी एवं समृद्ध इंडो-पैसिफिक का समर्थन करता है।
- 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद चारों देशों के बीच मानवीय समन्वय के परिणामस्वरूप इस समूह का गठन हुआ।
- जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2007 में इस विचार को व्यक्त किया था; चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच 2017 में क्वाड को पुनर्जीवित किया गया था।
- 2021 के क्वाड की भावना ने लोकतांत्रिक मूल्यों, विधि के शासन और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की पुष्टि की।
- क्वाड-एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन तटरक्षक बल की अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देता है जबकि मालाबार अभ्यास क्वाड सदस्यों के बीच नौसैनिक समन्वय को मज़बूत करता है।
- दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड एवं वियतनाम के साथ क्वाड प्लस की सहभागिता व्यापक मुद्दे-आधारित साझेदारी की संभावनाओं को दर्शाती है।

## समकालीन वैश्विक व्यवस्था में क्वाड की प्रासंगिकता

- **रणनीतिक प्रतिसंतुलन :** क्वाड यथास्थिति में जबरदस्ती किए गए परिवर्तनों का विरोध करता है, नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और दक्षिण चीन सागर, ताइवान जलडमरूमध्य और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून को सुदृढ़ करता है।
- **आर्थिक सुरक्षा :** क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव और लचीली अवसंरचना साझेदारी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाती है, चीन+1 रणनीति की पूरक है और भारत की विनिर्माण क्षमता को मज़बूत करती है।
- **उभरती प्रौद्योगिकियाँ :** 5जी व 6जी, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और समुद्र के नीचे बिछे केबलों में सहयोग सुरक्षित डिजिटल कनेक्टिविटी को मज़बूत करता है।
- **क्षेत्रीय सार्वजनिक वस्तुएँ :** संयुक्त स्वास्थ्य सेवा पहल और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) सहयोग से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपदा की तैयारी व त्वरित प्रतिक्रिया में सुधार होता है।

## आसियान की केंद्रीयता के लिए क्वाड के समर्थन को विश्वसनीय बनाना

- **AOIP संरेखण :** क्वाड पहलों को AOIP की चार प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना : समुद्री सहयोग, कनेक्टिविटी, सतत विकास लक्ष्य और आर्थिक सहयोग।
- **संस्थागत आधार :** ईस्ट एशिया समिट, आसियान रीजनल फोरम और एडीएमएम-प्लस जैसे आसियान के नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से प्रमुख कार्यक्रमों का संचालन करना।
- **पूरक लघुपक्षीयवाद :** आसियान की क्षेत्रीय भूमिका को कमजोर करने वाली समानांतर संस्थाओं का निर्माण किए बिना, समुद्री क्षमता की कमियों को दूर करने के लिए आईपीएमडीए (IPMDA) जैसी पहलों का उपयोग करना।
- **आसियान स्वामित्व :** आसियान के सदस्य देशों और संस्थानों के साथ मिलकर परियोजनाओं का सह-डिजाइन तैयार करना, यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्रीय आवश्यकताएँ प्राथमिकताओं को निर्धारित करें न कि बाहरी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा।
- **सार्वजनिक वस्तुओं की डिलीवरी :** एएचए सेंटर और आसियान के आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र जैसे संस्थानों के साथ आपदा राहत, स्वास्थ्य सेवा व अवसंरचना कार्यक्रमों का समन्वय करना।
- **समावेशी स्थिति :** पारदर्शी और गैर-विशिष्ट सहयोग बनाए रखना, सैन्य गठबंधन की धारणाओं से बचना या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को चीन के खिलाफ एकजुट होने के लिए बाध्य न करना।
- **कार्यान्वयन विश्वसनीयता :** 2026 के मनीला समझौतों के साथ पूर्वानुमानित वित्त पोषण, समयसीमा और स्थानीय क्षमता निर्माण को जोड़ना, जिससे राजनयिक आश्वासनों को मापन योग्य क्षेत्रीय लाभों में परिवर्तित किया जा सके।

## प्रारंभिक परीक्षा

### अमेरिका-सऊदी नागरिक परमाणु सहयोग समझौता

#### संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब ने अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम की धारा 123 के तहत 30 साल के नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, साथ ही एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।

#### मुख्य प्रावधान

- इस समझौते के तहत सऊदी अरब को नागरिक परमाणु सामग्री, उपकरण, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का हस्तांतरण संभव हो सकेगा।
  - इसके कार्यान्वयन के लिए सऊदी अरब को अब्राहम समझौते में शामिल होना और इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना आवश्यक है।
- सऊदी अरब की अरबों डॉलर की नागरिक परमाणु अवसंरचना के विकास में अमेरिकी कंपनियों को प्राथमिकता मिलेगी।
- सऊदी अरब शुरू में अपने प्रस्तावित परमाणु रिएक्टरों के संचालन के लिए परमाणु ईंधन का आयात करेगा।
- दो साल के संयुक्त अध्ययन में घरेलू स्तर पर यूरेनियम संवर्धन की व्यावसायिक व्यवहार्यता का आकलन किया जाएगा।
- प्रस्तावित ब्लैक-बॉक्स व्यवस्था संवेदनशील संवर्धन प्रौद्योगिकी को अमेरिकी नियंत्रण में रखेगी।
- यदि यह संभव हो तो अमेरिकी कंपनियाँ सऊदी अरब को संवेदनशील प्रौद्योगिकी हस्तांतरित किए बिना संवर्धन सुविधाएँ स्थापित और संचालित करेंगी।
- 2009 के अमेरिका-यूएई समझौते के विपरीत सऊदी अरब को स्थायी रूप से संवर्धन या प्रयुक्त ईंधन पुनर्संसाधन को त्यागने की आवश्यकता नहीं है।
- इस समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त प्रोटोकॉल को अपनाने की आवश्यकता नहीं है जो दखलंदाजी वाले निरीक्षणों को सीमित करता है।
- आलोचकों का कहना है कि दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों की अनुमति देने से वैश्विक परमाणु अप्रसार मानदंडों को कमजोर किया जा सकता है।

### बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा गठबंधन

#### संदर्भ

चौदह देशों ने बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी के माध्यम से नौवहन की सुरक्षा के लिए एक समुद्री गठबंधन की स्थापना की।

#### बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा गठबंधन के बारे में

- इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों पर जहाजरानी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की रक्षा करना है।
- यह गठबंधन समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है और नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
- सऊदी अरब, यमन, कुवैत, बहरीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्किये, मिस्र, जॉर्डन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया इसके सदस्य हैं।
- सऊदी अरब इस गठबंधन का संस्थापक एवं प्रमुख सदस्य है और गठबंधन के स्थायी मुख्यालय की मेजबानी करता है।
- यह गठबंधन पूरी तरह से रक्षात्मक है और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार कार्य करता है।

### दक्षिण चीन सागर विवाद

#### संदर्भ

चीन ने स्कारबोरो शोल के आसपास स्थित हुआंगयान दाओ राष्ट्रीय प्रकृति अभयारण्य के लिए प्रबंधन उपाय जारी किए हैं जिसमें नियमित गश्त और अनधिकृत मछली पकड़ने या संसाधन निष्कर्षण के लिए दंड का प्रावधान शामिल है।

#### दक्षिण चीन सागर के बारे में

- यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक रणनीतिक सीमांत सागर है जो मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से प्रशांत एवं हिंद महासागर को जोड़ता है।
- यह ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम से घिरा हुआ है।
- चीन द्वारा 1947 में निर्धारित नाइन-डैश लाइन इस समुद्र के लगभग 90% हिस्से पर अपना दावा करती है जो कई देशों के समुद्री दावों के साथ ओवरलैप करती है।
- स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने 2016 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के तहत इन दावों को अमान्य घोषित कर दिया; चीन ने इस फैसले को खारिज कर दिया।
- पैरासेल द्वीप समूह, जिसमें लगभग 130 द्वीप और चट्टानें शामिल हैं, चीन के नियंत्रण में हैं किंतु वियतनाम व ताइवान दोनों ही इस पर अपना दावा करते हैं।
- स्प्रैटली द्वीप समूह, जिसमें सेकंड थॉमस शोल भी शामिल है, पर चीन, वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया व ब्रुनेई दावा करते हैं।
- स्कारबोरो शोल फिलीपींस के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के भीतर स्थित है किंतु ऐतिहासिक आधार पर चीन इस पर अपना दावा करता है।

IKAS ACADEMY YOUR GUIDE TO THE FIRST MILESTONE

# प्रशासन/सार्वजनिक नीति/ सरकारी योजनाएँ



## संपादकीय

### फास्ट ट्रैक न्यायालय और शीघ्र न्याय का वादा

'क्या फास्ट-ट्रैक अदालतों ने त्वरित न्याय के वादे को पूरा किया है?' (Have fast-track courts delivered on the promise of speedy justice?) शीर्षक वाला यह संपादकीय 31 जुलाई, 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सीमित न्यायिक क्षमता, प्रक्रियात्मक देरी और संसाधनों की कमी किस प्रकार फास्ट-ट्रैक अदालतों द्वारा त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में बाधक है।

### प्रदर्शन और संरचनात्मक सीमाएँ

- फास्ट-ट्रैक कोर्ट चुनिंदा मामलों में तेजी लाते हैं, लेकिन आम तौर पर वे कुल न्यायिक क्षमता बढ़ाने के बजाय मौजूदा जजों को ही दूसरे कामों में लगाते हैं, जिससे दूसरे मामलों में देरी होने लगती है।
- प्रभावी कामकाज के लिए पर्याप्त न्यायाधीश, सहायक कर्मचारी, समय पर गवाहों के बयान, समन्वित हितधारक व कम अनावश्यक स्थगन आवश्यक हैं।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 के तहत पेपर लीक मामलों के लिए एक फास्ट-ट्रैक अदालत का गठन किया है जिससे उनकी प्रभावशीलता पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

### लंबित मामले और डेटा अंतराल

- फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में लगभग 2.45 लाख मामले लंबित हैं क्योंकि सालाना निपटान लगातार नए मामलों के आने की संख्या से कम रहा है।
- 2025 में, लगभग 1.4 लाख मामले दर्ज किए गए, लेकिन केवल 66,000 मामलों का निपटारा किया गया, जिससे केस-निपटान दर 100% से नीचे रही।
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड में तुलनीय एफटीएससी निपटान-समय डेटा का अभाव है, जिससे यह पारदर्शी आकलन करना संभव नहीं है कि क्या ये अदालतें तेजी से न्याय प्रदान करती हैं।
- एफटीएससी में लंबित मामलों की संख्या व्यापक न्यायिक तनाव को दर्शाती है, जिसमें निचली अदालतों में लगभग 4.8 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से लगभग 74% आपराधिक मामले हैं।

### समयसीमा और समावेशी पहुँच

- प्रस्तावित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 में दो महीने की जाँच और तीन महीने के मुकदमे का प्रावधान है, लेकिन संस्थागत क्षमता शायद इतनी कठोर समयसीमा का समर्थन न कर पाए।
- जटिल आपराधिक मामलों में अनिवार्य समयसीमा, बचाव पक्ष की तैयारी, साक्ष्य मूल्यांकन और गवाह प्रबंधन को सीमित करके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से समझौता कर सकती है।
- समयसीमा में त्वरित न्याय और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के बीच संतुलन होना चाहिए; महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निपटान में सुधार कर सकते हैं, लेकिन कठोर आदेश न्यायिक गुणवत्ता को कम कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 14 के तहत फास्ट-ट्रैक सुनवाई वाली अदालतों को मामले सौंपते समय तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार का पालन किया जाना चाहिए, न कि जनमत या चुनिंदा नीतिगत प्राथमिकताओं का।

### संसाधन घाटे और सुधार

- बलात्कार और बाल यौन शोषण के मामलों के लिए 2019 में गठित एफटीएससी न्यायाधीशों, अभियोक्ताओं और परिचालन संसाधनों की कमी से ग्रस्त हैं।
- सरकारी अभियोजक अक्सर कई अदालतों का कार्यभार संभालते हैं, जबकि कर्मचारियों की कमी के कारण फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण में देरी होती है और जटिल अभियोजन कमजोर हो जाते हैं।
- त्वरित न्याय के लिए विश्वसनीय जाँच, प्रशिक्षित कर्मियों, समय पर फोरेंसिक सहायता, पर्याप्त अभियोजन समर्थन और न्यायिक रिक्तियों का पूर्ण होना आवश्यक है।
- पहले से समय निर्धारित करने, अदालत के त्वरित निर्देशों और स्थगन को कम करने से सुनवाई को बाधित किए बिना प्रक्रियात्मक देरी को कम किया जा सकता है।

#### संपादकीय के अतिरिक्त

*त्वरित न्यायनिर्णय के विकल्प*

- **केस-फ्लो प्रबंधन :** वाणिज्यिक न्यायालयों का ढाँचा प्रारंभिक केस-प्रबंधन सुनवाई और साक्ष्य और तर्कों के लिए निश्चित कार्यक्रम अनिवार्य करता है, जो नियमित न्यायालयों के लिए एक मॉडल प्रदान करता है।
- **मुकदमे से पहले की मध्यस्थता :** मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 5 विवादों को दर्ज करने से पहले निपटाने में सक्षम बनाती है, जबकि मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त मामलों को इससे बाहर रखा गया है।

- **लोक अदालतें :** NALSA की लोक अदालतें लंबित और मुकदमे से पहले के विवादों को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से सुलझाती हैं, और निर्णयों को अंतिम एवं बाध्यकारी दीवानी अदालत के फैसलों के रूप में माना जाता है।
- **प्ली बारगेन :** बीएनएसएस की धारा 290 पात्र अभियुक्त व्यक्तियों को आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर प्ली बार्गेनिंग की मांग करने की अनुमति देती है जिससे अनावश्यक फुल ट्रायल को कम किया जा सके।
- **वर्चुअल कोर्ट :** दिसंबर 2024 तक, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 27 वर्चुअल अदालतों ने 6.36 करोड़ से अधिक यातायात मामलों का निपटारा किया था।
- **ग्राम स्तर पर न्याय :** भारत में 338 कार्यरत ग्राम न्यायालय थे, जिनमें से 111 उत्तर प्रदेश में और 89 मध्य प्रदेश में थे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के वादियों के लिए छोटे-मोटे विवादों का समाधान आसान हो गया था।
- **न्यायिक डिजिटलीकरण :** ई-कोर्ट्स के तीसरे चरण में पेपरलेस अदालतों, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और व्यापक ऑनलाइन न्यायनिर्णय के लिए ₹7,210 करोड़ का परिव्यय निर्धारित है।

## गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के दस वर्ष

'दस साल बाद, एक सच्चे जीईएम पर पीछे और आगे की ओर नजर' शीर्षक वाला यह संपादकीय 11 अगस्त, 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जो पारदर्शिता, दक्षता एवं समावेशी भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के एक दशक लंबे परिवर्तन को उजागर करता है।

### GeM से खरीद प्रक्रिया में परिवर्तन

- 9 अगस्त, 2016 को लॉन्च किया गया GeM 1.37 लाख सरकारी खरीदारों को 25 लाख विक्रेताओं एवं सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है।
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस प्रमुख खरीद कार्यों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है, जो समावेशी विकास और विकसित भारत 2047 का समर्थन करता है।
- GeM ने अप्रभावी आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय का स्थान लिया है जिससे खरीद प्रक्रिया के लिए एक ऐसा खुला मंच तैयार हुआ जिस पर पहले विशेषाधिकार प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं का वर्चस्व था।
- खोज, बोली, अनुबंध एवं भुगतान सहित संपूर्ण खरीद प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से मनमानी में कमी आती है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।
- प्रत्येक लेन-देन एक लेखापरीक्षण योग्य रिकॉर्ड निर्मित करता है जिससे सरकारी खरीद में जवाबदेही, ईमानदारी एवं जनता का विश्वास मजबूत होता है।
- सरलीकृत पंजीकरण, मानकीकृत प्रक्रियाएँ और जमानत राशि जमा एवं लेनदेन शुल्क को हटाने से भागीदारी संबंधी बाधाएँ कम हो गई हैं।




### समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता

- घरेलू उद्यमों को प्राथमिकता देने से स्थानीय मूल्य शृंखलाओं, स्वदेशी उत्पादन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलती है।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम कुल ऑर्डर की मात्रा का लगभग 60% और GeM के सकल व्यापार मूल्य का 45% से अधिक हिस्सा बनाते हैं।
- सरकारी खरीदारों तक सीधी पहुँच से स्टार्ट-अप और महिला नेतृत्व वाले उद्यम मध्यस्थों या स्थापित बाजार के लाभों के बिना प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होते हैं।
- लोकतांत्रिक खरीद प्रक्रिया छोटे व्यवसायों को सक्रिय विकास भागीदार बनाती है जिससे उद्यमिता एवं समान विकास को बढ़ावा मिलता है।
- दवाओं, टीकों, रक्षा सामग्री, ड्रोन एवं बुनियादी ढाँचे की कुशल खरीद से सार्वजनिक सेवा वितरण और संसाधन उपयोग में सुधार होता है।

### पैमाना, लाभ एवं भविष्य की दिशा

- GeM ने विगत दो वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में 5 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक GMV को पार कर लिया है जिससे इसका संचयी मूल्य लगभग 20 लाख करोड़ रुपए हो गया।
- बाजार में अब 10,644 उत्पाद श्रेणियाँ और 350 सेवा श्रेणियाँ शामिल हैं जो इसके बढ़ते खरीद दायरे को दर्शाती हैं।
- आईआईटी दिल्ली के एक अध्ययन में तीन वित्तीय वर्षों में मौद्रिक मूल्य और प्रक्रिया-दक्षता लाभ के रूप में ₹86,571.69 करोड़ का अनुमान लगाया गया है।
- GeM का दूसरा दशक एक ऐसे स्मार्ट एवं पर्यावरण अनुकूल प्लेटफॉर्म की तलाश में है जो वैश्विक स्तर पर मानकीकृत हो और उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित हो।

❖ भविष्य में होने वाले विस्तार से हितधारकों की भागीदारी और गहन होगी, विशेष रूप से नवप्रवर्तकों, स्टार्ट-अप्स, महिलाओं, युवाओं, छोटे शहरों के उद्यमियों और वंचित समूहों के बीच।

संपादकीय के अतिरिक्त

*डिजिटल खरीद जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा उपाय*

- **साइबर सुरक्षा संरक्षण :** GeM को CERT-In की छः घंटे की घटना-रिपोर्टिंग आवश्यकता का पालन करना चाहिए और संवेदनशील खरीद एवं विक्रेता डेटा की सुरक्षा के लिए आवधिक सुरक्षा ऑडिट करना चाहिए।
- **एल्गोरिथम पारदर्शिता :** चूँकि GeM विक्रेता रेटिंग कई L1 प्रस्तावों में से चयन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए रेटिंग मानदंड स्पष्ट, समीक्षा योग्य और पूर्वाग्रह से मुक्त होने चाहिए।
- **मिलीभगत का पता लगाना :** GeM विक्रेताओं को कार्टेलाइजेशन के खिलाफ चेतावनी देता है, जबकि CCI का डायग्नोस्टिक टूलकिट खरीद अधिकारियों को संदिग्ध बोली पैटर्न और समन्वित कोटेशन की पहचान करने में मदद करता है।
- **डिजिटल समावेशन :** GeM पहले से ही 12 भाषाओं में इंटरैक्टिव विक्रेता-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है; सहायता प्राप्त ऑनबोर्डिंग में सीमित डिजिटल क्षमता वाले ग्रामीण उद्यमों को भी शामिल किया जा सकता है।
- **डेटा सुरक्षा :** GeM द्वारा वित्तीय एवं वाणिज्यिक जानकारी के प्रबंधन में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें उद्देश्य सीमा व सुरक्षित प्रसंस्करण शामिल है।
- **बाजार संकेंद्रण :** ऑनलाइन उद्यम सत्यापन से एमएसई खरीद के लाभ मिलते हैं किंतु खरीद विश्लेषण के माध्यम से कुछ प्रमुख विक्रेताओं द्वारा बार-बार अनुबंध हथियाने से रोकना चाहिए।
- **शिकायत के लिए जवाबदेही :** GeM की घटना प्रबंधन नीति और लंबित भुगतान संबंधी शिकायत निवारण तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूची से हटाने, भुगतान एवं संविदात्मक शिकायतों की समयबद्ध समीक्षा की जाए।

## राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग

12 अगस्त, 2026 को द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय 'इन द वे' (In the way) इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग पर कार्यपालिका का नियंत्रण न्यायाधिकरण की स्वतंत्रता एवं न्यायिक स्वायत्तता को किस प्रकार कमजोर करता है।

### न्यायाधिकरण का उद्देश्य और न्यायिक सुरक्षा उपाय

❖ न्यायाधिकरण सामान्य अदालतों की तुलना में तकनीकी विवादों का विशेष रूप से निपटारा तेजी से करने में सक्षम बनाते हैं जिससे न्यायिक दक्षता मजबूत होती है।

❖ एस.पी. संपत कुमार (1987) और एल. चंद्र कुमार (1997) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की समीक्षा को बरकरार रखा है क्योंकि न्यायिक समीक्षा मूल ढाँचा का निर्माण करती है।

❖ न्यायाधिकरण संरचनात्मक रूप से कमजोर बने रहते हैं क्योंकि उनका प्रशासन उन्हीं सरकारी मंत्रालयों द्वारा किया जाता है जिनके निर्णयों की स्वतंत्र समीक्षा आवश्यक होती है।

❖ रोजर मैथ्यू (2019) वाद में न्यायालय ने न्यायाधिकरणों के चयन एवं प्रशासन की स्वतंत्र रूप से निगरानी करने के लिए एक वैधानिक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की सिफारिश की।

### विधायी इतिहास और प्रस्तावित सुधार

❖ वित्त अधिनियम, 2017 ने नियुक्तियों पर कार्यकारी नियंत्रण का विस्तार किया है जबकि 2021 के अध्यादेश ने उन सेवा शर्तों को बहाल किया जिन्हें पहले ही न्यायिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।

❖ मद्रास बार एसोसिएशन (2025) वाद में न्यायालय ने पुनः अधिनियमित आपत्तिजनक प्रावधानों को रद्द कर दिया और चार महीने के भीतर NTC की स्थापना का निर्देश दिया।

❖ संसद ने 10 अगस्त को लोकसभा में चर्चा किए बिना ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026 पारित कर दिया, जिसके बाद 11 अगस्त को राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी।

❖ इस विधेयक में पाँच वर्ष के कार्यकाल को बहाल किया गया है, सेवा शर्तों को मानकीकृत किया गया है, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड स्थापित किया गया है और लंबित नियुक्तियों की सुरक्षा की गई है।

### संस्थागत कमजोरियों का जारी रहना

❖ धारा 14, इस तरह के विधायी प्रत्यायोजन के न्यायिक विरोध के बावजूद, योग्यता, चयन प्रक्रिया, वेतन एवं सेवा शर्तों को कार्यकारी नियमों को सौंपती है।

❖ धारा 3 में अस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है जो कार्यकारी विवेकाधिकार की अनुमति देता है जो कि इस विधेयक द्वारा 2025 के फैसले के अनुपालन के दावे के विपरीत है।

❖ धारा 16 के तहत, संबंधित मंत्रालय एनटीसी जाँच से पहले शिकायतों की जाँच करता है जिससे निष्कासन कार्यवाही पर कार्यकारी प्रभाव बरकरार रहता है।

❖ केंद्र सरकार सभी एनटीसी सदस्यों की नियुक्ति स्वयं करती है, न्यायिक नियुक्तियों के लिए केवल मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करती है, जबकि पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण अपने पास रखती है।

## संपादकीय के अतिरिक्त

### *न्याय तक पहुँच के परिणाम*

- **संस्थागत विश्वसनीयता :** मद्रास बार एसोसिएशन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका-प्रभुत्व वाले न्यायाधिकरण नियमों को बार-बार रद्द किया, जिसमें स्वतंत्रता को सीधे जनता के विश्वास से जोड़ा गया।
- **मामलों में विलंब :** एनसीएलटी (NCLT) में रिक्तियाँ एवं दिवालियापन की लंबी कार्यवाही आईबीसी के 330-दिवसीय समाधान ढाँचे को विफल कर सकती हैं, जिससे लेनदारों और संकटग्रस्त व्यवसायों के लिए वसूली में देरी हो सकती है।
- **मुकदमेबाजी की लागत :** एल. चंद्र कुमार वाद के बाद अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा सीएटी के निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है जिससे न्यायाधिकरण के निर्णय विफल होने पर एक अतिरिक्त मुकदमेबाजी चरण जुड़ जाता है।
- **निर्णय की गुणवत्ता :** एनजीटी के न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्यों का संयोजन प्रदूषण, वन संरक्षण व पर्यावरणीय मुआवजे जैसे तकनीकी मामलों पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
- **कानूनी निश्चितता :** 2017, 2020 और 2021 में जारी किए गए लगातार न्यायाधिकरण नियमों को न्यायिक रूप से अमान्य घोषित कर दिया गया, जिससे नियुक्तियों, कार्यकाल व सेवा शर्तों को लेकर अस्थिरता पैदा हो गई।
- **समान न्याय :** सीएटी सरकारी कर्मचारियों को नाममात्र ₹50 शुल्क पर आवेदन करने की अनुमति देता है जो दर्शाता है कि सुलभ न्यायाधिकरण औपचारिक अदालती खर्चों को किस प्रकार कम कर सकते हैं।
- **सार्वजनिक जवाबदेही :** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यह दर्शाता है कि कैसे डिजिटाइज्ड लंबित मामलों और निपटान डेटा न्यायाधिकरणों में समान पारदर्शी प्रदर्शन निगरानी का समर्थन कर सकता है।

## मुख्य परीक्षा

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण

### संदर्भ

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के डिजिटलीकरण व आधुनिकीकरण के सरकारी प्रयासों का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट जारी की।

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में

- **इसके बारे में :** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) भारत का प्रमुख खाद्य सुरक्षा नेटवर्क है, जो पात्र परिवारों को किफायती और रियायती कीमतों पर आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराता है।
- **केंद्र सरकार :** भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से यह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चावल एवं गेहूँ की खरीद करता है, बफर स्टॉक बनाए रखता है, अनाज का परिवहन करता है और उन्हें राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित करता है।
- **राज्य सरकारें :** वे पात्र परिवारों की पहचान करते हैं, राशन कार्ड जारी करते हैं, उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के माध्यम से अनाज वितरित करते हैं और अंतिम छोर तक आपूर्ति की निगरानी करते हैं।

### *सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास*

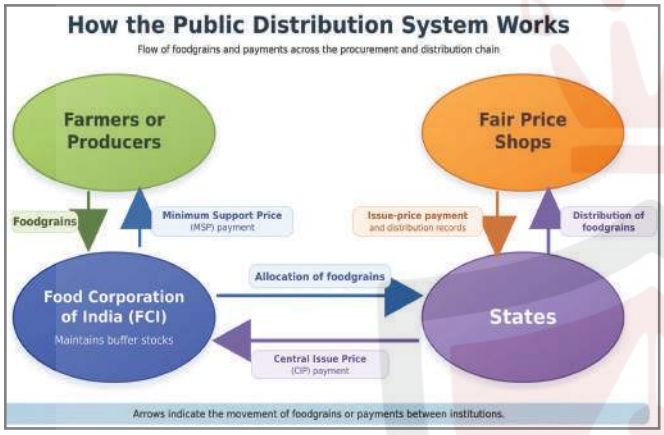
- **1940-1960 के दशक :** युद्धकालीन राशनिंग से उत्पन्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का विस्तार 1960 के दशक में खाद्य पदार्थों की कमी के दौरान हुआ, जिसे भारतीय खाद्य निगम और कृषि मूल्य आयोग का समर्थन प्राप्त था। बाद में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया।
- **1992 :** पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने दूरस्थ, पिछड़े एवं दुर्गम क्षेत्रों तक खाद्य वितरण का विस्तार किया।
- **1997 :** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए अलग-अलग कवरेज व कीमतों की शुरुआत की।
- **2000 :** अंत्योदय अन्न योजना के तहत सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया गया।
- **2013 :** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने खाद्य सहायता को एक कानूनी अधिकार बना दिया, जो ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक को कवर करता है।

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपलब्धियाँ

- **व्यापक कवरेज :** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) लगभग 80.5 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करती है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा नेटवर्क में से एक बन जाती है।
- **डिजिटल रिकॉर्ड :** लगभग सभी लाभार्थियों के डेटा को डिजिटाइज कर दिया गया है, जिससे 20.5 करोड़ से अधिक राशन कार्डों का एक पारदर्शी रजिस्टर तैयार हो गया है।
- **आधार एकीकरण :** लगभग 99.8% राशन कार्ड कम से कम एक सदस्य के लिए आधार से जुड़े हुए हैं जिससे डुप्लिकेट या अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलती है।

YOUR GUIDE TO THE NEW MINDSET

- **FPS स्वचालन :** 5.43 लाख उचित मूल्य की दुकानों में से लगभग 99.6% दुकानें इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल उपकरणों का उपयोग करती हैं जिनमें 97% से अधिक लेनदेन आधार प्रमाणीकरण द्वारा कवर किए जाते हैं।
- **राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी :** 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना प्रवासी मजदूरों और लाभार्थियों को देश भर में किसी भी भाग लेने वाली 'उचित मूल्य की दुकान' (फेयर प्राइस शॉप) से अपने हिस्से का खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा देती है।




## सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण से जुड़े मुद्दे

- **वित्तीय दबाव :** 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने से 2025-26 के लिए संशोधित खाद्य सब्सिडी का अनुमान बढ़कर लगभग 2.28 लाख करोड़ रुपये हो गया है जिससे सिंचाई, कोल्ड चेन और कृषि अनुसंधान में निवेश सीमित हो सकता है।
- **रिसाव एवं गुणवत्ता संबंधी जोखिम :** वर्ष 2022-23 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर आधारित ICRIER के एक अनुमान में 28% अनाज की हेराफेरी पाई गई; डिजिटल प्रमाणीकरण निम्न गुणवत्ता वाले स्टॉक के साथ हेराफेरी या सत्यापन के बाद प्रतिस्थापन को नहीं रोक सकता है।
- **समावेशन त्रुटियाँ :** जनगणना 2011 पर आधारित सीमाएँ कई नए गरीब और शहरी प्रवासियों को बाहर कर देती हैं जबकि आधार, बायोमेट्रिक एवं कनेक्टिविटी की विफलताएँ वास्तविक लाभार्थियों को पहुँच से वंचित कर सकती हैं।
- **एफपीएस व्यवहार्यता :** बिजली, कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल के रखरखाव का बोझ कम मार्जिन वाले डीलरों पर पड़ता है, जिससे संभावित रूप से कारोबार बंद करने या कम वजन का सामान बेचने, जैसे कि 5 किलोग्राम के बजाय 4.5 किलोग्राम सामान उपलब्ध कराने को प्रोत्साहन मिलता है।
- **पोषण की कमी :** अनाज प्रधान पीडीएस कैलोरी तो प्रदान करता है लेकिन आहार विविधता सीमित होती है; छः राज्यों के एक अध्ययन में पाया गया कि नमूना में शामिल 80% परिवारों ने अपर्याप्त प्रोटीन का सेवन किया।
- **ONORC की बाधाएँ :** अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी में डीलरों द्वारा अस्वीकृति, स्टॉक आवंटन में देरी और प्रमाणीकरण विफलताओं जैसी समस्याएँ आती हैं; अंतरराज्यीय लेनदेन अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी लेनदेन की तुलना में काफी कम रहते हैं।
- **डिजिटल विश्वसनीयता :** SARTHAK-PDS वास्तविक समय की कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है; ऑफलाइन प्रमाणीकरण पहुँच की सुरक्षा करता है लेकिन विलंबित सिंक्रनाइजेशन ऑडिट ट्रेल्स को कमजोर करता है और धोखाधड़ी वाले लेनदेन के जोखिम को बढ़ाता है।

## स्थायी समिति की प्रमुख सिफारिशें

- **लाभार्थी सत्यापन :** लाभार्थियों के रिकॉर्ड को सही करने के लिए अनिवार्य फील्ड सत्यापन के साथ एक समयबद्ध, मिशन-मोड अभियान चलाना।
- **व्यापक कवरेज :** पात्र लेकिन बहिष्कृत परिवारों, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों की पहचान करना और उन्हें शामिल करना।
- **एकीकृत डिजिटल प्रणाली :** संचालन को मानकीकृत करने और पारदर्शिता, दक्षता एवं सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए केंद्रीय व राज्य प्लेटफार्मों को एकीकृत करके स्मार्ट-पीडीएस को लागू करना।
- **अंतिम-मील कनेक्टिविटी :** दूरस्थ एवं नेटवर्क रहित क्षेत्रों में स्थित उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर ऑफलाइन सिंक्रोनाइजेशन और वैकल्पिक प्रमाणीकरण प्रदान करना।
- **एफपीएस आधुनिकीकरण :** शिकायत निवारण और लेनदेन में पारदर्शिता को मजबूत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल उपकरणों को वजन मशीनों से जोड़ना।
- **डेटा एकीकरण :** सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान और निगरानी के लिए पीडीएस डेटाबेस को भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से जोड़ना।
- **आपूर्ति शृंखला अनुकूलन :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित अन्न चक्र को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करना, इसे पीएम गति शक्ति के साथ एकीकृत करना और परिवहन लागत को कम करने के लिए लॉजिस्टिक्स की लगातार निगरानी करना।

# लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम, 2026

## संदर्भ

संसद द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 को मंजूरी दे दी।

## लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम, 2026 के प्रमुख प्रावधान

- **व्यक्तिगत अपराध :** पेपर लीक करना, प्रतिरूपण करना या उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ करने पर 5 से 10 वर्ष की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

- **संगठित अपराध :** परीक्षा संबंधी गिरोहों और संगठित धोखाधड़ी में शामिल संस्थानों को 7-10 साल की कैद और कम से कम 10 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है।
- **सेवा प्रदाता :** मिलीभगत करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी विक्रेताओं, प्रिंटरों या परीक्षा एजेंसियों को 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आठ साल का प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है।
- **प्रबंधन दायित्व :** सेवा प्रदाताओं के जिम्मेदार निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधकों को 5 से 10 साल की कैद और 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- **समयबद्ध जाँच :** पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों या सरकार द्वारा गठित विशेष कार्यबलों को दो महीने के भीतर जाँच पूरी करनी होगी।
- **विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालय :** राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से दैनिक सुनवाई और तीन महीने के मुकदमों के लिए सत्र न्यायालयों को नामित करना होगा; 2024 अधिनियम के तहत लंबित मामलों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- **अपील :** निर्णय, सजा या जमानत आदेश के खिलाफ अपील प्रायः 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए और दो न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय पीठ द्वारा तीन महीने के भीतर उनका निपटारा किया जाना चाहिए।

### परीक्षा सुधारों पर उच्चाधिकार प्राप्त कार्य बल

- सरकार ने इंफोसिस के सह-संस्थापक और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संस्थापक अध्यक्ष (2009-14) नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में छः सदस्यीय कार्यबल का गठन किया।
- यह सार्वजनिक परीक्षाओं को विश्वसनीय, पारदर्शी, सुरक्षित, छेड़छाड़-रोधी एवं लीक-प्रूफ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित और संस्थागत सुधारों की सिफारिश करेगा।

## भारत की परीक्षा (टेस्टिंग) प्रणाली में सुधार का औचित्य

- **केंद्रीकृत कमजोरियाँ :** पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग और भौतिक परिवहन की केंद्रीकृत प्रणाली से जोखिम के एकल बिंदु बन जाते हैं जहाँ एक भी गड़बड़ी लाखों उम्मीदवारों वाली परीक्षा को प्रभावित कर सकती है।
- **आउटसोर्सिंग के जोखिम :** नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की निजी प्रौद्योगिकी विक्रेताओं एवं परीक्षा केंद्रों पर निर्भरता से सुरक्षा मानकों में असमानता पैदा होती है जिससे सर्वर में सेंध, स्क्रीन-शेयरिंग धोखाधड़ी, प्रॉक्सी उम्मीदवार और संगठित 'सॉल्वर गैंग' जैसी समस्याएँ पैदा होती हैं।
- **योग्यता प्रणाली का क्षरण :** परीक्षा में धांधली से संगठित गिरोहों और संसाधन संपन्न उम्मीदवारों को फायदा होता है, जिससे कानून के समक्ष समानता से संबंधित अनुच्छेद 14 और सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद 16 कमजोर हो जाते हैं।
- **आर्थिक और रोजगार संबंधी लागतें :** पेपर लीक होने, रद्द होने एवं मुकदमों के कारण भर्ती में देरी होती है और उम्मीदवारों के उत्पादक वर्ष बर्बाद होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट, 2024 में बताया गया है कि भारत की बेरोजगार आबादी में युवाओं की संख्या लगभग 83% है जो देश के जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए खतरा है।
- **कोचिंग एवं ऋण का बोझ :** अनिश्चित परीक्षा चक्रों ने अनुमानित ₹50,000 करोड़ से अधिक के कोचिंग उद्योग को बढ़ावा दिया है जिससे कई ग्रामीण और निम्न-मध्यम आय वाले परिवारों को बार-बार फीस, आवास लागत व लंबे समय तक कर्ज का बोझ उठाना पड़ रहा है।
- **मनोवैज्ञानिक और मानवीय लागतें :** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों से पता चलता है कि 2014 और 2024 के बीच छात्र आत्महत्याओं में लगभग 80% की वृद्धि हुई है जिसमें परीक्षा में असफलता भी दर्ज कारणों में से एक है, जो परामर्श एवं संस्थागत सहायता की आवश्यकता को उजागर करता है।
- **तकनीकी अंतराल :** एकसमान जीरो-ट्रस्ट सुरक्षा, एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, रीयल-टाइम ऑडिट ट्रेल और प्रश्न निर्माण की सुरक्षित प्रक्रिया की अनुपस्थिति परीक्षाओं को विकसित हो रहे साइबर हमलों और संगठित लीक नेटवर्क के प्रति संवेदनशील बनाती है।

## एक सुरक्षित सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली का निर्माण

| | |
|---|---|
| सुरक्षित प्रौद्योगिकी | ◆ **जस्ट-इन-टाइम डिलीवरी :** एन्क्रिप्टेड पेपर को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के माध्यम से भेजना, ड्यूल की (Dual-Key) डिक्रिप्शन का उपयोग करना और परीक्षा से केवल 15-30 मिनट पहले ही उन्हें स्थानीय रूप से प्रिंट करना।<br>◆ **प्रश्न यादृच्छिकीकरण :** आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी पर आधारित कैलिब्रेटेड प्रश्न बैंकों का उपयोग करके समान कठिनाई स्तर के विभिन्न प्रश्नपत्र तैयार करना, जिससे लीक हुई उत्तर कुंजी अप्रभावी हो जाए।<br>◆ **सुरक्षित डिजिटल परीक्षण :** एयर-गैप्ड इंट्रानेट के माध्यम से कंप्यूटर-आधारित परीक्षा आयोजित करना, रिमोट-एक्सेस एप्लिकेशन को अक्षम करना और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत उम्मीदवार डेटा की सुरक्षा करते हुए छेड़छाड़-प्रूफ लॉग बनाए रखना। |

YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

| | |
|---|---|
| संस्थागत सुधार | ◆ **सार्वजनिक टेस्टिंग नेटवर्क :** केंद्रीय विद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अनुमोदित सार्वजनिक कॉलेजों को स्थायी टेस्टिंग केंद्रों में उन्नत बनाना, जिससे निजी केंद्रों पर निर्भरता कम हो सके।<br>◆ **नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सुधार :** एजेंसी को पेशेवर कर्मचारी, स्वतंत्र वित्तपोषण और स्पष्ट जवाबदेही प्रदान करें, बजाय इसके कि आउटसोर्स विक्रेताओं पर अत्यधिक निर्भर रहें।<br>◆ **स्वतंत्र लेखापरीक्षण :** मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय द्वारा ऑडिट और आईएसओ/आईईसी 27001 अनुपालन अनिवार्य है, साथ ही अप्रत्याशित निरीक्षण और व्हिसलब्लोअर शिकायतों के लिए एक स्वतंत्र परीक्षा लोकपाल द्वारा समर्थित है। |
| प्रक्रियात्मक सुधार | ◆ **एकाधिक परीक्षा चक्र :** राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा जैसी लगभग 24 लाख उम्मीदवारों वाली एक दिवसीय परीक्षाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य परीक्षा के समान कई सत्रों और सर्वश्रेष्ठ दो या तीन अंकों के आधार पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं से प्रतिस्थापित किया जाए।<br>◆ **स्तरित पहचान जाँच :** पंजीकरण, प्रवेश और कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के दौरान चेहरे, आँखों की पुतली या उंगलियों के निशान के प्रमाणीकरण का उपयोग करके उम्मीदवारों का सत्यापन करना, जिसमें गोपनीयता सुरक्षा उपाय और गैर-आधार विकल्प शामिल हों। |
| दीर्घकालिक सुधार | ◆ **विविध मूल्यांकन :** समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं ज्ञान के विश्लेषण को मजबूत करना ताकि स्कूल बोर्ड के मूल्यांकन को मानकीकृत किया जा सके और कक्षा 12 के प्रदर्शन को प्रवेश परीक्षा के अंकों के साथ जोड़ा जा सके।<br>◆ **कोचिंग विनियमन :** पारदर्शी शुल्क, आनुपातिक धनवापसी, परामर्श एवं भ्रामक रैंक गारंटी या परीक्षा धोखाधड़ी में संलिप्तता के लिए दंड सुनिश्चित करने हेतु कोचिंग सेंटर दिशा-निर्देश 2024 को वैधानिक समर्थन प्रदान करना। |

## प्रारंभिक परीक्षा

### समुद्र मंथन : राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना

#### संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की अपतटीय ऊर्जा क्षमता को उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस, 2025 के विजन को लागू करने वाली समुद्र मंथन परियोजना को मंजूरी दे दी है।

#### योजना के बारे में

- यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- इसमें गहरे पानी, अति गहरे पानी और सीमावर्ती अन्वेषण के लिए 2030-31 तक ₹84,084 करोड़ का परिव्यय निर्धारित है।
- समुद्र में अन्वेषण के लिए पाँच से दस साल लगते हैं जबकि किसी गहरे पानी के कुएँ की लागत 125-150 मिलियन डॉलर होती है।
- मौजूदा तेल एवं गैस क्षेत्रों में वार्षिक प्राकृतिक उत्पादन में लगभग 6-7% की गिरावट देखी जाती है।
- इस योजना का उद्देश्य अन्वेषण से जुड़े जोखिम को कम करना, निवेश आकर्षित करना, उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।
- यह घरेलू ऊर्जा विकास के माध्यम से विकसित भारत, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है।
- इन गतिविधियों में भूकंपीय डेटा का अधिग्रहण एवं व्याख्या, वैज्ञानिक ड्रिलिंग और गहरे पानी में अन्वेषण में वृद्धि शामिल हैं।
- बुनियादी ढाँचे में सामान्य उत्पादन और निकासी केंद्र और एक एकीकृत तेल और गैस विनिर्माण-सेवा क्षेत्र शामिल हैं।
- यह डिजिटल प्रबंधन, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी अपनाने, हितधारकों की सहभागिता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देता है।
- इस आवंटन में 60 कुओं के लिए ₹43,200 करोड़, भूकंपीय सर्वेक्षणों के लिए ₹28,534 करोड़, अवसंरचना केंद्रों के लिए ₹10,000 करोड़ और विनिर्माण-सेवा क्षेत्रों के लिए ₹2,000 करोड़ शामिल हैं।
- सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता पात्र ड्रिलिंग लागत का 50% कवर करती है जो प्रति कुएँ ₹675 करोड़ तक सीमित है।
- प्राथमिकता वाले बेसिनों में कृष्णा-गोदावरी, कावेरी, महानदी और अंडमान क्षेत्र शामिल हैं।

### गोबरधन राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना

#### संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैविक कचरे को स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित करने और ग्रामीण समृद्धि को मजबूत करने के लिए गोबरधन राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना को मंजूरी दी।

LEGACY YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

### योजना के बारे में

- यह पशु अपशिष्ट, फसल अवशेष, रसोई अपशिष्ट और बाजार अपशिष्ट को संपीडित बायोगैस और बायो-स्लरी में परिवर्तित करता है।
- 6 अगस्त, 2026 को स्वीकृत यह परियोजना पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत 2026-27 से 2035-36 तक संचालित होगी।
- इस योजना का परिव्यय ₹23,731 करोड़ है, जो पहले से खंडित संपीड़ित-बायोगैस पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करेगी।
- इसके छः विकास इंजन सुनिश्चित बिक्री, मूल्य निर्धारण, पूंजी समर्थन, पाइपलाइन, क्रेडिट गारंटी और पारिस्थितिकी तंत्र विकास को कवर करते हैं।
- इसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर संपीडित बायोगैस उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाना और निजी निवेश को आकर्षित करना है।
- चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था गाँवों को स्वच्छ ऊर्जा केंद्रों में परिवर्तित करेगी, साथ ही किसानों और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा का समर्थन करेगी।
- भारत अपनी प्राकृतिक गैस का लगभग आधा हिस्सा आयात करता है; द्रवीकृत प्राकृतिक गैस आयात का 55-60% हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
- गोबरधन एकीकृत पंजीकरण पोर्टल सरकारी सहायता के लिए मौजूदा और प्रस्तावित संपीडित बायोगैस या बायो-सीएनजी संयंत्रों को पंजीकृत करता है।
- 6 अगस्त, 2026 तक 1,908 संयंत्र पंजीकृत किए गए थे, जिनमें 217 चालू और 339 निर्माणाधीन संयंत्र शामिल थे।
- चालू संयंत्रों ने सामूहिक रूप से प्रतिदिन 0.4 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर का उत्पादन किया।

## राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

### संदर्भ

संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया, जिससे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के वित्तपोषण और विकास अधिदेश का विस्तार हुआ।

### मुख्य प्रावधान

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए सहकारी विकास में लगी किसी भी सहकारी समिति या संस्था को प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित कर सकता है।
- पहले, प्रत्यक्ष ऋण एवं अनुदान राष्ट्रीय स्तर की और बहु-राज्यीय सहकारी समितियों तक ही सीमित थे।
- विस्तारित प्रत्यक्ष वित्तपोषण चैनल के साथ-साथ राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तपोषण जारी रहेगा।
- अब 'खाद्य पदार्थों' में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य वस्तुएँ शामिल हैं जिससे पात्रता का दायरा बढ़ गया है।
- औद्योगिक सहकारी समितियाँ, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संबद्ध उद्योग अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थित होने की आवश्यकता नहीं है।
- केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से NCDC सहकारी-विकास संस्थाओं की शेयर पूंजी में निवेश कर सकती है।
- NCDC केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के साथ ऋण एवं संबंधित जानकारी का आदान-प्रदान कर सकता है।

### राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के बारे में

- NCDC एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना 1963 में एनसीडीसी अधिनियम, 1962 के तहत की गई थी, जिसे 1973, 1974 और 2002 में इसके अधिदेश एवं प्रत्यक्ष वित्तपोषण शक्तियों का विस्तार करने के लिए संशोधित किया गया था।
- यह सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- यह उत्पादन, उत्पादकता, प्रसंस्करण, भंडारण, कोल्ड चेन, विपणन और फसल कटाई के बाद अन्य बुनियादी ढाँचा के लिए वित्तपोषण करके किसान सहकारी समितियों को बढ़ावा देता है।
- यह डेयरी, पशुधन, हथकरघा, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन सहकारी समितियों का भी समर्थन करता है जिनमें महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व वाली सहकारी समितियां शामिल हैं।
- एनसीडीसी द्वारा किए गए ऋण वितरण 2014-15 में ₹5,735 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹95,182 करोड़ हो गए जो ग्रामीण ऋण क्षेत्र में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
- राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 के तहत एनसीडीसी पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित एवं पेशेवर रूप से प्रबंधित सहकारी समितियों का समर्थन करता है जो विकसित भारत 2047 के अनुरूप हैं।
- इस कार्यान्वयन में इफको, नैफेड, अमूल, कृभको, NDDB, NCEL और नाबार्ड जैसी संस्थाएँ शामिल हैं जो भारत के सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करती हैं।

## वन हर्ब, वन स्टैण्डर्ड पहल

### संदर्भ

आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस पहल के तहत अपनी साझेदारी को तीन साल के लिए नवीनीकृत किया।

### इस पहल के बारे में

- इस पहल के तहत विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों में उपयोग होने वाले औषधीय पौधों के लिए एक समान गुणवत्ता और परीक्षण मानक स्थापित किए गए हैं।

EKAM ACADEMY YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

- इसका कार्यान्वयन भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषध संहिता आयोग और भारतीय औषध संहिता आयोग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
- यह भारतीय औषध संहिता और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी व होम्योपैथिक औषध संहिताओं में प्रयुक्त मोनोग्राफों में सामंजस्य स्थापित करता है।
- इन मानकों में आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी और होम्योपैथी में उपयोग की जाने वाली वनस्पति-आधारित औषधियाँ शामिल हैं।
- वर्ष 2022 में शुरू किए गए पहले चरण में सफलतापूर्वक 50 एकल-जड़ी बूटी मोनोग्राफ विकसित किए गए।
- भारतीय वनस्पति उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता व वैश्विक विश्वसनीयता में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को शामिल किया गया है।
- एक एकीकृत संदर्भ परीक्षण प्रयोगशालाओं, नियामकों और निर्माताओं के लिए परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को समाप्त करता है जिससे व्यापार व अनुपालन को समर्थन मिलता है।

## खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

### संदर्भ

संसद ने खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर राज्य के करों को सीमित करके एक समान राजकोषीय ढाँचा स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया।

### मुख्य प्रावधान

- यह खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करता है जिससे खनिज युक्त भूमि स्पष्ट रूप से केंद्र शासित प्रदेश के विनियमन के अंतर्गत आ जाती है।
- नई धारा 9D राज्यों को केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा खनिज अधिकारों या खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने से रोकती है।
- यह प्रतिबंध खनिजों की मात्रा या मूल्य, रॉयल्टी भुगतान या अन्य मापदंडों पर आधारित शुल्कों पर लागू होता है।
- अदा न किए गए या वसूल न किए गए पिछले शुल्क अमान्य हो जाते हैं जबकि पहले से एकत्र की गई राशि वापस नहीं की जाएगी।
- संशोधित धारा 13 केंद्र सरकार को भविष्य में राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों के लिए मापदंड निर्धारित करने का अधिकार देती है।

### खनिजों को नियंत्रित करने वाला वर्तमान ढाँचा

- संघ सूची प्रविष्टि 54 सार्वजनिक हित में खान एवं खनिज विकास के संसदीय विनियमन की अनुमति देता है।
- राज्य सूची प्रविष्टि 23 में संघ के कानून के अधीन खनिज विकास शामिल है जबकि प्रविष्टि 50 संसदीय सीमाओं के भीतर खनिज अधिकारों पर कराधान की अनुमति देती है।
- राज्य सूची प्रविष्टि 49 खनिज युक्त भूमि सहित भूमि पर कराधान को अधिकृत करता है।
- केंद्र सरकार प्रमुख खनिजों और रॉयल्टी दरों को नियंत्रित करती है; राज्य सरकार पट्टे प्रदान करती है, रॉयल्टी वसूल करती है और मुख्य रूप से लघु खनिजों को नियंत्रित करती है।
- 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि रॉयल्टी खनिज अधिकारों के लिए एक संविदात्मक भुगतान है, न कि कर।

## चुनावी काले धन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

### संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनावों से काले धन को समाप्त करना भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की जिम्मेदारी है।

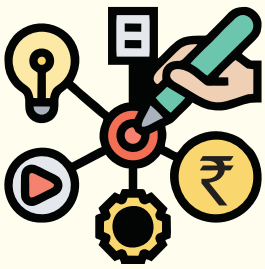
### मुख्य दिशा-निर्देश

- जब्त की गई नकदी या संपत्ति की सूचना 24 घंटे के भीतर जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम न्यायालय को देनी होगी।
- रिपोर्ट में जब्ती एवं संदिग्ध चुनावी अपराधों के बीच प्रथम दृष्टया संबंध स्थापित करना आवश्यक है।
- चुनाव संबंधी प्रथम सूचना रिपोर्ट्स की जाँच सामान्यतः एक वर्ष के भीतर पूरी होनी चाहिए और देरी की सूचना और औचित्य चुनाव आयोग को दी जानी चाहिए।
- जाँच अधिकारियों को चुनाव संबंधी लंबित काले धन के मामलों पर तिमाही स्थिति रिपोर्ट चुनाव आयोग को प्रस्तुत करनी होगी।
- जब भी पकड़ी गई नकदी ₹10 लाख से अधिक हो, तो स्टैटिक सर्विलांस टीमों को इनकम टैक्स अधिकारियों को सूचित करना होगा।
- उच्च न्यायालयों को त्वरित सुनवाई की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर नामित न्यायालयों के माध्यम से सुनवाई करना भी शामिल है।
- चुनाव चक्र से संबंधित उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों को संबंधित उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना वापस नहीं लिया जा सकता है।
- ECI और राज्य सरकारों को 18 नवंबर, 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

❑❑❑

KRATADEMY YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

# विविध



## चर्चित स्थल

| | |
|---|---|
| **सिगुर हाथी गलियारा** | ◆ तमिलनाडु में स्थित सिगुर पठार, जिसे सेगुर भी कहते हैं, एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील गलियारा है जो पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों को जोड़ता है।<br>◆ यह हाथियों की आवाजाही और आनुवंशिक विविधता को सहारा देता है। हाथी भोजन, पानी एवं उपयुक्त आवासों की तलाश में पठार को पार करते हैं।<br>◆ यह दक्षिण-पश्चिम में नीलगिरी पहाड़ियों और उत्तर-पूर्व में मोयार नदी घाटी के बीच स्थित है।<br>◆ यह पठार नीलगिरी जैवमंडल अभयारण्य का हिस्सा है, जो यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल है।<br>◆ सर्वोच्च न्यायालय ने सिगुर पठार से सभी वाणिज्यिक गतिविधियों को हटाने के फैसले को बरकरार रखा है, जिसे हाथी गलियारा घोषित किया गया है। |
| **काला सागर** | ◆ काला सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित एक निम्न ज्वारीय, खारे पानी का अंतरमहाद्वीपीय सागर है।<br>◆ इसे अटलांटिक महासागर का एक सीमांत सागर माना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मेरोमिक्टिक बेसिन है जहाँ गहरे और सतही जल आपस में नहीं मिलते हैं।<br>◆ इसके गहरे पानी के 90% से अधिक हिस्से में ऑक्सीजन की कमी है जिससे समुद्री जीवन गंभीर रूप से सीमित हो जाता है।<br>◆ यह रूस, यूक्रेन, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया व जॉर्जिया से घिरा हुआ है।<br>◆ केर्च जलडमरूमध्य इसे आजोव सागर से जोड़ता है जबकि बॉस्फोरस जलडमरूमध्य इसे मरमरा सागर से जोड़ता है।<br>◆ इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियों में डेन्यूब, नीपर एवं नीस्टर शामिल हैं।<br>◆ यूक्रेन के तट से दूर काला सागर में एक व्यापारिक पोत पर रूसी हमले में चार भारतीय चालक दल के सदस्य मारे गए हैं। |
| **सेउटा एन्क्लेव** | ◆ सेउटा उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्थित एक स्पेनिश स्वायत्त शहर है जो जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के पास मोरक्को की सीमा से लगता है।<br>◆ यह स्पेन एवं यूरोपीय संघ का हिस्सा है, हालाँकि मोरक्को इस पर संप्रभुता का दावा करता है।<br>◆ सेउटा एवं मेलिला अफ्रीका के साथ यूरोपीय संघ की एकमात्र स्थलीय सीमाएँ हैं।<br>◆ मोरक्को से स्पेन के सेउटा एन्क्लेव में प्रवेश करने की कोशिश में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई। |
| **लेक मीड** | ◆ लेक मीड संयुक्त राज्य अमेरिका के मोजावे रेगिस्तान में स्थित एक कृत्रिम जलाशय है।<br>◆ जल भंडारण क्षमता के लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा जलाशय है।<br>◆ इसका निर्माण 1930 के दशक में कोलोराडो नदी पर हूवर बांध के निर्माण के दौरान हुआ था।<br>◆ कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक हिस्सा है।<br>◆ लेक मीड में पानी का स्तर लगभग 90 साल पहले इसके भरने के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। |

LKACADEMY YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

| | |
|---|---|
| **रब-अल-खाली (एम्प्टी क्वार्टर)** | ◆ रब-अल-खाली दुनिया का सबसे बड़ा अविरल रेतीला रेगिस्तान है जो 650,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।<br>◆ यह मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी सऊदी अरब में स्थित है और ओमान, संयुक्त अरब अमीरात व यमन तक फैला हुआ है।<br>◆ यह पृथ्वी के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है जहाँ वार्षिक वर्षा 3 सेंटीमीटर से भी कम होती है।<br>◆ गर्मी के मौसम में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है जिसके बाद रात के दौरान इसमें तेजी से गिरावट आती है।<br>◆ परंपरागत रूप से इस रेगिस्तान में बद्दू (Bedouin) समुदाय निवास करते रहे हैं और इसका उपयोग करते रहे हैं।<br>◆ ओमान और सऊदी अरब ने होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे समुद्री अवरोधों के विकल्प के रूप में सीधे रब-अल-खाली सड़क का उपयोग करते हुए सीमा पार माल ढुलाई समझौते पर हस्ताक्षर किए। |
| **कुरिल द्वीप समूह** | ◆ इस द्वीपसमूह में 22 मुख्य द्वीप, 36 छोटे द्वीप और कई चट्टानें शामिल हैं जो लगभग 15,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं।<br>◆ यह रूस के कामचटका प्रायद्वीप और जापान के होक्काइडो के बीच स्थित है।<br>◆ ये द्वीप पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में ओखोटस्क सागर को अलग करते हैं।<br>◆ ये प्रशांत महासागर के अग्नि-वलय का हिस्सा हैं जहाँ प्रायः भूकंप व ज्वालामुखी उद्‌गार होते रहते हैं।<br>◆ ज्वालामुखीय द्वीप शृंखला में सबडक्शन के माध्यम से निर्मित स्ट्रैटोवॉल्कनो शामिल हैं जिसने कुरिल ट्रेंच का भी निर्माण किया।<br>◆ जापान ने रूसी राष्ट्रपति की कुरिल द्वीप समूह की यात्रा का विरोध किया, जो विवादित द्वीपसमूह को लेकर जारी तनाव को दर्शाता है। |
| **हारा मैंग्रोव्स** | ◆ ये मैंग्रोव वन मुख्य रूप से फारस की खाड़ी में होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित केशम द्वीप के आसपास पाए जाते हैं।<br>◆ इनमें लवण सहन करने वाली एविसेनिया मरीना या ग्रे मैंग्रोव का प्रभुत्व है, जिसे स्थानीय रूप से हारा या हर्रा कहा जाता है।<br>◆ इस पारिस्थितिकी तंत्र को 1975 में रामसर आर्द्रभूमि और 1976 में यूनेस्को जैवमंडल अभ्यारण्य घोषित किया गया था।<br>◆ यह हॉक्सबिल एवं ग्रीन कछुओं, डालमेटियन पेलिकन व प्रवासी पक्षियों के लिए आवास प्रदान करता है।<br>◆ मैंग्रोव वन मत्स्य पालन, तटीय संरक्षण एवं स्थानीय आजीविका को भी सहारा देते हैं।<br>◆ फारस की खाड़ी में हुए समुद्री तेल रिसाव से ईरान का केशम द्वीप दूषित हो गया है, जिससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हारा मैंग्रोव वनों को खतरा पैदा हो गया है। |
| **बन्नी घास के मैदान** | ◆ बन्नी घास के मैदान गुजरात के कच्छ जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित हैं।<br>◆ इस भूभाग में कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य और छारी ढांड संरक्षण अभ्यारण्य शामिल हैं।<br>◆ यहाँ पर मालधारी, रबारी, जाट, मुतवा और मेघवाल सहित 22 जातीय समुदाय पाए जाते हैं।<br>◆ गुजरात ने कच्छ के बन्नी घास के मैदान में 20 काले हिरण छोड़े हैं ताकि वहाँ के मूल शाकाहारी जीव समुदाय को बहाल किया जा सके और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को मजबूत किया जा सके। |

LK ACADEMY
YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

## चर्चित व्यक्तित्व

### चंद्र शेखर आजाद (1906-1931)

#### संदर्भ



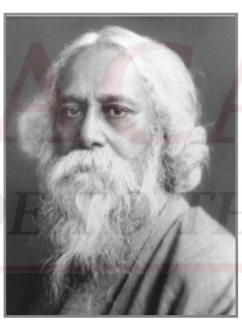
प्रधानमंत्री मोदी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्र शेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

#### चंद्र शेखर आजाद के बारे में

- आजाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 को वर्तमान मध्य प्रदेश के भावरा गाँव में हुआ था।
- 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने पर उन्होंने अपना नाम 'आजाद' घोषित किया, जिसका अर्थ है स्वतंत्र।
- उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल होकर राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर काम किया।
- उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सरकारी धन पर कब्जा करने के उद्देश्य से 9 अगस्त, 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती में भाग लिया था।
- भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के साथ मिलकर उन्होंने एचआरए को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के रूप में पुनर्गठित किया।
- लाला लाजपत राय की मौत के लिए जेम्स स्कॉट को निशाना बनाने वाले क्रांतिकारियों ने गलती से पुलिस अधिकारी जॉन पी. सॉन्डर्स को मार डाला।
- इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरे होने के दौरान 'आजाद' ने 27 फरवरी, 1931 को खुद को गोली मार ली।
- उनका जीवन साहस, नेतृत्व, राष्ट्रवाद, समानता एवं देशभक्ति का प्रतीक था।

### रबींद्रनाथ टैगोर (1861-1941)

#### संदर्भ



गृह मंत्री ने गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

#### रबींद्रनाथ टैगोर के बारे में

- कलकत्ता में जन्में टैगोर ब्रह्म समाज के नेता देबेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे बेटे थे और उन्होंने मुख्य रूप से घर पर ही शिक्षा प्राप्त की थी।
- उन्होंने मानसी, सोनार तरी और गीतांजलि : सॉन्ग ऑफरिंग्स सहित 50 से अधिक कविता संग्रह प्रकाशित किए।
- 1913 में गीतांजलि के लिए वे साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और गैर-यूरोपीय व्यक्ति बने।
- उन्होंने भारत के राष्ट्रगान 'जन गण मन' और बांग्लादेश के 'आमार सोनार बांग्ला' की रचना की।
- उन्होंने शांतिनिकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की, जो अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
- उन्हें 1915 में अंग्रेजों द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था, किंतु उन्होंने 1919 के जलियाँवाला बाग हत्याकांड के बाद इस सम्मान को त्याग दिया।
- उनका जीवन मानवतावाद, देशभक्ति, विचार की स्वतंत्रता, रचनात्मकता, शांति और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है।

## चर्चित प्रजातियाँ

### एलोग्राफ

#### संदर्भ

शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में एलोग्राफ जीनस से संबंधित लाइकेन बनाने वाले कवक की पाँच नई प्रजातियों की पहचान की है।

#### एलोग्राफ के बारे में

- एलोग्राफा (Allographa), ग्राफिडेसी (Graphidaceae) कुल से संबंधित लंबे फ्रूटिंग बॉडी वाले स्क्रिप्ट लाइकेन का एक वंश है।
- इसमें 200 से अधिक प्रजातियाँ शामिल हैं किंतु भारत में, विशेष रूप से पश्चिमी घाट में, इसकी दर्ज विविधता सीमित बनी हुई है।
- ये लाइकेन प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावास में व्यवधान के प्रति संवेदनशील होते हैं जिससे ये पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के विश्वसनीय संकेतक बन जाते हैं।
- पहचानी गई प्रजातियों में A. keralensis, A. paraconsanguinea, A. persistinspersa और A. semicarbonisata शामिल हैं।

#### लाइकेन के बारे में

- लाइकेन ऐसे संयुक्त जीव हैं जो कवक और फोटोबायोंट (प्रायः शैवाल या साइनोबैक्टीरिया) के बीच सहजीवन से बनते हैं।
- कवक संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है जबकि फोटोबायोंट प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन का उत्पादन करता है।
- लाइकेन प्राकृतिक जैव संकेतक के रूप में मृदा निर्माण, कीट खाद्य शृंखलाओं और प्रदूषण निगरानी में सहायक होते हैं।

### व्हाइट-बिल्ड हेरॉन

#### संदर्भ

अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी पर प्रस्तावित 1,200 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना गंभीर रूप से लुप्तप्राय व्हाइट-बिल्ड हेरॉन के आवास को खतरे में डालती है।



## व्हाइट-बिल्ड हेरॉन के बारे में

- व्हाइट-बिल्ड हेरॉन (Ardea insignis) को इम्पीरियल हेरॉन भी कहा जाता है जो कि Ardeidae कुल से संबंधित है।
- यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बगुला है, जिसकी ऊँचाई लगभग चार फीट तक होती है, और यह बेहद मायावी होता है।
- यह लगभग 1,500 मीटर की ऊँचाई तक, परिपक्व नदीतटीय जंगलों से घिरे, अबाधित, तेज बहने वाली पूर्वी हिमालयी नदियों में निवास करता है।
- यह मुख्य रूप से उथले जलधाराओं में मछलियाँ पकड़ता है, जिससे यह बांधों, प्रवाह में परिवर्तन व पानी में बढ़ते गंदलापन के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
- इसकी लचीली गर्दन, दांतेदार चोंच, सुगठित शरीर, छोटे पैर और फैली हुई उंगलियां उफनती व वेगवती नदियों के अनुकूल हैं।
- यह ज्यादातर एकाकी रहता है, नदी किनारे के ऊँचे पेड़ों में घोंसला बनाता है और भोर एवं शाम के समय गहरी कर्कश आवाजें निकालता है।
- भूटान, भारत, म्यांमार, चीन और बांग्लादेश में लगभग 165,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए इस समुदाय के 60 से भी कम जीवित बगुले बचे हैं।
  - भूटान में वैश्विक आबादी का लगभग 45% हिस्सा और 3-5 प्रजनन युगल मौजूद हैं; यह नेपाल और संभवतः बांग्लादेश में यह विलुप्त हो चुका है।
- भारत में ऐसे केवल 6-9 बगुले हैं, जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के लोहित, अंजॉ और चांगलांग जिलों में पाए जाते हैं।
- ये नामदफा और कामलांग टाइगर रिजर्व के आसपास और नोआ-देहिंग, लाहम एवं लोहित नदियों के किनारे पाए जाते हैं।
- लाहम नदी बेसिन भारत की लगभग 70% आबादी का भरण-पोषण करता है जबकि वालॉन्ग छावनी एक प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है।
- यह आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अतिसंकट ग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित है।

# पिग्मी हॉग

## संदर्भ

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आने वाली गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में पिग्मी हॉग को शामिल करने की सिफारिश की है।



## पिग्मी हॉग के बारे में

- पिग्मी हॉग दुनिया का सबसे छोटा एवं दुर्लभ जंगली सुअर है और पोरकुला जीनस की एकमात्र प्रजाति है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और CITES के परिशिष्ट I के अंतर्गत संरक्षित किया गया है।
- इसका प्राकृतिक आवास उप-हिमालयी तराई-दुआ क्षेत्र के ऊँचे जलोढ़ घास के मैदानों से मिलकर बना है।
- इसकी जंगली आबादी मुख्य रूप से असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है।
- ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में इनकी आबादी को पुनःस्थापित किया गया है।
- यह छोटे पारिवारिक समूहों में रहता है और जमीन पर घास से बने विशिष्ट घोंसले बनाता है।

# लेपिडोप्टेरा

## संदर्भ



भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने 12 वर्षों से अधिक के शोध के बाद भारत में तितलियों और पतंगों की पहली व्यापक सूची तैयार की।

## लेपिडोप्टेरा के बारे में

- यह सूची क्षेत्र सर्वेक्षणों, संग्रहालय के संग्रहों और वैज्ञानिक साहित्य के माध्यम से सदियों पुरानी वर्गीकरण संबंधी कमियों को दूर करती है।

- इसमें 22 खंड शामिल हैं जिसका अंतिम खंड अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका जूटैक्सा में प्रकाशित हुआ था। अंतिम खंड में शेष 1,689 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया था।
- भारत में तितलियों और पतंगों की 13,703 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो वैश्विक स्तर पर ज्ञात तितली और पतंगों की विविधता का लगभग 8.25% प्रतिनिधित्व करती हैं।
  - भारत में जियोमेट्रोइडिया पतंगों की 2,205 प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं जो उनकी वैश्विक विविधता का लगभग 8.8% है।
  - जियोमेट्रिडे कुल में 2,100 प्रजातियाँ हैं, उसके बाद यूरानिडे कुल में 95, एपिकोपीडे कुल में नौ और स्यूडोबिस्टोनिडे कुल में एक प्रजाति है।
  - सेमाटुरिडे कुल भारत में नहीं पाया जाता है।
- तितलियाँ और पतंगे परागणकर्ता, शाकाहारी और अपघटक के रूप में कार्य करते हैं और पक्षियों, चमगादड़ों और अन्य कीटभक्षी जीवों का समर्थन करते हैं।

## क्लाउडेड लेपर्ड

### संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस (4 अगस्त) के अवसर पर भारत ने नवगठित क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना के माध्यम से संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।



### क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में

- मुख्य भूमि पर पाए जाने वाले क्लाउडेड लेपर्ड को वैज्ञानिक रूप से नियोफेलिस नेबुलोसा के नाम से जाना जाता है।
  - सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड (Neofelis diardi) एक अलग प्रजाति है जो केवल सुमात्रा और बोर्नियो में ही पाई जाती है।
- इसका वैश्विक वितरण क्षेत्र हिमालय की तलहटी, दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिणी चीन तक फैला हुआ है।
- भारत में यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में निवास करता है।
- इसका आवास क्षेत्र लगभग 6,000-9,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित मैंग्रोव दलदल से लेकर हिमालयी जंगलों तक फैला हुआ है।
- यह बड़ी बिल्लियों के उपपरिवार पैंथेरिना का सबसे छोटा सदस्य है जिसका वजन लगभग 11-20 किलोग्राम होता है।
- इसकी हायोइड हड्डी की संरचना इसे छोटी बिल्लियों की तरह गुर्राने में सक्षम बनाती है किंतु इसे दहाड़ने से रोकती है।
- यह बाघों और सामान्य तेंदुओं के आसपास निशाचर और वृक्षवासी हो जाता है किंतु उनकी अनुपस्थिति में दिन के उजाले में अधिक सक्रिय रहता है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह साइट्स के परिशिष्ट I और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध है।
- यह मेघालय का आधिकारिक राजकीय पशु है।
- त्रिपुरा का क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, जो सिपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है, भारत का पहला समर्पित पार्क है जो विशेष रूप से इस प्रजाति के लिए बनाया गया है।
- यह मानस, डम्पा और पक्के टाइगर रिजर्व में भी पाया जाता है।

## एशियाई जंगली जल भैंस

### संदर्भ



छत्तीसगढ़ सरकार जंगली भैंसों की घटती संख्या को पुनर्जीवित करने के लिए असम से उन्हें स्थानांतरित करने की योजना बना रही है।

### एशियाई जंगली जल भैंस के बारे में

- एशियाई जंगली जल भैंस (बुबालस आर्नी) भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एवं कंबोडिया में पाई जाती है।
- भारत वैश्विक आबादी के 90% से अधिक हिस्से का मेजबान है जिसकी अनुमानित संख्या 3,500-3,700 है।
- असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इनकी अधिकांश आबादी पाई जाती है जबकि मेघालय, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र में इनकी छोटी आबादी पाई जाती है।
- यह खुले घास के मैदानों, जलोढ़ मैदानों और दलदलों में निवास करता है। अत्यधिक गर्मी या भारी वर्षा के दौरान यह आश्रय के लिए जंगलों का उपयोग कर सकता है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और CITES के परिशिष्ट III के अंतर्गत संरक्षित किया गया है।

YOUR GATEWAY TO THE NEXT MILESTONE

## स्लेंडर-बिल्ड वल्चर

### संदर्भ

असम में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) के संरक्षण केंद्र से पाँच कैप्टिव-ब्रेड स्लेंडर-बिल्ड वल्चर को जंगल में छोड़ दिया गया।



### स्लेंडर-बिल्ड वल्चर के बारे में

- स्लेंडर-बिल्ड वल्चर (Gyps tenuirostris) एक प्राचीन विश्व का गिद्ध है जो उप-हिमालयी क्षेत्र की मूल प्रजाति है।
- यह आर्द्रभूमि, वन क्षेत्रों और खुले ग्रामीण इलाकों में निवास करता है, लेकिन आमतौर पर मानव बस्तियों के पास के क्षेत्रों से बचता है।
- भारत में यह गंगा के मैदानी इलाकों में पाया जाता है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी ओडिशा और असम तक फैला हुआ है।
  - भारत के बाहर यह बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार एवं कंबोडिया में पाया जाता है।
- इसकी गर्दन लंबी और पतली होती है निचले हिस्से हल्के रंग के होते हैं और इसकी चोंच गहरे रंग की व संकीर्ण होती है जो इसकी एक विशिष्ट विशेषता है।
- यह मृत जानवरों का मांस खाता है, शवों के पास इकट्ठा होता है और भोजन का पता लगाने के लिए कुशल ग्लाइडिंग उड़ान भरता है।
- डिक्लोफेनाक और अन्य गैर-स्टेरॉयडल सूजनरोधी दवाओं से युक्त पशुओं के शवों का सेवन करने के बाद इसकी आबादी में मुख्य रूप से गिरावट आई।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा अतिसंकट ग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है।

## ब्लैक-नेक्ड क्रेन

### संदर्भ

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) ने अल्पाइन आर्द्रभूमि में सारस के घोंसलों और चूजों की सुरक्षा के लिए लद्दाख में 2,950 से अधिक आवारा कुत्तों की नसबंदी की।



### ब्लैक-नेक्ड क्रेन के बारे में

- ब्लैक-नेक्ड क्रेन (ग्रस निग्रिकोलिस) एक मध्यम आकार की सारस है जो उच्च ऊँचाई वाले आर्द्रभूमि क्षेत्रों के अनुकूल होती है।
- लद्दाख में इसे स्थानीय रूप से 'चा थुंग-थुंग' और अरुणाचल प्रदेश में 'थुंगडुंग कर्मा' कहा जाता है।
- इसका शरीर सफेद-भूरे रंग का, सिर एवं गर्दन का ऊपरी हिस्सा काला, आँखों के ऊपर लाल धब्बे और पानी में चलने के लिए लंबे पैर होते हैं।
- यह तिब्बती पठार, सिचुआन और पूर्वी लद्दाख में स्थित उच्च ऊँचाई वाले दलदलों एवं झीलों में निवास करता है।
  - अरुणाचल प्रदेश की सांगती और जिमिथंग घाटियों में सर्दियों में इनकी छोटी आबादी पाई जाती है।
- इसका आहार सर्वाहारी होता है जिसमें सेज कंद, पौधों की जड़ें, केंचुए, कीड़े, अकशेरुकी जीव और मेंढक शामिल होते हैं।
- यह 2,600-4,900 मीटर की ऊँचाई पर प्रजनन करता है और धीरे-धीरे ढलान वाले आर्द्रभूमि में घास व सेज के साथ घोंसला बनाता है।
- प्रमुख प्रजनन क्षेत्रों में चांगथांग शीत रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य, विशेष रूप से हानले, त्सो कर, न्योमा और आसपास के दलदली क्षेत्र शामिल हैं।
- लद्दाख की बौद्ध संस्कृति में इसे शांति, पवित्रता और सौभाग्य के पवित्र प्रतीक के रूप में माना जाता है।

DRISHTI IAS
YOUR GUIDE TO THE CIVIL SERVICES

## ब्लैकबक

### संदर्भ

गुजरात ने कच्छ के बन्नी घास के मैदान में 20 काले हिरण छोड़े ताकि वहां के मूल शाकाहारी जीव समुदाय और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बहाल किया जा सके।



### ब्लैकबक के बारे में

- ब्लैकबक भारत और नेपाल में पाया जाने वाला एक तेज रफ्तार वाला, मध्यम आकार का, दिन में सक्रिय रहने वाला मृग है।
- यह खुले घास के मैदानों, शुष्क झाड़ीदार क्षेत्रों और विरल वन क्षेत्रों में निवास करता है।
- भारत में यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है।
- यह पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा 'संकट मुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और CITES के परिशिष्ट III के अंतर्गत संरक्षित किया गया है।

# चर्चित सैन्य अभ्यास

## ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस

### संदर्भ

भारतीय नौसेना ने कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 की मेजबानी की।

### ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस के बारे में

- यह एक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास है और भारत में आयोजित होने वाला सदर्न रेडीनेस का पहला संस्करण है।
- इसका संचालन भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाली संयुक्त कार्य बल 154 (CTF 154) के अंतर्गत किया जाता है।
- यह अभ्यास संयुक्त समुद्री बलों (CMF) के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है।
  - CMF 47 देशों की एक समुद्री साझेदारी है जो अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता एवं समृद्धि को बढ़ावा देती है।
- यह खुले समुद्र में अवैध गैर-राज्य अभिकर्ताओं का मुकाबला करके अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था को कायम रखता है।

## विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास

### संदर्भ

आठवाँ भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना विस्फोटक आयुध निपटान (EOD) अभ्यास दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि में आयोजित किया जाएगा।

### विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास के बारे में

- इस द्विपक्षीय अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जलमग्न बचाव कार्य, बम निरोधक और विस्फोटक सामग्री को निष्क्रिय करना है।
- यह 2005 से SALVEX बैनर के तहत आयोजित संयुक्त बचाव और EOD शृंखला से विकसित हुआ है।
- इस अभ्यास में भारतीय व अमेरिकी नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और EOD टीमें भाग लेती हैं।
- यह उनकी विशेषज्ञ इकाइयों के बीच परिचालन संबंधी अंतरसंचालनीयता, व्यावसायिक सहयोग और सामरिक समन्वय को मजबूत करता है।
- विषयवस्तु संबंधी चर्चाओं में आधुनिक ईओडी तकनीकें, परिचालन अवधारणाएँ और सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल हैं।

## अभ्यास मैत्री-XV

### संदर्भ

भारत-थाईलैंड के 15वें संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी सूरत थानी, थाईलैंड के लिए रवाना हुई।

### अभ्यास मैत्री-XV के बारे में

- मैत्री भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका उद्देश्य सहयोग, विश्वास और अंतर-संचालनीयता को मजबूत करना है।
- इसकी शुरुआत 2006 में थाई-भारतीय सहयोग फील्ड अभ्यास के रूप में हुई थी और 2013 में इसका नाम बदलकर मैत्री कर दिया गया, जिसका अर्थ 'मित्रता' है।
  - दोनों देशों द्वारा बारी-बारी से आयोजित होने वाला यह आयोजन 2019 के बाद पाँच साल के अंतराल के बाद 2024 में फिर से शुरू हुआ।
- कंपनी स्तर के इस अभ्यास में जंगल और अर्ध-शहरी इलाकों में उग्रवाद रोधी और आतंकवाद रोधी अभियान शामिल हैं।
- ये अभियान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं।
- प्रशिक्षण में मैदानी अभ्यास, युद्ध संबंधी चर्चाएँ, व्याख्यान, प्रदर्शन, संयुक्त योजना और सामरिक अभ्यास शामिल हैं।

❑❑❑

IKAGAMY YOUR GUIDE TO THE NEAR MILESTONE




LK ACADEMY

YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE